रेड स्टार

कम्युनिस्ट क्रांतिकारियों का मंच

भाकपा (माले) रेड स्टार का मुख पत्र

खण्ड - 24 | अंक - 1 | जनवरी 2023

वर्ष 2023 के आगमन पर आरएसएस नव-फासीवाद को परास्त करने के लिये अपने प्रयासों में तेजी लायें

आरएसएस मनुवादी हिन्दुत्व के खिलाफ अभियान

पार्टी दस्तावेज

राजनीतिक प्रस्ताव

WWW.REDSTARONLINE.COM

संपादकीय 4

राजनीतिक प्रस्ताव 6

आलेख 23

- एलिजाबेथ युगः ब्रिटिश साम्राज्य द्वारा विनाश गाथा
- जातिसूचक पदनाम/टाइटल त्यागना एक शुरुआत है
- ईरान में महसा अमीनी की शहादत
- आर्थिक आधार पर आरक्षण के निहितार्थ
- छत्तीसगढ़ डायरी

बहस 32

- हमारे मतभेद

गतिविधियाँ 40

मनुवादी हिंदुत्व के खिलाफ़ देशव्यापी अभियान 44

संपादक मंडल
विजय कुमार, उर्मिला, तेजराम विद्रोही, सौरा, वशिष्ठ, रितांश

संपादक : तुहिन

मुद्रक, प्रकाशक, स्वामी:
पीजे जेम्स
सी - 141
सैनिक नगर, नई दिल्ली - 110059
फ़ोन: 011-41056622 (ऑफिस), 9425560952
ईमेल: *redstarhindi@gmail.com, info@cpiml.in*
वेबसाइट: www.cpiml.in, redstaronline.in

FOLLOW US ON:

HTTPS://WWW.FACEBOOK.COM/CPIMLRS

HTTPS://TWITTER.COM/CPIMLREDSTAR

HTTPS://WWW.INSTAGRAM.COM/CPIMLREDSTAR/

भाकपा (माले) रेड स्टार की 12वीं कांग्रेस (महासम्मेलन) ने आरएसएस फासीवाद के खिलाफ पूरी तरह आक्रामक होने का आह्वान किया

24 से 29 सितंबर तक कोझिकोड केरल के शिवराम-शर्मिष्ठा हॉल (एसके पोट्टेकड़ हॉल) में आयोजित भाकपा (माले) रेड स्टार के 12वीं कांग्रेस का समापन आरएसएस के नव-फासीवाद का प्रतिरोध करने और उसे हराने के आह्वान के साथ हुआ। कांग्रेस में 16 राज्यों के लगभग 300 प्रतिनिधियों और पर्यवेक्षकों ने भाग लिया। गहन चर्चा के बाद अद्यतन पार्टी कार्यक्रम,क्रांति का पथ, संविधान में संशोधन, राजनीतिक संगठनात्मक रिपोर्ट और राजनीतिक प्रस्ताव पर कांग्रेस ने मुहर लगाया। कांग्रेस द्वारा सर्वसम्मति से चुने गए 34 सदस्यीय केंद्रीय समिति और 3 सदस्यीय केंद्रीय नियंत्रण आयोग ने कॉमरेड पीजे जेम्स को पार्टी के महासचिव और कॉमरेड साबी जोसेफ को केंद्रीय कंट्रोल कमीशन(नियंत्रण आयोग) के संयोजक के रूप में चुना।

पार्टी कांग्रेस ने दुनिया के सबसे बड़े और सबसे पुराने फासीवादी संगठन, आरएसएस के नव-फासीवाद के खिलाफ व्यापक फासीवाद-विरोधी मोर्चा बनाने के कार्य को तात्कालिक रूप से करने का फैसला किया। इस कार्य में सभी फासीवाद-विरोधी ताकतों के साथ शामिल होते हुए, पार्टी कांग्रेस ने नवउदार-कॉरपोरेटकरण के खिलाफ लड़ाई में मजदूर वर्ग और सभी उत्पीड़ितों की वैचारिक स्वतंत्रता को बनाए रखने के लिए कम्युनिस्टों के स्वतंत्र पहल के कर्तव्य को प्राथमिकता में रखने का भी फैसला किया। मनुस्मृति पर आधारित अमानवीय जाति व्यवस्था आरएसएस फासीवाद का वैचारिक आधार है, पार्टी कांग्रेस ने सर्वसम्मति से संकल्प लिया कि केंद्रीय समिति के सदस्य सभी जातिगत उपनामों/ पदवी को छोड़ देंगे। इसी तारतम्य में , कांग्रेस ने सभी प्रकार के लैंगिक भेदभाव को समाप्त करने और लैंगिक समानता की दिशा में आगे बढ़ने के लिए अडिग लड़ाई लड़ाई लड़ने का भी आह्वान किया।

धार्मिक-सांप्रदायिक संगठनों पर सीपीआई (एमएल) रेड स्टार की स्थिति स्पष्ट है। कांग्रेस ने मुस्लिम संगठनों को चुनिंदा रूप से लक्षित और प्रतिबंधित करने के मोदी शासन के जारी कदम की कड़ी निंदा की है, जो आरएसएस के सांस्कृतिक राष्ट्रवाद के अनुरूप है,

जो मुसलमानों की पहचान अपने दुश्मन नंबर एक के रूप में बहुत शुरुआत से करते आई है। पार्टी कांग्रेस ने प्रकृति पर लगातार बढ़ते कॉर्पोरेट अतिक्रमण का प्रतिरोध करने के अत्यधिक महत्व पर भी जोर दिया, जो अब एक पर्यावरणीय तबाही की ओर ले जा रहा है जिससे सभी जीवित प्राणियों का अस्तित्व खतरे में पड़ गया है।

पार्टी संगठन के निर्माण के प्राथमिक कार्य के साथ, कांग्रेस ने देश में कम्युनिस्ट क्रांतिकारी संगठनों के बीच एकता बनाने के लिए प्रयास को तेज करने का निर्णय लिया। आईकोर (क्रांतिकारी दलों और संगठनों का अंतरराष्ट्रीय मंच) के एक घटक होने के नाते, पार्टी ने आईकॉर के साम्राज्यवाद और नवफासीवाद के खिलाफ अंतरराष्ट्रीय स्तर पर एक साम्राज्यवाद-विरोधी, फासीवाद-विरोधी संयुक्त संयुक्त मोर्चा बनाने के प्रयासों को मजबूत करने का फैसला किया है।

पार्टी कांग्रेस ने जनता के लोकतंत्र और समाजवाद की ओर आगे बढ़ने के पार्टी के रणनीतिक कार्य को कॉर्पोरेट-भगवा फासीवादी शासन की धूरदक्षिणपंथी नवउदारवादी नीतियों का विरोध करने और उन्हें हराने के तत्काल कार्य के साथ एकीकृत करने का संकल्प लिया है, जिसके कारण समस्त संपदा का केंद्रीकरण एक तरफ तो अडानी-अंबानी जैसे बड़े कॉर्पोरेट्स के एक छोटे समूह के हाथों हो रहा है और दूसरी तरफ भारत को "पूर्ण" या "अत्यधिक" गरीबी के गढ़ में बदलने के साथ-साथ अभूतपूर्व बेरोजगारी और आसमान छूती मंहगाई की भीषण परिस्थिति पैदा की गई है।इसने आम लोगों के जीवन को दुभर कर दिया है।

भाकपा(माले) रेड स्टार उन सभी मेहनतकश , उत्पीड़ित जनता और प्रगतिशील जनवादी तबकों को अपनी क्रांतिकारी बधाई देता है जिन्होंने 12वीं पार्टी कांग्रेस को सफल बनाने के लिए तहेदिल से समर्थन किया।

आइए, वर्ष 2023 के आगमन पर आरएसएस नव-फासीवाद को परास्त करने के लिये अपने प्रयासों में तेजी लायें

नए साल की शुरूआत के साथ राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ (आरएसएस) जो दुनिया का सबसे बड़ा और सबसे लंबे समय तक चलने वाला फासीवादी संगठन है, ने अपने राजनीतिक उपकरण भाजपा के माध्यम से सम्पूर्ण भारत पर शिकंजा कसते हुये भारत को एक हिंदुराष्ट्र बनाने के अपने अंतिम लक्ष्य की ओर तेजी से बढ़ रहा है। मोदी सरकार ने एक तरफ घोर दक्षिणपंथी आर्थिक नीतियों को और अधिक दक्षिणपंथी मोड देते हुये सबसे भ्रष्ट क्रोनी पूंजीपतियों (चहेते पूँजीपतियों) के नेतृत्व में बेरोकटोक कारपोरेटीकरण को तेज़ किया है तो वहीं दूसरी ओर फासीवादी आरएसएस के वैचारिक आधार मनुवादी –हिंदुत्व को मजबूत किया है। नतीजतन, अडानी जैसे क्रोनी पूंजीपतियों का धन संग्रह अभूतपूर्व स्तर पर पहुँच गया है, जहाँ एक ओर वे महाअमीर बनते जा रहे हैं, वहीं भारत वैश्विक गरीबी का गढ़ बनता जा रहा है। बेरोजगारी, मूल्य-वृद्धि, अभाव में जिंदगी, भुखमरी आदि आम बात होती जा रही हैं। संसद को मूकदर्शक बना दिया गया है, सारे नीतिगत निर्णय कारपोरेट बोर्ड-रूम में लिए जाते हैं, यहाँ तक कि राज्य स्वयं अबाध कारपोरेटीकरण का सूत्रधार बन गया है। उद्योग और कृषि सहित सभी सार्वजनिक क्षेत्रों के उद्यमों को व्यवस्थित ढंग से समाप्त करने के कारण, कुल कार्यबल में संगठित श्रमिकों की हिस्सेदारी 3 प्रतिशत से भी कम रह गई है। जबकि 97 प्रतिशत से अधिक कार्यबल अनौपचारिक अथवा जीवन निर्वाह के न्यूनतम साधनों से भी वंचित असंगठित क्षेत्र में लगा हुआ है। यहाँ तक कि मजदूरों द्वारा लंबे और कठिन संघर्षों के बाद हासिल किये गये मज़दूर अधिकारों को व्यवस्थित ढंग से छीना जा रहा है।

इस धुर दक्षिणपंथी कार्पोरेटीकरण के एजेंडे के साथ-साथ आरएसएस और भाजपा मनुवादी-हिंदुत्व जोकि आरएसएस के नव-फासीवाद की विचारधारा है, को अधिक मजबूत करने के लिए तमाम तरीके अपना रही है। आर्थिक आरक्षण की आड़ में संभ्रांत सवर्णों को आरक्षण देने के लिये संविधान संशोधन कर संविधान के मूल ढांचे को भी ध्वस्त कर दिया गया है। यहां तक कि सर्वोच्च न्यायालय भी उत्पीड़ित जातियों के खिलाफ आरएसएस और भाजपा के इस ब्राह्मणवादी कदम के सामने नतमस्तक है।

अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग की बहुसंख्यक आबादी वाली उत्पीड़ित जातियों के खिलाफ इस मनुवादी हमले के साथ-साथ अल्पसंख्यकों के अलगाव की प्रक्रिया, विशेष रूप से मुसलमानों को बदनाम करने की आरएसएस की रणनीति तेज हो गई है। वे अल्पसंख्यकों, विशेषकर मुसलमानों को देश में दोयम दर्जे का नागरिक बनाने के अपने घिनौने प्रयास में लगे हुये हैं। भारतीय संविधान के धर्मनिरपेक्ष चरित्र के उलट मुस्लिम प्रवासियों को पूरी तरह से छोड़कर, गैर-मुस्लिम श्रेणी के सभी प्रवासियों के लिए भारतीय नागरिकता का मार्ग खोलकर पिछले दरवाजे से सीएए को लागू करने के हालिया कदम को, हिंदुराष्ट्र के एजेंडे के रूप में देखा जाना चाहिए। बेशक, समान नागरिक संहिता को लागू करने का प्रयास, एनआईए को मजबूत करने सहित राज्यों में इसके कार्यालयों की स्थापना, नागरिक और सैन्य क्षेत्रों सहित शिक्षा, न्यायपालिका और पूरे प्रशासन के भगवाकरण की निरंतरता को, आरएसएस का भारतीय समाज के समूचे बृहद और सूक्ष्म क्षेत्रों पर पूर्ण नियंत्रण को कायम करने कि दिशा में बढ़ते हुये कदम है।

हालहि आरएसएस के नव-फासीवादी शस्त्रागार के नए अस्त्र ईवीएम को आरवीएम (रिमोट वोटिंग मशीन) के रूप में आगे परिष्कृत और विस्तारित करना की योजना है, ताकि घरेलू प्रवासियों को दूरस्थ मतदान के माध्यम से अपने मताधिकार को प्रयोग करने में सक्षम बनाया जा सके। तकनीकी विशेषज्ञों द्वारा ईवीएम की सुरक्षा, सटीकता और विश्वसनीयता के बारे में उठाए गए कई संदेहों के कारण, तकनीकी रूप से उन्नत कई देशों ने चुनावों में ईवीएम के उपयोग पर पूर्णतः प्रतिबंध लगा दिया है। बाबजूद इसके सत्ता में आने के बाद मोदी सरकार फासीवादी तरीके से भारतीय चुनावों में ईवीएम के उपयोग को भारी पैमाने पर बढ़ा रही है। अब इसे प्रवासियों को मतदान में सक्षम करने की आड़ में आरवीएम के रूप में विस्तारित किया जा रहा है। इससे ईवीएम के संबंध में पहले से मौजूद आशंकाओं के साथ-साथ कई प्रक्रियात्मक, प्रशासनिक और तकनीकी बाधाएं उत्पन्न होने वाली हैं। ईवीएम से जुड़े संदेहों के मद्देनजर चुनाव आयोग पहले भी तकनीकी और व्यावहारिक समस्याओं का सही जबाब नहीं दे पाया है। लेकिन भारतीय राजसत्ता पर आरएसएस के साथ-साथ जनता के बीच भारी पकड़ रखने वाले भगवा गुंडों का प्रभाव देखते हुए, मोदी सरकार ने अचानक आरवीएम की घोषणा कर दी है। ईवीएम/आरवीएम में हेरफेर की कई संभावनाओं को नजरंदाज नहीं किया जा सकता है। इसलिए सभी प्रगतिशील-लोकतांत्रिक ताकतों सहित गैर-फासीवादी ताकतों को मिलकर आरएसएस के नवफासीवादी हमले को परास्त करने के लिये तात्कालिक कार्यभार के हिस्से के रूप में आरवीएम का मज़बूती से विरोध करना चाहिए।

हालहि के विधानसभा और उपचुनाव के परिणामों का करीबी विश्लेषण, स्पष्ट रूप से राज्यों में मुस्लिम अल्पसंख्यकों के खिलाफ और हिंदुत्व के पक्ष में ध्रुवीकरण की ओर इशारा करता है। आरएसएस/बीजेपी केंद्र की दमनकारी राजकीय शक्ति का उपयोग करते हुए, सबसे भ्रष्ट कॉर्पोरेट अरबपतियों एवं भगवा मीडिया के समर्थन से आगामी विधानसभा चुनावों के आधार पर 2024 के आम चुनावों को जीतने के लिये खुद को तैयार कर रहे है। इस तैयारी का एक ही मकसद है कि भारत को एक बहुसंख्यकवादी हिंदु राष्ट्र बनाना जिसका वैचारिक आधार मनुस्मृति है, जिसे आरएसएस ने नवंबर 1949 में ही भारत के संविधान के रूप में पेश किए जाने पर ज़ोर दिया था। इसमें कोई संदेह नहीं है कि आने वाले दिनों में फासीवादी ताक़तें हिंदुत्ववादी राष्ट्रवाद को भड़का कर घृणित चालों की एक श्रृंखला का सहारा लेंगी, जो सार रूप से राष्ट्रविरोधी होगा। धर्म के आधार पर लोगों के बीच नफरत और संदेह फैलाकर विभाजनकारी ताकतों को मजबूत करेगा। विविधता और मेलजोल की संस्कृति को तहस नहस करते हुये सांप्रदायिक ध्रुवीकरण को मज़बूत करेगा परिणामस्वरूप आगामी चुनावों में आरएसएस/ भाजपा को चुनावों में लाभ मिलेगा।

मौजूदा गंभीर परिस्थितियां वामपंथी, प्रगतिशील और जनवादी ताकतों की ओर से ठोस मूल्यांकन और केन्द्रित हस्तक्षेप की मांग करती है। आने वाले समय में मनुवादी-हिंदुत्व के अनुरूप आरएसएस के गुंडों द्वारा अल्पसंख्यकों खासकर मुसलमानों और दलितों के खिलाफ तीव्र हिंसा और नफ़रत का वातावरण निर्मित किया जाएगा। ऐसे में दलितों, आदिवासियों, महिलाओं और अल्पसंख्यकों सहित सभी उत्पीड़ितों और मेहनतकश जनता के साथ खड़ी सभी जनवादी ताक़तों को व्यापक पहलकदमी लेने की आवश्यकता है। यह समय व्यापक हस्तक्षेप के लिए दो स्तरों पर पहल की मांग करता है। पहला कि नवउदारवादी कार्पोरेटीकरण तथा इसके सभी प्रभावों और भारतीय फासीवाद के वैचारिक आधार मनुवादी-हिंदुत्व के खिलाफ एक आम कार्यक्रम के आधार पर, वाम – जनवादी ताकतों को एक राजनीतिक कोर बनाना चाहिए। इस आधार पर सभी राज्यों में ठोस परिस्थितियों के अनुरूप कारपोरेट-भगवा-फासीवादी ताकतों के खिलाफ निरंतर और समझौताहीन संघर्षों को विकसित किया जाना चाहिए। इस प्रक्रिया में फ़ासीवादी कार्पोरेटी हमलों के खिलाफ मेहनतकश जनता, विशेष रूप से विशाल असंगठित और अनौपचारिक क्षेत्र से जुड़े मेहनतकश, .

जो भारतीय मजदूर वर्ग के 95 प्रतिशत से अधिक हिस्से का प्रतिनिधित्व करते है, को लामबंद करना तथा किसानों, महिलाओं, दलितों, आदिवासियों, अल्पसंख्यकों सहित उत्पीड़ित जनता, विशेष रूप से उत्पीड़ित मुस्लिम, युवाओं, छात्रों को कारपोरेट हमलों के खिलाफ एकताबद्ध करने की आवश्यकता है। हमें कथित विकास के नाम पर बड़े पैमाने पर हो रहे विस्थापन, पर्यावरण विनाश के खिलाफ संघर्ष तेज़ करते हुये जातिगत और सांप्रदायिक उत्पीड़न तथा लोकतांत्रिक अधिकारों के हनन आदि के खिलाफ लामबंद होना होगा। साझा कार्यक्रम के आधार पर राज्य-स्तरीय पहलों और हस्तक्षेपों से उभरने वाला क्रांतिकारी वामपंथी, जनवादी और संघर्षशील ताकतों का नेतृत्व, कॉर्पोरेट-हिंदुत्व फासीवाद के खिलाफ एक राष्ट्रीय समन्वय की परिस्थिति उत्पन्न कर सकता है।

दूसरा एक संयुक्त मोर्चा बनाने का कार्यभार है। इसके लिए राज्यों में ठोस परिस्थितियों के अनुरूप फासीवाद-विरोधी, जाति-विरोधी और धर्मनिरपेक्ष ताकतों के साथ गठबंधन की संभावना को तलाशा जाय जिसे ठोस परिस्थितियों के आधार पर चुनावी संघर्षों तक ले जाया जा सके। इस आधार पर 2023 के विधानसभा चुनाव में जहां भी संभव हो भाग लेने का प्रयास किया जाना चाहिए तथा इसके अनुभवों का उपयोग करते हुए, प्रतिक्रियावादी दलों और फासीवादियों को अलग-थलग करने के लिए, शासक वर्गीय दलों के बीच के अंतर्विरोधों का इस्तेमाल करते हुए एक व्यापक फासीवाद-विरोधी आंदोलन का निर्माण करने की आवश्यकता है। यह प्रक्रिया 2024 के आम चुनाव में, आरएसएस का नव-फासीवाद जो आज की सबसे बड़ी चुनौती है, को परास्त करने के लिए सभी गैर-फासीवादी शासक वर्गीय दलों को एकजुट होने के लिए ठोस आधार तैयार करेगी। नए साल में प्रवेश करते समय, क्रांतिकारी, वामपंथी और जनवादी ताकतों के लिए इन दिशा में सोचने और कार्यवाहियों को अंजाम देने का यह सही समय है।

यह राजनीतिक प्रस्ताव सीपीआई (एमएल) रेड स्टार की 12 वीं काँग्रेस में अनुमोदित किया गया।

1. भूमिका

1.1 : हमारी पार्टी की 12 वीं कांग्रेस ऐसे समय में आयोजित की गई है जब 2018 में 11 वीं कांग्रेस के बाद से विश्व साम्राज्यवादी व्यवस्था के तीव्र होते संकट सहित समग्र वैश्विक और राष्ट्रीय राजनीतिक क्षेत्र में व्यापक बदलाव हुए हैं। इस संकट के बोझ को श्रमिक वर्ग और उत्पीड़ित लोगों के कंधों पर स्थानांतरित करने के शासक वर्ग के प्रयास को भी नए आयाम मिले हैं। यह साम्राज्यवादी विश्व व्यवस्था में सभी अंतर्निहित अंतर्विरोधों को तेज कर रहा है, जिससे नव-फासीवाद के प्रति सामान्य वैश्विक प्रवृत्ति को जन्म दिया गया है। हमारे देश में भी, 11 वीं कांग्रेस के बाद, विशेष रूप से 2019 में मोदी 2 के बाद से, कॉरपोरेट- भगवा फासीवाद ने अपने बहुआयामी आक्रामकता के साथ मनुवाद की कट्टर प्रतिक्रियावादी विचारधारा द्वारा समर्थित एक पागल गति से आगे बढ़ रहा है। इसलिए 12 वीं पार्टी कांग्रेस के लिए राजनीतिक प्रस्ताव को उचित परिप्रेक्ष्य में गढ़ने के लिए पिछले चार वर्षों में,अंतरराष्ट्रीय और भारत दोनों में आए प्रमुख बदलावों का ठोस मूल्यांकन करने की जरूरत है।

2. अंतर्राष्ट्रीय स्थिति

2.1 : 2020 की शुरुआत से पूरी दुनिया को तबाह करने वाली कोविद महामारी जिसने पूरे राजनीतिक-आर्थिक नींव को महीनों तक जमाए रखा, वह एक ऐतिहासिक मोड़ रहा है। यहां तक कि उत्पादन, व्यापार, परिवहन और खपत पूरे वैश्विक आपूर्ति-मांग श्रृंखलाओं में एक पड़ाव के साथ ढह गए, डिजिटलीकरण जैसी तेजी से उभरती हुई सीमांत तकनीकों का उपयोग करते हुए, शासक वर्गों ने हर जगह महामारी का इस्तेमाल किया। शासक वर्गों ने प्रकृति की लूट सहित धन संपदा हस्तगत करने के भयावह स्तरों को बनाने के लिए एक अवसर के रूप में महामारी का इस्तेमाल किया और श्रमिक वर्ग और उत्पीड़ित लोगों को हर जगह और अधिक बेरोजगारी के लिए हर जगह और अधिक उत्पीड़ित होने के लिए प्रताड़ित किया। यहां तक कि विश्व आर्थिक विकास दर नकारात्मक हो गई, वैश्विक अरबपतियों की संख्या और उनके हाथ धन की एकाग्रता अभूतपूर्व हो गई है। धुर दक्षिणपंथी नवउदारवादी नीतियों के एक सहवर्ती के रूप में नव-फासीवाद, नस्लीय, जातीय और धार्मिक अल्पसंख्यकों, प्रवासियों, शरणार्थियों और हाशिए पर रहने वाले लोगों और उत्पीड़ित वर्गों के प्रति अत्यधिक परायेपन की घृणा द्वारा कई देशों में ताकत इकट्ठा कर रहा है।

2.3 : इसने नवउदारवादी काल में साम्राज्यवाद के सभी अंतर्निहित संकटों और अंतर्विरोधों को तीव्र कर दिया है।

जबकि अमेरिका सहित अन्य सभी साम्राज्यवादी शक्तियों को पूर्ण गिरावट या नकारात्मक वृद्धि का सामना करना पड़ा, सामाजिक साम्राज्यवादी चीन सकारात्मक क्षेत्र में विकास दर के साथ एकमात्र देश के रूप में बना रहा, हालांकि कम दर पर। महामारी के दिनों के दौरान, न केवल एफ्रो-एशियाई-लैटिन अमेरिकी देशों, बल्कि यहां तक कि पश्चिमी शक्तियों को भी बुरी तरह से आवश्यक चिकित्सा आपूर्ति के लिए चीन पर निर्भर रहना पड़ा। यद्यपि अमेरिका अभी भी दुनिया की सबसे बड़ी सैन्य मशीन के रूप में बना हुआ है, चीन जो जैव प्रौद्योगिकी, रोबोटाइजेशन, ईकॉमर्स, डिजिटलीकरण, आदि सहित तेजी से आगे बढ़ने वाली तकनीकों के कई क्षेत्रों में आगे है, विशेष रूप से अपने बीआरआई-(बेल्ट और सड़क पहल) के माध्यम से - राजनीतिक-आर्थिक क्षेत्रों में अमेरिकी साम्राज्यवाद को प्रभावी ढंग से चुनौती देने के लिए पूंजी के अधिक गहन निर्यात में लगा हुआ है।

2.3 । शंघाई सहयोग संगठन, ब्रिक्स, आरसीईपी, आदि में अपनी अग्रणी भूमिका को जारी रखने में, चीन ने अपने प्रभाव क्षेत्र और राजनीतिक-आर्थिक दबदबे को न केवल एशिया में बल्कि अफ्रीका में और यहां तक कि दूरदराज के लैटिन अमेरिका में कायम रखा है और यहां तक कि कई गरीब देश पहले से ही चीन पर निर्भर हो गए हैं। दक्षिण एशिया में श्रीलंका और नेपाल, अफ्रीका में सूडान आदि से रिपोर्ट की गई नवउदारवादी राजनीतिक-आर्थिक संकटों की नई लहर भी इन देशों में चीनी पैठ के विशिष्ट चरित्र से संबंधित हैं। रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण दक्षिण प्रशांत में सोलोमन द्वीप के साथ चीन का हालिया सुरक्षा समझौता अमेरिकी साम्राज्यवाद के लिए एक और झटका है। चीन नाटो के सदस्यों के साथ भी द्विपक्षीय आर्थिक संबंधों में प्रवेश करने की प्रक्रिया में है। उदाहरण के लिए, इटली जिसे महामारी के शुरुआती दिनों में चीन पर निर्भर रहना था, पहले से ही अपने सदस्य के रूप में BRI में शामिल हो गया है। इसी तर्ज पर, ईरान में अपनी दीर्घकालिक रणनीतिक भूमिका के साथ, हाल ही में चीन ने सऊदी के साथ एक सौदा किया है, जो कि पश्चिम एशिया में ईरान के कट्टर प्रतिद्वंद्वी के रूप में है। चीन ने सऊदी अरब के साथ युआन(चीनी मुद्रा) में पेट्रोलियम उत्पादों के आयात के लिए संधि की है। चीन द्वारा केंद्रीय बैंक डिजिटल मुद्रा (CBDC),.....

डिजिटल युआन को डिजाइन करने के लिए नवीनतम प्रयास और इसे अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा के रूप में प्रोजेक्ट करना युद्ध के बाद के अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक और वित्तीय संबंधों में अमेरिकी प्रभुत्व की स्थिति के लिए एक गंभीर चुनौती है। देशों द्वारा अपने तेल के आयात के लिए रूबल भुगतान के लिए हाल ही में रूसी आग्रह भी डॉलर की वैश्विक स्थिति के लिए एक झटका है।

2.4 : इसने अमेरिकी साम्राज्यवाद और सामाजिक साम्राज्यवादी चीन के बीच अंतर्विरोध को पहले से कहीं अधिक तेज कर दिया है। अफगानिस्तान से अपनी वापसी के तुरंत बाद, जिसके बाद चीन वहां एक रणनीतिक खिलाड़ी के रूप में उभरा, अमेरिकी साम्राज्यवाद ने AUKUS औकस की शुरुआत की है - एक परमाणु-आधारित एंग्लो-सैक्सन सैन्य गठबंधन, जो ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड और अमेरिका से बना है, जो एशिया-प्रशांत और पूर्व और दक्षिण चीन सागर में ,ताइवान जिसका केंद्रबिंदु है चीन के खिलाफ अपने उकसाने वाली हस्तक्षेपों को तेज करता है। इस परमाणु-सैन्य समझौते पर हस्ताक्षर करने में, इसने फ्रांस सहित नाटो के सदस्यों को अंधेरे में रखा, जबकि फ्रांस का पहले से ही ऑस्ट्रेलिया के साथ एक पनडुब्बी सौदा हुआ है , जिसके कारण फ्रांस ने तुरंत वाशिंगटन से अपने राजदूत को वापस ले लिया। हालांकि इस मुद्दे को अस्थायी रूप से सुलझा लिया गया है, लेकिन इसने नाटो में निहित कमजोरी को उजागर किया। अमेरिकी साम्राज्यवाद के साथ पूर्व के करीबी एकीकरण के बाद ब्रेक्सिट के माध्यम से यूरोपीय संघ से ब्रिटेन के अलग होने के बाद, यूरोपीय संघ की अग्रणी शक्तियों ने अमेरिकी नेतृत्व वाले नाटो से स्वतंत्र एक यूरोपीय सेना के गठन के लिए गंभीर होमवर्क शुरू कर दिया है।

2.5 : साम्राज्यवादी रूस द्वारा यूक्रेन पर हाल ही में हमला हालांकि निंदनीय रूप से अपनी सदस्यता को और बढ़ाकर 30-सदस्यीय नाटो को फिर से मजबूत करने के अमेरिकी प्रयासों के साथ जुड़ा हुआ है। जब 1991 में सोवियत संघ के विघटन के साथ शीत युद्ध समाप्त हुआ, नाटो की सदस्यता 16 थी, और जब नाटो का उद्घाटन 1949 में ट्रूमैन द्वारा किया गया था, जो शीत युद्ध का नेतृत्व करने के लिए महत्वपूर्ण सैन्य संस्थान के रूप में था, इसकी सदस्यता केवल 12 थी। जैसा कि स्पष्ट है, यूक्रेन पर रूसी हमला, यूक्रेन के नव नाज़ी शासकों को नाटो की सदस्यता ग्रहण करने पर मजबूर किये जाने, जो कि रूस की सीमाओं से लगे देशों के सैन्यकरण की अमरीकी साजिश की उपज थी। अब यूक्रेन अमेरिका के नेतृत्व वाले नाटो बलों के हाथों में एक मोहरे की तरह है। और जो चल रहा है वह एक अंतर-साम्राज्यवादी संघर्ष है,जहां एक तरफ अमरीका नीत नाटो गठबंधन है और दूसरी तरफ रूस। जहां यूक्रेन की स्थिति मात्र एक प्यादे से ज्यादा कुछ नहीं है। यूक्रेन युद्ध, जबकि दुनिया के अग्रणी हथियारों के निर्माताओं विशेष रूप से जो अमरीका के हैं, तिजोरियों में अधिक धन प्रवाह की सुविधा प्रदान करता है। खासकर तीन सबसे बड़े कृषि-बहुराष्ट्रीय कंपनियों कारगिल, मोनसेंटो और ड्यूपॉन्ट, जो पहले से ही यूक्रेन में लगभग 17 लाख हेक्टेयर की अत्यधिक उपजाऊ भूमि खरीद चुके हैं। यह संकटग्रस्त वित्त पूंजी के लिए एक और अवसर है, जो अपने संकट के बोझ को दुनिया के मेहनतकश और उत्पीड़ित जनता के कंधों पर डाल रहे हैं। जबकि ईंधन, भोजन और जीविका की अन्य आवश्यक वस्तुओं की कीमतों में वृद्धि आम जनता की कमर तोड रही है।

2.6 : यूक्रेन पर रूसी हमले और बिना किसी रुकावट के जारी युद्ध ने वैश्विक महत्व के दूरगामी नतीजों को जन्म दिया है। इसने एक ओर अमेरिका और उसके सहयोगियों तथा दूसरी ओर चीन व रूस के बीच अंतर-साम्राज्यवादी अंतर्विरोधों को और तेज कर दिया है । चीन के खिलाफ निर्देशित एशिया-प्रशांत में बढ़ते अमेरिकी फोकस के प्रत्यक्ष परिणाम के रूप में, चीन ने "वैश्विक सुरक्षा पहल" के लिए पहल की है, विशेष रूप से उसने औकस संधि को अपना निशाना बनाया है। AUKUS संधि के आधार पर अमेरिका एक "एशियाई नाटो" बनाने की परिकल्पना कर रहा है। यूएस हाउस ऑफ स्पीकर नैन्सी पेलोसी की ताइवान की यात्रा के बाद चीन के सैन्य अभ्यासों ने ताइवान और आसपास के क्षेत्रों को बदले की कारवाई में घेर लिया और इसके बाद दक्षिण चीन सागर में अमरीकी सातवें बेड़े की तैनाती के बाद चीन-अमेरिका के तनाव को और बढ़ा दिया। "ताइवान प्रश्न" को हल करके "चीनी एकीकरण को पूरा करने" के लिए "कठोर और अडिग दृष्टिकोण" की घोषणा करने वाली चीनी कम्युनिस्ट पार्टी (सीपीसी) की 20वीं कांग्रेस में किए गए नवीनतम चीनी दावे निश्चित रूप से स्थिति को बद से बदतर बनाने जा रहे हैं। जैसा कि अमेरिका पूर्व की ओर अपने पंजे फैला रहा है, चीन अपने सहयोगियों विशेष रूप से रूस के साथ मिलकर, पश्चिम अतिक्रमण क्षेत्रों की ओर बढ़ रहा है, जो पूर्व में अमेरिका और उसके सहयोगियों के एकाधिकार में था, जिससे "नया शीत युद्ध" पैदा हो रहा है।

डिजिटल युआन को डिजाइन करने के लिए नवीनतम प्रयास और इसे अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा के रूप में प्रोजेक्ट करना युद्ध के बाद के अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक और वित्तीय संबंधों में अमेरिकी प्रभुत्व की स्थिति के लिए एक गंभीर चुनौती है। देशों द्वारा अपने तेल के आयात के लिए रूबल भुगतान के लिए हाल ही में रूसी आग्रह भी डॉलर की वैश्विक स्थिति के लिए एक झटका है।

2.4 : इसने अमेरिकी साम्राज्यवाद और सामाजिक साम्राज्यवादी चीन के बीच अंतर्विरोध को पहले से कहीं अधिक तेज कर दिया है। अफगानिस्तान से अपनी वापसी के तुरंत बाद, जिसके बाद चीन वहां एक रणनीतिक खिलाड़ी के रूप में उभरा, अमेरिकी साम्राज्यवाद ने AUKUS औकस की शुरुआत की है - एक परमाणु-आधारित एंग्लो-सैक्सन सैन्य गठबंधन, जो ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड और अमेरिका से बना है, जो एशिया-प्रशांत और पूर्व और दक्षिण चीन सागर में ,ताइवान जिसका केंद्रबिंदु है चीन के खिलाफ अपने उकसाने वाली हस्तक्षेपों को तेज करता है। इस परमाणु-सैन्य समझौते पर हस्ताक्षर करने में, इसने फ्रांस सहित नाटो के सदस्यों को अंधेरे में रखा, जबकि फ्रांस का पहले से ही ऑस्ट्रेलिया के साथ एक पनडुब्बी सौदा हुआ है , जिसके कारण फ्रांस ने तुरंत वाशिंगटन से अपने राजदूत को वापस ले लिया। हालांकि इस मुद्दे को अस्थायी रूप से सुलझा लिया गया है, लेकिन इसने नाटो में निहित कमजोरी को उजागर किया। अमेरिकी साम्राज्यवाद के साथ पूर्व के करीबी एकीकरण के बाद ब्रेक्सिट के माध्यम से यूरोपीय संघ से ब्रिटेन के अलग होने के बाद, यूरोपीय संघ की अग्रणी शक्तियों ने अमेरिकी नेतृत्व वाले नाटो से स्वतंत्र एक यूरोपीय सेना के गठन के लिए गंभीर होमवर्क शुरू कर दिया है।

2.5 : साम्राज्यवादी रूस द्वारा यूक्रेन पर हाल ही में हमला हालांकि निंदनीय रूप से अपनी सदस्यता को और बढ़ाकर 30-सदस्यीय नाटो को फिर से मजबूत करने के अमेरिकी प्रयासों के साथ जुड़ा हुआ है। जब 1991 में सोवियत संघ के विघटन के साथ शीत युद्ध समाप्त हुआ, नाटो की सदस्यता 16 थी, और जब नाटो का उद्घाटन 1949 में ट्रूमैन द्वारा किया गया था, जो शीत युद्ध का नेतृत्व करने के लिए महत्वपूर्ण सैन्य संस्थान के रूप में था, इसकी सदस्यता केवल 12 थी। जैसा कि स्पष्ट है, यूक्रेन पर रूसी हमला, यूक्रेन के नव नाज़ी शासकों को नाटो की सदस्यता ग्रहण करने पर मजबूर किये जाने, जो कि रूस की सीमाओं से लगे देशों के सैन्यकरण की अमरीकी साजिश की उपज थी। अब यूक्रेन अमेरिका के नेतृत्व वाले नाटो बलों के हाथों में एक मोहरे की तरह है। और जो चल रहा है वह एक अंतर-साम्राज्यवादी संघर्ष है,जहां एक तरफ अमरीका नीत नाटो गठबंधन है और दूसरी तरफ रूस। जहां यूक्रेन की स्थिति मात्र एक प्यादे से ज्यादा कुछ नहीं है। यूक्रेन युद्ध, जबकि दुनिया के अग्रणी हथियारों के निर्माताओं विशेष रूप से जो अमरीका के हैं, तिजोरियों में अधिक धन प्रवाह की सुविधा प्रदान करता है। खासकर तीन सबसे बड़े कृषि-बहुराष्ट्रीय कंपनियों कारगिल, मोनसेंटो और ड्यूपॉन्ट, जो पहले से ही यूक्रेन में लगभग 17 लाख हेक्टेयर की अत्यधिक उपजाऊ भूमि खरीद चुके हैं। यह संकटग्रस्त वित्त पूंजी के लिए एक और अवसर है, जो अपने संकट के बोझ को दुनिया के मेहनतकश और उत्पीड़ित जनता के कंधों पर डाल रहे हैं। जबकि ईंधन, भोजन और जीविका की अन्य आवश्यक वस्तुओं की कीमतों में वृद्धि आम जनता की कमर तोड रही है।

2.6 : यूक्रेन पर रूसी हमले और बिना किसी रुकावट के जारी युद्ध ने वैश्विक महत्व के दूरगामी नतीजों को जन्म दिया है। इसने एक ओर अमेरिका और उसके सहयोगियों तथा दूसरी ओर चीन व रूस के बीच अंतर-साम्राज्यवादी अंतर्विरोधों को और तेज कर दिया है । चीन के खिलाफ निर्देशित एशिया-प्रशांत में बढ़ते अमेरिकी फोकस के प्रत्यक्ष परिणाम के रूप में, चीन ने " वैश्विक सुरक्षा पहल "के लिए पहल की है, विशेष रूप से उसने औकस संधि को अपना निशाना बनाया है। AUKUS संधि के आधार पर अमेरिका एक" एशियाई नाटो" बनाने की परिकल्पना कर रहा है। यूएस हाउस ऑफ स्पीकर नैन्सी पेलोसी की ताइवान की यात्रा के बाद चीन के सैन्य अभ्यासों ने ताइवान और आसपास के क्षेत्रों को बदले की कारवाई में घेर लिया और इसके बाद दक्षिण चीन सागर में अमरीकी सातवें बेड़े की तैनाती के बाद चीन-अमेरिका के तनाव को और बढ़ा दिया। "ताइवान प्रश्न" को हल करके "चीनी एकीकरण को पूरा करने" के लिए "कठोर और अडिग दृष्टिकोण" की घोषणा करने वाली चीनी कम्युनिस्ट पार्टी (सीपीसी) की 20 वीं कांग्रेस में किए गए नवीनतम चीनी दावे निश्चित रूप से स्थिति को बद से बदतर बनाने जा रहे हैं। जैसा कि अमेरिका पूर्व की ओर अपने पंजे फैला रहा है, चीन अपने सहयोगियों विशेष रूप से रूस के साथ मिलकर, पश्चिम अतिक्रमण क्षेत्रों की ओर बढ़ रहा है, जो पूर्व में अमेरिका और उसके सहयोगियों के एकाधिकार में था , जिससे "नया शीत युद्ध" पैदा हो रहा है।

2.7 : चीन द्वारा अमेरिका को निशाना बनाने से संबंधित एक ध्यान देने योग्य बात यह है कि अफ्रीका और लैटिन अमेरिका में चीन की बढ़ती भागीदारी हो रही है ,जहां चीन का 2008 के विश्व आर्थिक संकट से पहले बहुत कम बोलबाला था। अब चीन अफ्रीकी महाद्वीप का सबसे बड़ा व्यापारिक भागीदार है और सूडान में सैन्य शासकों द्वारा चीन की नवीनतम सहायता पहले से ही स्वीकार की गई है। चीन ने पहले से ही अल्जीरिया, नाइजीरिया, इथियोपिया, कांगो, केन्या अंगोला, आदि जैसे देशों में अपने राजनीतिक-आर्थिक दबदबे की स्थापना की है, इसके अलावा 2016 के बाद से जिबूती में उसने अपने घोषित सैन्य अड्डे की स्थापना की है,जहां उसके साथ-साथ अन्य साम्राज्यवादी शक्तियों के भी अड्डे हैं। कोविद महामारी चीन के लिए अफ्रीका में अपने निवेश में तेजी लाने का एक उपयुक्त अवसर रहा है। आज चीन 32 अफ्रीकी देशों में अग्रणी द्विपक्षीय ऋणदाता है और समग्र रूप से अफ्रीकी महाद्वीप के लिए शीर्ष अधोसंरचनात्मक फाइनेंसर और अंतर्राष्ट्रीय ऋणदाता है। 46 अफ्रीकी देशों द्वारा BRI(बेल्ट एंड रोड इनिटिएटिव) में हस्ताक्षर करने के साथ, अफ्रीका इसका सबसे बड़ा क्षेत्रीय घटक बन गया है।

2.8 : लैटिन अमेरिका में चीन की राजनीतिक-आर्थिक भूमिका भी तेजी से बढ़ रही है। इसने दक्षिण अमेरिकी महाद्वीप के सबसे बड़े देश वेनेजुएला और ब्राजील के साथ घनिष्ठ आर्थिक और सुरक्षा संबंध विकसित किए हैं। हालांकि, लैटिन अमेरिका को कभी अमेरिकी साम्राज्यवाद का पिछवाड़ा माना जाता था, चीन ने पहले ही अमरीका को लैटिन अमेरिका के सबसे बड़े व्यापारिक भागीदार के रूप में पीछे छोड़ दिया है। 19 लैटिन अमेरिकी देशों द्वारा पहले से ही BRI पर हस्ताक्षर करने के जरिए, चीनी राज्य फर्म और वित्तीय संस्थान वहां के अधोसंरचनात्मक विकास में एक प्रमुख भूमिका निभा रहे हैं। हाल ही में, अमेरिका और अन्य साम्राज्यवादी शक्तियों के साथ, चीन भी अंतर-अमेरिकी विकास बैंक का सदस्य बन गया है। जाहिर है, लैटिन अमेरिका में चीनी पूंजी निवेश के अपने सहवर्ती राजनीतिक, राजनयिक, सुरक्षा और सांस्कृतिक प्रभाव होंगे।

2.9 : यहां तक कि चीनी पूंजी और माल निर्यात में यह 'पश्चिम की ओर' विस्तार अमेरिका और चीन के बीच तीव्र अंतर-साम्राज्यवादी अंतर्विरोध पैदा कर रहा है। लैटिन अमेरिका के कई देशों में वामपंथी और प्रगतिशील आंदोलनों के उभार द्वारा चिह्नित "दूसरे गुलाबी ज्वार" के उदय का गवाह बन रहा है। लैटिन अमेरिका में इस प्रगतिशील राजनीतिक बदलाव को मुख्य रूप से आईएमएफ-विश्व बैंक द्वारा समर्थित नवउदारवादी नीतियों, भ्रष्टाचार, अत्यधिक गरीबी, बेरोजगारी और पारिस्थितिक तबाही के कारण पिछले दो वर्षों के दौरान आईएमएफ-विश्व बैंक द्वारा पोषित आर्थिक संकट के कारण लोगों के असंतोष और प्रतिरोध के लिए जिम्मेदार ठहराया गया है। जैसा कि 2020 के दौरान लैटिन अमेरिका और कैरिबियन पर आर्थिक आयोग द्वारा अनुमान लगाया गया था, लैटिन अमेरिका में 6.8 प्रतिशत की महामारी-प्रेरित भयावह विकास संकुचन था। चिली में गेब्रियल बोरिक , बोलीविया में लुइस एर्स, पेरू में पेड्रो कैस्टिलो, होंडुरास में शियोमारा कास्त्रो, कोलंबिया में गुस्तावो पेट्रो और कोस्टा रिका में रोड्रिगो चेव्स की हालिया चुनावी जीत , साम्राज्यवाद के सेवक नवउदारवादी नवफासीवादी शासकों के खिलाफ लोगों की बढ़ती नाराजगी की अभिव्यक्तियाँ हैं।

2.10 : यहां तक कि चीनी पूंजी और माल निर्यात में यह 'पश्चिम की ओर' विस्तार अमेरिका और चीन के बीच तीव्र अंतर-साम्राज्यवादी अंतर्विरोध पैदा कर रहा है। लैटिन अमेरिका के कई देशों में वामपंथी और प्रगतिशील आंदोलनों के उभार द्वारा चिह्नित "दूसरे गुलाबी ज्वार" के उदय का गवाह बन रहा है। लैटिन अमेरिका में इस प्रगतिशील राजनीतिक बदलाव को मुख्य रूप से आईएमएफ-विश्व बैंक द्वारा समर्थित नवउदारवादी नीतियों, भ्रष्टाचार, अत्यधिक गरीबी, बेरोजगारी और पारिस्थितिक तबाही के कारण पिछले दो वर्षों के दौरान आईएमएफ-विश्व बैंक द्वारा पोषित आर्थिक संकट के कारण लोगों के असंतोष और प्रतिरोध के लिए जिम्मेदार ठहराया गया है। जैसा कि 2020 के दौरान लैटिन अमेरिका और कैरिबियन पर आर्थिक आयोग द्वारा अनुमान लगाया गया था, लैटिन अमेरिका में 6.8 प्रतिशत की महामारी-प्रेरित भयावह विकास संकुचन था। चिली में गेब्रियल बोरिक, बोलीविया में लुइस एर्स, पेरू में पेड्रो कैस्टिलो, होंडुरास में शियोमारा कास्त्रो, कोलंबिया में गुस्तावो पेट्रो और कोस्टा रिका में रोड्रिगो चेव्स की हालिया चुनावी जीत, साम्राज्यवाद के सेवक नवउदारवादी नवफासीवादी शासकों के खिलाफ लोगों की बढ़ती नाराजगी की अभिव्यक्तियाँ हैं।

2.11 : पश्चिमी एशिया (मध्य पूर्व) में, चीन की उन्नति और डॉलर-साम्राज्य की पतन की ओर रुझान और पेट्रो-डॉलर पर पड़ रहे प्रभाव के कारण, अमेरिकी साम्राज्यवाद वहां भू-राजनीति के पुन: व्यूह रचना की योजना बना रहा है।....

यह दिसंबर 2020 में हस्ताक्षरित अब्राहम समझौते में प्रकट हुआ था जिसमें ज़ायोनी इज़राइल और संयुक्त अरब अमीरात (यूएई) के नेतृत्व में अरब देशों के एक समूह के बीच संबंधों को सामान्य बनाने का दावा किया गया था।
लगभग एक साल बाद अक्टूबर 2021 में, अमेरिका के नेतृत्व में एक आभासी बैठक में, अमेरिका, इजरायल, यूएई और भारत के विदेश मंत्रियों ने अब्राहम समझौते के पीछे सहयोग और साझेदारी को मजबूत करने का फैसला किया। यद्यपि पश्चिम एशिया में राजनीतिक गतिशीलता भारत - प्रशांत महासागर क्षेत्र(इंडो-पैसिफिक) से भिन्न है, तथापि नई अमेरिकी पहल को चीन से निपटने के लिए डिज़ाइन किए गए एशिया-प्रशांत क्षेत्र में जिसमें अमेरिका, भारत, ऑस्ट्रेलिया और जापान शामिल हैं से बने क्वाड या चतुर्भुज के लिए "अमरीका की इस नई पहल को मध्य पूर्व क्वाड"के रूप में पेश किया गया।

2.12 : इस बीच, अब्राहम समझौते की आड़ में, यहूदी कट्टरपंथियों(ज़ायोनीवादियों) द्वारा फिलिस्तीनियों के खिलाफ मानवाधिकारों का उल्लंघन बढ़ रहा है। कब्जाए गए पश्चिमी किनारे (वेस्ट बैंक) और घेराबंदी में रखे गए गाजा पट्टी को घेरने के साथ-साथ इजरायली पुलिस और आधिकारिक सुरक्षा तंत्र के साथ, ज़ायोनीवादी आतंकवादी समूहों को भी फिलिस्तीनी लोगों के खिलाफ उनके बीच भय पैदा करने और अस्तित्व के लिए उनके संघर्ष को कमजोर करने के लिए उकसाया जाता है। अमेरिका द्वारा इस नए दृष्टिकोण के पीछे का एजेंडा फिलिस्तीनी जनता के मुद्दों की जानबूझकर उपेक्षा के लिए राजनीतिक माहौल बनाना है और उन पर बढ़ते दमन को कवर करना है जो मानवता के खिलाफ अपराधों में बढ़ोतरी कर रहा है। इसराइली ज़ायोनवादीयों के कब्जे वाले क्षेत्रों पर महामारी का प्रभाव सबसे विनाशकारी रहा है क्योंकि ज़ायोनी सुरक्षा बलों ने इसे कोविड प्रोटोकॉल को लागू करने की आड़ में फिलिस्तीनियों पर भयावह प्रतिबंध, सामाजिक-आर्थिक दुख और बोझ डालने के लिए एक सुनहरे अवसर के रूप में इस्तेमाल किया।

2.13 : हमारे पड़ोस में, श्रीलंका अब एक अभूतपूर्व आर्थिक पतन और सामाजिक-राजनीतिक संकट में है। एक नव-औपनिवेशिक आश्रित देश के रूप में साम्राज्यवादी केंद्रों के निर्देशन में नवउदारवादी-कॉरपोरेटपरस्त विकास नीति का पीछा करते हुए श्रीलंका की ये हालत हुई है। हालांकि संकट की शुरुआत तक दक्षिण एशिया में श्रीलंका , 'मानव विकास सूचकांक' में सबसे ऊंचाई पर था , लेकिन इसकी प्रमुख कमाई मुख्य रूप से पर्यटन और प्राथमिक उत्पादों के निर्यात से हुई।वहां संपूर्ण ऋण-वित्तपोषित आधारभूत ढांचा का निर्माण पर्यटकों को आकर्षित करने के लिए किया गया था। आर्थिक और सामाजिक संकटों का आधार पहले से ही कई कारकों के विन्यास के माध्यम से निर्धारित किया गया था जैसे कि कॉर्पोरेट करों में भारी कमी, कुल आर्थिक कुप्रबंधन, जिसमें असंतुलित और दूर दृष्टि के अभाव वाली नीतियों, चरम भ्रष्टाचार और क्रोनी (जुआड़ी/ दरबारी) पूंजीवाद शामिल है। जो कि सिंहली बुद्धवाद की विचारधारा द्वारा समर्थित प्रशासन की पूरी बागडोर रखने वाले राजपक्षे परिवार के साथ जुडा हुआ है। इस पृष्ठभूमि में, लगभग दो साल की महामारी ईस्टर बमबारी से पहले और यूक्रेन युद्ध के बाद पूरी तरह से एक तरफ विदेशी पर्यटक प्रवाह का सूख जाना और दूसरी तरफ ईंधन, भोजन और दवा की कीमतों को आसमान छू लेना है जो दूसरी ओर निजी और सरकारी बचत दोनों को मिटा देते हैं। चीन के BRI से जुड़े परियोजनाओं सहित श्रीलंका में निर्मित विभिन्न आधारभूत और सामाजिक संरचनाओं से नियमित आधार पर किसी भी पर्याप्त आय की उपज के बिना देश के लिए भारी ऋण-देनदारी का बोझ बन गए हैं। आज, दिवालिया श्रीलंकाई शासन , सहवर्ती कठोर शर्तों के साथ राहत (बेल आउट) कार्यक्रम के लिए नव उपनिवेशिक वित्तीय संस्थानों और विभिन्न साम्राज्यवादी शक्तियों के दरवाजे पर दस्तक दे रहा है।

2.14 : इस प्रकार, आज सामान्य रूप से अंतर्राष्ट्रीय स्थिति कुछ कॉर्पोरेट अरबपतियों के हाथों में धन संचय के भयावह स्तरों, अत्यधिक गरीबी के अभूतपूर्व स्तर, भयावह अनुपातों में पारिस्थितिक विनाश और साम्राज्यवादी संकट के बोझ को श्रमिक वर्ग और उत्पीड़ितों के कंधों पर स्थानांतरित करने से चिह्नित है। अंतर-साम्राज्यवादी अंतर्विरोधों के तेज होने के साथ-साथ, शोषित और उत्पीड़ित लोग सत्तारूढ़ व्यवस्था के खिलाफ दुनिया के कई हिस्सों में विभिन्न रूपों में विरोध में खड़े हो रहे हैं। भारत जैसे कुछ देशों के शासक वर्गों ने भी साम्राज्यवादी शक्तियों के साथ अपनी सौदेबाजी की स्थिति को मजबूत करने के लिए इस गहन साम्राज्यवादी संकट का उपयोग किया है। हालांकि, इन संघर्षों और आंदोलनों का नेतृत्व करने में सक्षम कम्युनिस्ट पार्टियों की अनुपस्थिति में, शासक वर्ग और उनके साम्राज्यवादी स्वामी, जनता के रोष को सुरक्षित रास्ते में मोड़ने में सफल रहे हैं।

2.15 : साम्राज्यवाद के गहरे संकटों का लाभ उठाते हुए, नव-फासीवादी ताकतें पूरी दुनिया में उभर कर सामने आई हैं। कई देशों में, जैसे हंगरी, तुर्की, भारत, रूस और अन्य जगहों पर, फासीवादी शासन पहले से ही अस्तित्व में आ गए हैं, जबकि इंग्लैंड(यूके) और अमेरिका जैसे प्रमुख साम्राज्यवादी देश भी नव-फासीवाद की ओर इस प्रवृत्ति का हिस्सा हैं।

3. अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर हमारे कार्यभार।

3.1 : आज के संकट-ग्रस्त संदर्भ में जहां क्रांतिकारी परिवर्तन के लिए वस्तुनिष्ठ अंतर्राष्ट्रीय स्थिति अनुकूल है, जबकि सामाजिक परिवर्तन के लिए आवश्यक आत्मगत कारक कमजोर हैं, जो आवश्यक है वह है साम्राज्यवाद और नव-फासीवाद के खिलाफ कम्युनिस्ट पार्टियों और क्रांतिकारी संगठनों के बीच समन्वित कार्रवाई ।

3.2 : 2018 में आयोजित 11 वी कांग्रेस द्वारा अनुमोदित राजनीतिक प्रस्ताव ने बताया था: "जैसा कि साम्राज्यवाद का प्रतिक्रियावादी सार अधिक से अधिक भयावह होता जा रहा है, एक विश्वव्यापी साम्राज्यवाद विरोधी आंदोलन जो प्रभावी रूप से आक्रामकता के खतरे को चुनौती दे सकता है, कॉरपोरेटाइजेशन, फासीवादीकरण और प्रतिक्रिया के सभी रूपों का विरोध कर सकता है तथा लोकतंत्र और समाजवाद की ओर आगे बढ़ सकता है, एक जरूरी आवश्यकता बन गया है।" आज चार वर्षों के बाद, अंतर्राष्ट्रीय स्थिति का हमारा विश्लेषण इस कार्य को और अधिक महत्वपूर्ण बनाता है।

3.3 : इस कार्य को पूरा करने के लिए, साम्राज्यवाद और नवउदारवादी कॉरपोरेटकरण के बारे में वैश्विक स्तर और विशेष देशों की ठोस परिस्थिति में वैचारिक स्पष्टता अत्यंत महत्वपूर्ण है। इसलिए, इसके प्रमुख सदस्यों में से एक के रूप में आइकोर (ICOR)और इसके अभियानों में सक्रिय भूमिका निभाते हुए, हमारे तत्काल अंतर्राष्ट्रीय कार्यों में से एक आइकोर और मार्क्सवादी लेनिनवादी ताकतों के बीच वैचारिक-सैद्धांतिक बहस को आगे बढ़ाना है ।ताकि सामान्य रूप से आज के साम्राज्यवाद की बुनियादी समझ और नवउपनिवेशिक भूमंडलीकरण ,कॉरपोरेटकरण के तहत नवउपनिवेशिक आश्रित देशों की विशेषता के बारे में भी बुनियादी समझ बन सके ।
हमें विशेष रूप से नव-औपनिवेशिक रूप से आश्रित देशों में क्रांतिकारी दलों और समान विचारधारा वाले संगठनों के साथ द्विपक्षीय संबंधों को विकसित करना है, ताकि साम्राज्यवाद-विरोधी, फासीवाद विरोधी संघर्षों से संबंधित वैचारिक स्पष्टता प्राप्त हो और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर व्यावहारिक सहयोग कायम किया जा सके।

4. राष्ट्रीय स्थिति

4.1 : पार्टी की 10 वीं कांग्रेस 2015 में आयोजित की गई थी जब मोदी शासन ने अपने कार्यकाल के सिर्फ 8 महीने पूरे किए थे। नीतियों में धुर दक्षिणपंथी मोड़ का निचोड़ निकालते हुए , तब अपनाये गये राजनीतिक प्रस्ताव में चिन्हित किया गया था कि: "2.9 मोदी के सत्तारोहण के बाद मनमोहन सिंह की आर्थिक नीति (मनमोहनॉमिक्स) को निर्मम तरीके से लागू किया गया है, जो कि पूर्व के 'गुजरात मॉडल' के क्रियान्वयन में प्रकट होता है, जो पूरे भारत में कॉर्पोरेट-अनुकूल शब्दावलियों जैसे कि 'न्यूनतम सरकार' ,"अच्छा प्रबंधन", " विकास बंधुता" आदि के रूप में लागू किया गया। आने वाले वर्षों में मोदी शासन की आर्थिक नीति में व्यापार के लिए पारदर्शी नीति का माहौल शामिल किया गया , जिसमें" व्यापार करने में आसानी ", उदार कर व्यवस्था, रक्षा और रेलवे जैसे रणनीतिक क्षेत्रों में भी प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (एफडीआई) का पूर्ण उदारीकरण , सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकिंग कार्यों का बहुराष्ट्रीय कंपनियों और रिलायंस सरीखे कॉरपोरेट दैत्यों के हित में आउटसोर्सिंग , निजीकरण के लिए उन्माद,१०० शहरों को विश्व स्तर की सुविधाओं से लैस करना, कोयला क्षेत्र में निजी निवेश को आकर्षित करना, परमाणु ऊर्जा परियोजनाओं को पूरा करना और अंतर्राष्ट्रीय परमाणु समझौतों का संचालन, आधुनिकीकरण और कृषि का निगमीकरण, समय-समय पर वन और परियोजनाओं के लिए पर्यावरणीय मंजूरी, और इसी तरह पूरी तरह से संकटग्रस्त अंतरराष्ट्रीय वित्त पूंजी की आवश्यकताओं और मार्गदर्शन के अनुरूप ही तमाम बातें लागू की जा रही हैं।" बेशक, राज्य सरकारों के संसाधन जुटाने के संवैधानिक संघीय अधिकारों को खत्म करने वाले बलपूर्वक उपर से थोपे गए नोटबंदी और जीएसटी ने इस धुर दक्षिणपंथी नवउदारवादी प्रक्रिया के उत्प्रेरक के रूप में काम किया है।

4.2 : 2018 में 11 वीं कांग्रेस आयोजित होने तक, मोदी सरकार ने चार साल पूरे कर लिए थे। पार्टी कांग्रेस द्वारा अपनाए गए राजनीतिक प्रस्ताव में कहा गया था कि: "2.I. चार साल से अधिक के मोदी शासन द्वारा भारत के सामाजिक-आर्थिक और राजनीतिक ताना बाना को भयावह विघटन के कगार पर पहुंचा दिया गया है। आरएसएस के नेतृत्व में चरम विभाजनकारी नीतियों का फैलाव , लोगों के बीच आपसी घृणा की प्रवृत्ति, और दलितों और अल्पसंख्यकों के बीच असुरक्षा की भावना को बढ़ाकर ,ऐसे माहौल में, भाजपा सरकार ने सामाजिक जीवन के हर पहलू को कॉर्पोरेट पूंजी की दृढ़ पकड़ के तहत लाया है।.....

.....अमेरिकी साम्राज्यवाद के कनिष्ठ साझेदार के रूप में भारत की स्थिति को मजबूत करना और इसके साथ रणनीतिक गठबंधन में प्रवेश करने के जरिए मोदी ने अंतरराष्ट्रीय मामलों में भारत की गुट निरपेक्ष स्थिति को काफी हद तक नष्ट कर दिया है। संसदीय लोकतंत्र के सभी संस्थानों को इस हद तक गिरा दिया गया है ताकि कॉर्पोरेट, भगवा फासीवादी आक्रमण को सुविधाजनक बनाया जा सके।"

4.3 : अब, जब 12 वीं कांग्रेस आयोजित की जा रही है, तो मोदी 1 और मोदी .2 के तहत कॉर्पोरेट-भगवा फासीवादी शासन ने 8 साल से अधिक का कार्यकाल पूरा कर लिया है। कॉरपोरेट पूंजी की सेवा करने वाली मनुवादी हिंदुत्व की विचारधारा द्वारा समर्थित, मोदी का सबसे प्रतिक्रियावादी फासीवादी शासन, कॉरपोरेटकरण और भगवाकरण दोनों का सूत्रधार बन गया है। अब तक, RSS, दुनिया के सबसे बड़े फासीवादी संगठन ने भारत में सभी संवैधानिक और प्रशासनिक संस्थानों के भगवाकरण के लिए अग्रणी सामाजिक जीवन के हर पहलू का फासीवादीकरण कर दिया है। मोदी.2 के तहत 2019 के मध्य से, संविधान के अनुच्छेद 370 को निरस्त करने जैसे फासीवादी हमलों के जरिए एक तरफ कश्मीर को टुकड़ों में तोड़कर और दूसरी ओर भारतीय संघ में जबरन एकीकरण, बाबरी मस्जिद के ही स्थल पर राम मंदिर का निर्माण, नागरिकता कानून में संशोधन के जरिए मुस्लिमों को दूसरी श्रेणी का नागरिक बनाना और यहां तक कि नागरिकता से भी वंचित करने के बारे में कदम उठाया गया। NEP 2020 के माध्यम से शिक्षा का भगवाकरण और निगमीकरण, एक समान नागरिक संहिता की ओर बढ़ना आदि,RSS द्वारा बहुराष्ट्रीय, बहुभाषी, बहुसांस्कृतिक, बहु-जातीय, और बहु-धार्मिक भारत पर एक बहुसंख्यक हिंदुराष्ट्र जबरिया थोपने के लिए मोदी सरकार का उपयोग किया जा रहा है। इसे सुविधाजनक बनाने के लिए, प्रतिक्रियाशील और दकियानूसी परंपराओं को खाद पानी दिया जा रहा है और आधुनिकता और तर्कसंगत-वैज्ञानिक सोच के मूल्यों को खारिज कर दिया जा रहा है। जहां आमतौर पर अल्पसंख्यकों दमन किया जा रहा है, मुस्लिमों को विशेष रूप से इस्लामोफोबिया(इस्लाम के प्रति घृणा) फैलाने के माध्यम से निशाना बनाया जा रहा है। RSS- नियंत्रित भगवा शासन ने प्रतिक्रियावादी कॉर्पोरेट-वित्त पूंजी के साथ खुद को एकीकृत किया है, जिसने भारत को एक विशिष्ट नवफासीवादी शासन में बदल दिया है। नवफासीवाद के तहत,पर्यावरणीय प्रभाव आकलन (ईआईए), आदि में संशोधन के माध्यम से प्रकृति की बेलगाम कॉर्पोरेट लूट की जा रही है जिसने एक अभूतपूर्व पारिस्थितिकी तबाही को जन्म दिया है।

4.4 : कोविड महामारी की पूर्व संध्या पर, राष्ट्रीय संपदा और बड़े पैमाने पर संपत्ति व धन की भारतीय कॉरपोरेट्स द्वारा नोटबंदी, जीएसटी और एकमुश्त लूट के कारण, भारत एक बड़े आर्थिक संकुचन, रिकॉर्ड बेरोजगारी और बड़े पैमाने पर बदहाली की दृढ़ पकड़ में था। 2019 में सत्ता में आने के साथ मोदी शेष सार्वजनिक क्षेत्र की इकाइयों जैसे रेलवे स्टेशन, हवाई अड्डे, एलआईसी, हथियार कारखाने आदि के कुल विनिवेश को पूरा करने की प्रक्रिया में अधिक जोशीले व तत्पर रहे हैं। इस बात की निरंतरता में, मोदी शासन ने अपने कॉर्पोरेट-फासीवादी एजेंडे के लिए एक अतिरिक्त अवसर के रूप में महामारी का इस्तेमाल किया।

यहां तक कि संसद से परामर्श किए बिना, और किसी भी तैयारी के बिना, नवफासीवादी शासन ने दुनिया के सबसे कठोर और सबसे अधिक पीड़ादायक लॉकडाउन को महीनों के लिए अचानक से लागू कर दिया।जिससे उद्योग धंधे , व्यापार और परिवहन ठप्प हो गए। और यहां तक कि कृषि भी प्रभावित हुई और प्रशासन को और अधिक दमनकारी बनाया गया ।जिसने विशेष रूप से प्रवासियों और असंगठित श्रमिकों को लक्षित करते हुए, उन्के न्यूनतम भोजन और आजीविका से इनकार करते हुए उनके जीवन को तहस नहस किया गया। नतीजतन, जबकि 2020 के मध्य तक महामारी द्वारा पैदा वैश्विक संकुचन लगभग 6 प्रतिशत के आसपास था, भारत में यह लगभग 24 प्रतिशत था। इस प्रकार कोविड केवल भारत के अद्वितीय आर्थिक टूटन के लिए आंशिक जिम्मेदार हो सकता है; मुख्य जिम्मेदार मोदी सरकार की कॉर्पोरेट पूंजी की सेवा करने की धुर दक्षिणपंथी नवफासीवादी नीतियां हैं।

4.5 : नागरिकता संशोधन कानून(सीएए),मुसलमानों के लिए दूसरे दर्जे के नागरिकता पर मुहर लगाकर हिंदुराष्ट्र की ओर बढ़ने वाला आरएसएस का एक सधा हुआ कदम था। ऐतिहासिक शाहीनबाग आंदोलन सहित देशव्यापी सीएए विरोधी आंदोलन ने नवफासीवादी शासन को रक्षात्मक बना दिया। लेकिन महामारी के आगमन के साथ और कोविद प्रोटोकॉल के अनुरूप, दमन को बढ़ाया गया और आंदोलन को वापस लेने के लिए मजबूर करने के लिए शर्तों का निर्माण किया गया।

4.6 : हालांकि, यहां तक कि जब देश महामारी के बोझ के तहत कराह रहा था, एक अवसर के रूप में कोविद का उपयोग करते हुए, मोदी शासन ने सितंबर 2020 में डब्ल्यूटीओ के इशारे पर कृषि के कॉरपोरेटकरण उद्देश्य से तीन कृषि कानूनों को लागू किया, यहां तक कि उन्हें नियमित संसदीय समितियों द्वारा जांच के अधीन किए बिना ही किया गया। जिसके खिलाफ किसानों के नेतृत्व में एक ताकतवर गंभीर ऐतिहासिक संघर्ष सीएए विरोधी आंदोलन की वापसी के महीनों बाद उभरा। किसानों का ऐतिहासिक आंदोलन एक वर्ष से अधिक समय तक जारी रहा। इसने कृषि कानूनों को वापस लेने के लिए शासन को मजबूर किया। यह कॉरपोरेट परस्त 44 श्रम संहिताओं(लेबर कोड)के खिलाफ इसी प्रकार का एक आक्रामक अभियान शुरू करने में राजनीतिविहीन मुख्यधारा के ट्रेड यूनियन नेतृत्व की अक्षमता के संदर्भ में एक महान जीत थी। इससे भी महत्वपूर्ण बात यह है कि लंबे समय तक किसानों के संघर्ष के अनुभव ने कृषि क्षेत्र में हरित क्रांति प्रेरित परिवर्तनों की पैठ को दिखाया है, और श्रमिक वर्ग, किसान और तमाम उत्पीड़ित वर्गों के बीच व्यापक गठबंधन के लिए नई संभावनाओं को खोला है ताकि ये तमाम ताकतें एक होकर कॉर्पोरेट और नवफासीवाद के खिलाफ लड़ाई में उतर सकें।

4.7 : इसी समय, किसानों के आंदोलन ने विशिष्ट संगठनात्मक पहलों की तत्काल आवश्यकता को आगे बढ़ाया है, जो कृषि निगमीकरण (कॉरपोरेटकरण) के तेज होने के संदर्भ में उभरते कार्यों को ठीक से संभालने में सक्षम हो। यद्यपि पार्टी को नवउदारवादी-कॉरपोरेटकरण नीतियों के तहत लाए गए कृषि परिवर्तन की ठोस समझ है, लेकिन विभिन्न राज्यों में कृषि मोर्चे में हमारे काम में बहुत असमानता है। कई क्षेत्रों में यह मुख्य रूप से उनकी मांगों के लिए भूमिहीन गरीब किसानों को संगठित करने तक ही सीमित है। हरित क्रांति (GR) प्रेरित परिवर्तनों के खिलाफ भी कुछ अभियान और संघर्ष हुए हैं, खासकर जब किसानों के आंदोलन दिल्ली की सीमाओं तक पहुंच गए हैं। किसानों की भूमि की रक्षा के लिए संघर्ष,न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) के लिए कानूनी गारंटी के साथ एपीएमसी की स्थापना के माध्यम से कृषि उत्पादों के लिए लाभकारी कीमत सुनिश्चित करने के लिए आदि संघर्ष , किसान आधारित कृषि के निर्वाह के लिए अपरिहार्य हैं। वर्तमान स्थिति की मांगों के अनुसार, और हमारे अपने अनुभव के आधार पर, इन दो अंतर-संबंधितों को आगे बढ़ाने के लिए कार्यक्रम आधारित और संगठनात्मक परिवर्तनों को विकसित करने सहित उचित कदम उठाने होंगे।लेकिन एक ही समय में किसान आंदोलन के समग्र विकास के लिए अलग-अलग कार्य करने होंगे।

4.8 : हाल के विधानसभा चुनावों में बीजेपी की सफलता के बाद, विशेष रूप से इसके द्वारा शासित चार राज्यों में सत्ता में वापसी के बाद, पूरे देश में एक भयावह स्थिति विकसित हो रही है। राम नवमी और हनुमान जयंती के साथ शुरू होकर, कुछ ही हफ्तों के भीतर, मुस्लिमों को निशाना बनाते हुए आरएसएस गिरोह के नेतृत्व में असंख्य सांप्रदायिक हमले हुए, जो देश के विभिन्न हिस्सों में 'विभाजन के दिनों' की याद दिलाते हैं। पूरा प्रशासन और पुलिस मूक दर्शक बने रहे, और पीड़ितों पर झूठे मामले थोपे जाते रहे जबकि अपराधियों को खुला छोड़ दिया गया। भाजपा शासित राज्यों में जैसे कि यूपी, मध्य प्रदेश, गुजरात, हिमाचल प्रदेश, कर्नाटक, आदि में शब्दशः एक बुलडोजर राज थोप दिया गया है, यानी, फासीवादी शासन द्वारा मुसलमानों के घरों और संपत्तियों को अपने पुलिस और सुरक्षा बलों का उपयोग करके ध्वस्त किया गया।

4.9 : सबसे भयावह राष्ट्रीय राजधानी में जहांगीरपुरी की स्थिति थी, जहां सशस्त्र भगवा गुंडों ने उत्तेजक नारों के साथ मस्जिदों तक मार्च किया और रोहिंगियन और बांग्लादेशी अतिक्रमणकारियों के रूप में निवासियों की ब्रांडिंग करते हुए मुस्लिम घरों और प्रतिष्ठानों पर हमला किया और उनके बाद प्रशासन द्वारा बुलडोजर राज चलाया गया। शीर्ष अदालत के हस्तक्षेप के बाद भी, कॉरपोरेट-संघी मीडिया द्वारा लगातार अवैध प्रवासियों के खिलाफ जहरीले अफवाहों को फैलाया जाता रहा ,जिसके फलस्वरूप तोड़फोड़ जारी रहा ।यह हिटलर के नाज़ीवाद के दिनों के दौरान जो हुआ, उसकी याद दिलाते हुए , मुस्लिमों के प्रति घृणा एक व्यवस्थित और नियोजित तरीके से बनाई गई है, जो जनसंहारों के लिए अनुकूल परिस्थितियों का निर्माण कर रही है। 2024 के आम चुनाव के दौरान चरम सांप्रदायिक ध्रुवीकरण के लिए माहौल बनाना और भारत को आरएसएस के शताब्दी समारोह के अवसर पर हिंदुत्व-फासीवादी एजेंडे की ओर आक्रामक ढंग से आगे बढ़कर हिंदुराष्ट्र घोषित करना इनका उद्देश्य है।

4.10 : हिंदुराष्ट्र की ओर इस योजनाबद्ध कदम में, उत्पीड़ित दलितों और महिलाओं की स्थिति, जो मनुस्मृति के अनुसार 'अमानवीय' है, बदतर होती जा रही है। जातिवादी उत्पीड़न, भेदभाव, हमले और यहां तक कि हत्याएं नियमित रूप से की जा रही हैं। मनुवादी-हिंदुत्व शासन में खुले और गुप्त, आधिकारिक और गैर-आधिकारिक संरक्षण के साथ, ब्राह्मणवादी जाति व्यवस्था पूरी तरह से पूरे सत्तारूढ़ प्रणाली में,.....

..... राजनीति, अर्थव्यवस्था, संस्कृति, विज्ञान और अनुसंधान के क्षेत्र में गहराई में धंसी है। संविधान में 124 वें संशोधन के माध्यम से आर्थिक आरक्षण की गारंटी देकर, भाजपा सरकार ने जाति-आधारित आरक्षण को बाहर का रास्ता दिखा दिया है।

यह उच्च जातियों द्वारा सरकारी नौकरियों के एकाधिकार के लिए रास्ता प्रशस्त करेगी है, जिनके पास देश की संपदा और राजनीतिक शक्ति केंद्रित है। इसके साथ ही, आरएसएस और बीजेपी दलितों और निचली जातियों के संगठनों और दलों को विभाजित और विघटित करने में लगे हुए हैं। इसकी अभिव्यक्ति के रूप में, शक्ति-साझाकरण की पेशकश के साथ, हिंदुत्व बलों ने नव-अम्बेडकरवादी पार्टियों और वर्गों के बीच सहयोगियों को बनाने में सफल रहे हैं, जो पहचान की राजनीति को बनाए रखते हैं, जो जाति के विनाश पर अंबेडकर के कार्यक्रम को त्याग देते हैं। वर्ग, जाति और लैंगिकता के बीच अभिन्न संबंध के मद्देनजर, यह महत्वपूर्ण स्थिति पार्टी द्वारा तत्काल वैचारिक और राजनीतिक पहलों के लिए एक साथ जाति उन्मूलन आंदोलन और महिला आंदोलन में जोश के साथ प्राणवायु फूंकने का जोरदार आहवान करती है।

4.10 : अपने फासीवादी चरित्र के अनुरूप, संघीय ढांचा-विरोधी जीएसटी की निरंतरता में, मोदी शासन व्यवस्थित रूप से हिंदी को थोपने के माध्यम से देश के संघीय चरित्र पर चोट करने में लगे हुए हैं।राज्यपाल के पद का दुरुपयोग करते हुए, राज्यों के साथ राजस्व साझा करने के लिए अनिच्छा, राज्यों को अखिल भारतीय नीति की उनकी योजनाओं के बारे में अंधेरे में रखा जा रहा है। देश के विभिन्न क्षेत्रों में इसका प्रभाव देखने को मिल रहा है। जैसा कि पहले ही उल्लेख किया गया है, अनुच्छेद 370 के खात्मा ने कश्मीरी लोगों को पूरी तरह से अलगाव में डाल दिया है और जम्मू-कश्मीर का मुद्दा अब सुलझाना अब असंभव हो गया है। असम, मणिपुर, नागालैंड, मिजोरम और यहां तक कि त्रिपुरा जैसे पूरे उत्तर-पूर्व में, फासीवादी मोदी सरकार विभिन्न राष्ट्रीयताओं, जातीयताओं और धार्मिक वर्गों को एक-दूसरे के खिलाफ खड़ा करने का गंदा खेल खेल रही है। देर से, हालांकि कुछ क्षेत्रों से टुकड़े टुकड़े में वापसी के साथ एएफएसपीए(सशस्त्र बल विशेषाधिकार कानून) को निरस्त करने पर बयानबाजी होती रहती है, यह पीड़ितों के कभी-कभी तीव्र उत्पीड़न से ध्यान हटाने के लिए हिंदुत्व शासन के प्रतिक्रियात्मक हितों की सेवा करने के लिए चयनात्मक और उद्देश्यपूर्ण प्रतीत होता है। एनआरसी और सीएए के आरोपण ने पहले से ही उत्तर-पूर्वी राज्यों में अल्पसंख्यकों और उत्पीड़ित वर्गों को भारी नुकसान पहुंचाया गया था।

यह महत्वपूर्ण स्थिति संघीय सिद्धांतों के आधार पर राज्यों के संघ के रूप में भारत के पुनर्गठन के लिए जनता के निरंतर संघर्षों की मांग करती है और विभिन्न राष्ट्रीयताओं के भाषाई, जातीय और सांस्कृतिक अधिकारों को मान्यता देने की मांग करती है।

4.12 : कोविद महामारी, वैश्विक आर्थिक संकट, तेल की कीमतों में उतार-चढ़ाव आदि ने 60 लाख से अधिक भारतीय प्रवासियों के जीवन को अस्थिर बना दिया है जो अभी भी खाड़ी में काम कर रहे हैं। पिछले कई वर्षों से, वे भारत के विदेशी मुद्रा रिजर्व को बनाए रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं। महामारी के कारण, उनमें से कई भारत लौटने के लिए मजबूर थे। यह खाड़ी देशों के संबंध में उनके पुनर्वास और उचित नीतिगत पहलों के बारे में तत्काल राजनीतिक हस्तक्षेप की आवश्यकता को रेखांकित करता है जहां अधिकांश भारतीय प्रवासी श्रमिक केंद्रित हैं।

4.13 : 2014 में मोदी सरकार के सत्ता में आने के बाद से, भारत के पड़ोसियों के साथ संबंध लगातार बिगड़ते रहे हैं। नेपाल, भूटान, बांग्लादेश और पाकिस्तान के लिए अपने बड़े भाई के दृष्टिकोण के कारण, सार्क पहले से ही मृतप्राय हो गया है। नेपाल में एक धर्मनिरपेक्ष सरकार के गठन को विफल करने के लिए मोदी शासन का पूर्व प्रयास पहले से ही सब जानते हैं। संयुक्त राष्ट्र के अनुसार सबसे अधिक सताए गए अल्पसंख्यक रोहिंग्या शरणार्थियों के प्रति हिंदुत्ववादियों के रवैये ने बांग्लादेश को अलग थलग कर दिया है। भारत प्रशांत महासागरीय(इंडो-पैसिफिक) क्षेत्र में चीन के खिलाफ रणनीतिक गठबंधन सहित मोदी के विस्तारवादी डिजाइनों ने श्रीलंका और अन्य देशों को चीन के करीब जाने के लिए प्रेरित किया है। और चीन के साथ सीमा के सवाल में, साम्राज्यवादी चीन से निबटने में मोदी सरकार की अक्षमता पहले से ही उजागर है। अमेरिका के एक जूनियर पार्टनर के रूप में भारतीय शासन की भूमिका चीन के साथ अपने अंतर्विरोध को तीखा बना रही है, जो सीमा मुद्दे के किसी भी सौहार्दपूर्ण समाधान में बाधा है।

4.14 : दूसरी ओर, अंतरराष्ट्रीय पूंजी के लिए एक बड़ा बाजार होने के नाते, रूस और अमेरिका के बीच भारत की सौदेबाजी की स्थिति यूक्रेन पर रूसी हमले के लिए अपने दृष्टिकोण में स्वयं स्पष्ट है। ऐतिहासिक और राजनीतिक रूप से यूक्रेन के सवाल पर साम्राज्यवाद-विरोधी स्थिति लेने में असमर्थ, रूसी हथियारों और सस्ते तेल पर भारत सरकार की निर्भरता शुरू से ही खुले रूप से सामने आई है। इसे संतुलित करने के लिए, ...

..... सरकार की ओर से एक सम्पूर्ण प्रयास भी पूरे जोरों पर है, जो कि क्वाड में एक रणनीतिक भागीदार के रूप में और चीन को निशाना बनाते हुए अमेरिका के भारत-प्रशांत महासागरीय क्षेत्र में एक रणनीतिक भागीदार के रूप में टिके रहने के लिए अमेरिका का कोपभाजन नहीं बनने के लिए है।

4.15 : बीते समय की गुट निरपेक्ष परंपराओं को त्यागते हुए, नवफासीवादी मोदी शासन , उत्पीडक राष्ट्रों के साथ खड़े होकर सभी उत्पीड़ित राष्ट्रों और जनता के प्रति विशिष्ट रूप से विरोधी स्थिति ग्रहण कर रहा है। वास्तव में , भारतीय शासन का नेतृत्व करने वाला आरएसएस एक वैश्विक हिंदुत्ववादी अभियान में लगा हुआ है जो मुख्य रूप से अमेरिका में स्थित अपने असंख्य अंतरराष्ट्रीय सहयोगियों के माध्यम से इस्लामोफोबिया का उपयोग करते हुए मुसलमानों के खिलाफ यहूदी नस्लवादियों/ज़ायोनीवादियों के साथ गठबंधन कर रहे हैं। अमेरिका में रिपब्लिकन-यहूदी गठबंधन के बाद तैयार की गई हिंदुत्व-रिपब्लिकन गठबंधन आरएसएस के अंतरराष्ट्रीय कार्यों के अनुरूप नफरत के काम की पैरवी करने में सक्रिय है। संघ परिवार के तार, यूरोप में कई नव-नाजी और नवफासीवादी समूहों और आंदोलनों के साथ एक साथ जुड़े हैं।

5. आरएसएस नवफासीवाद के संदर्भ में हमारे फौरी कार्य।

5.1 : हमारे फौरी कार्य के बारे में, 2018 में 11 वीं पार्टी कांग्रेस में अनुमोदित किए गये राजनीतिक प्रस्ताव में बताया गया है। हमें तत्काल पार्टी बनाने, वर्ग/जन संगठनों और जनआंदोलनों को मजबूत करने और वर्ग संघर्ष को विकसित करने में संलग्न होना होगा। इसके साथ ही, सभी उपलब्ध साधनों का उपयोग करके हमें अपने देश की ठोस स्थिति के अनुसार मार्क्सवाद-लेनिनवाद के विकास की आवश्यकता पर, कॉर्पोरेट-भगवा फासीवाद के खिलाफ साम्राज्यवाद और सत्तारूढ़ प्रणाली के खिलाफ एक दृढ़ वैचारिक-राजनीतिक अभियान चलाना चाहिए। इस पृष्ठभूमि में, हमारी पार्टी को सभी क्रांतिकारी, लोकतांत्रिक ताकतों के साथ चर्चा के लिए सक्रिय रूप से प्रयास करना चाहिए, साथ ही एक राष्ट्रीय समन्वय के लिए अन्य संघर्षरत ताकतों के साथ कॉर्पोरेट सांप्रदायिक फासीवादी खतरे का विरोध करने और उन्हें हराने के लिए एक सामान्य घोषणापत्र का मसौदा तैयार करने की संभावना पर पहल करना चाहिए।

5.2 : मोदी 2 के तहत, और हाल के विधानसभा चुनावों के बाद, जैसा कि ऊपर संक्षेप में विश्लेषण किया गया है, RSS हिंदुराष्ट्र की ओर अंतिम धक्का देने में लगा हुआ है। यह दर्शाता है कि भारत , नवफासीवाद के एक बहुआयामी खतरे का सामना कर रहा है। इस परिवर्तन को स्वीकार करते हुए, 12 वीं कांग्रेस द्वारा अपनाई गई राजनीतिक संगठनात्मक रिपोर्ट इस प्रकार निष्कर्ष निकालती है: "हम फासीवादी आक्रामकता के सबसे खतरनाक दिनों से गुजर रहे हैं। इस चुनौती का सामना करने के लिए, हमें लगातार सभी विजातीय प्रवृत्तियों के खिलाफ वैचारिक संघर्ष को जारी रखना होगा, और फासीवादी मोदी राज के खिलाफ व्यापक संभव एकजुट मोर्चे के निर्माण के लिए प्रयास करना जारी रखना होगा। हमें स्वतंत्र वामपंथी पहल/ दावेदारी के नजरिए को दृढ़ता से लागू करना चाहिए। हमें उन सभी कम्युनिस्टों के साथ पार्टी के निर्माण कार्य में एकजुट होना चाहिए जो पार्टी कार्यक्रम और क्रांति का पथ दस्तावेजों के आधार पर आगे बढ़ने को तैयार हैं। हमें जनता के जनवाद और समाजवाद के कार्यक्रम के आधार पर क्रांतिकारी वामपंथी कोर/नाभिक को बनाने के लिए प्रयास करना चाहिए, जो आने वाले दिनों में क्रांतिकारी संघर्षों को शुरू करने के आवश्यक हैं। इस तरह हम निश्चित रूप से कम्युनिस्ट आंदोलन के वर्तमान ठहराव को दूर कर सकते हैं, आरएसएस के बढ़ते फासीवादी आक्रामकता के खिलाफ लड़ाई को तेज कर सकते हैं, जनवादी क्रांति के शेष कार्यों को पूरा कर सकते हैं और समाजवादी क्रांति के लिए आगे बढ़ सकते हैं।

5.3 : इस प्रकार, जैसा कि उल्लिखित है, "फासीवादी मोदी राज के खिलाफ व्यापक संभव एकजुट मोर्चा का निर्माण" "समझौताहीन वैचारिक संघर्ष" पर आधारित है, "स्वतंत्र वामपंथी पहल की लाइन" पर अमल करते हुए और "सभी कम्युनिस्टों के साथ एकजुट होकर पार्टी निर्माण कार्य" को तेज करने और फासीवाद का विरोध करने और पराजित करने के तत्काल राजनीतिक कार्य आपस में अविभाज्य और परस्पर संपर्कित घटक हैं। हमारी संगठनात्मक कमजोरी के बावजूद, हालांकि एक सीमित रूप में, इस राजनीतिक स्पष्टता पर आधारित होकर हमने यूपी में जो आज कॉरपोरेट-हिंदुत्व फासीवाद की प्रयोगशाला है, " भाजपा हराओ, लोकतंत्र बचाओ " अभियान का संचालन किया।

5.4 : गैर-फासीवादी शासक वर्ग के रंगबिरंगे राजनीतिक दायरे में, उनमें से किसी भी पक्ष या मोर्चों ने अब तक स्पष्ट-फासीवाद विरोधी अवस्थांन ग्रहण नहीं किया है।.....

गैर-भाजपा शासक वर्ग के कांग्रेस सहित अन्य दल जो पहले से ही कमजोर हो गए हैं, और जाति-सांप्रदायिक रुझान के साथ राज्य-स्तरीय और क्षेत्रीय दलों, नवउदारवादी निगमीकरण के अपने करीबी संबंध के साथ, मुख्य रूप से अब तक के सत्ता में हिस्सेदारी करने के लिए अवसरवादी गठबंधन बनाने में रुचि रखते हैं। यद्यपि उनमें से कुछ अपनी वर्गीय अवस्थान और वैचारिक-राजनीतिक दिवालियापन के कारण सबसे भ्रष्ट, बहुसंख्यक, भगवा फासीवादी खतरे के खिलाफ लोगों की नाराजगी का उपयोग कर सकते हैं लेकिन उनमें से किसी ने भी अब तक नवफासीवाद से लड़ने में पहल नहीं की है।

5.5 : अब वामपंथी दायरे के बारे में , जैसा कि कई बार साबित हुआ है ,वामपंथी दुस्साहसवादी राजनीतिक लाइन द्वारा फासीवाद विरोधी मैदान में खेलने की भूमिका बहुत कम है। वामपंथी दुस्साहसवाद शासक वर्गों के फासीवादी और गैर-फासीवादी तबकों के बीच अंतर नहीं करते हैं, और इस संकीर्णतावादी दृष्टिकोण के कारण, नवफासीवाद का सत्तासीन होना उनके लिए शासन का मात्र एक परिवर्तन है। दूसरी ओर, सामाजिक जनवादी धारा का नेतृत्व करने वाले सीपीआई (एम) ने वर्तमान भारतीय शासन को फासीवादी के रूप में स्वीकार नहीं किया है। जाहिर है, सरकार में रहने के दौरान नवउदारवादी निगमीकरण के पैरोकार होने के नाते, सीपीआई (एम) ने पहले से ही खुद को कॉर्पोरेट पूंजी जो फासीवाद का भौतिक आधार है के खिलाफ प्रमुख राजनीतिक संघर्षों में नेतृत्व प्रदान करने में खुद को अक्षम साबित किया है। सिंगुर और नंदीग्राम के बाद, बंगाल और त्रिपुरा में घोर कॉरपोरेटपरस्त नीतियों के चलते सीपीआई (एम) का पतन हो गया है। कोर पोरेटपरस्त नीतियों वाली इसकी वर्तमान नीति और उसकी नीतियों का विरोध करने वाली जनता के निर्मम दमन , जैसे केरल में यूएपीए जैसे फासीवादी हथियारों का उपयोग जनता के खिलाफ किया जाना आदि के कारण , इसका श्रमिक वर्ग और उत्पीड़ितों से अलगाव बढ़ रहा है।

5.6 : इसी समय, यह एक महत्वपूर्ण स्थिति है जहां एक कम्युनिस्ट आंदोलन जो राजनीतिक और संगठनात्मक रूप से सभी गैर-फासीवादी, धर्मनिरपेक्ष, लोकतांत्रिक और प्रगतिशील ताकतों को एकजुट करने वाले फासीवाद विरोधी आंदोलन का नेतृत्व करने में सक्षम है, अभी तक उभरना बाकी है। हालांकि, इस तथ्य की मात्र स्वीकार्यता आरएसएस नवफासीवाद को हराने के लिए एक फासीवाद-विरोधी आंदोलन के निर्माण के तत्काल और तत्काल कार्य से परहेज करने का औचित्य नहीं होगा। यह एक जटिल कार्य है जो विभिन्न स्तरों पर हमारी परस्पर संबंधित भागीदारी के लिए मांग करता है।

5.7 : बेशक, जैसा कि हमारे बुनियादी दस्तावेजों में रखा गया है, हमें पार्टी-निर्माण को गति देना है, वर्ग संघर्ष और बड़े पैमाने पर आंदोलनों को विकसित करना है, और हमारी वैचारिक-राजनीतिक लाइन के आधार पर सत्तारूढ़ व्यवस्था और धुर दक्षिण पंथी नवउदारवादी नीतियों के खिलाफ लोगों जनसंघर्षों को छेड़ना है। नवउदारवादी साम्राज्यवाद की ठोस अभिव्यक्तियों के अनुसार, पार्टी निर्माण के इस कार्य के दो घटक हैं- अंतर्राष्ट्रीय और देश विशिष्ट। पहले के बारे में अंतरराष्ट्रीय कार्यों के अध्याय में पहले से ही उल्लेख किया गया है।

5.8 : देश-व्यापी प्रभाव रखने वाली पार्टी के निर्माण में और ठोस भारतीय संदर्भ में जनवादी और क्रांतिकारी संघर्षों में नेतृत्व स्थापित करने के लिए, अतीत के जनवादी और समाजवादी अनुभवों से सबक को आत्मसात करते हुए, वर्ग, जाति और लैंगिक संघर्षों के बीच अभिन्न जुड़ाव स्थापित करते हुए और पारिस्थितिक संरक्षण के लिए संघर्ष को छेड़ा जाना चाहिए। यही है, पार्टी निर्माण प्रक्रिया जो कि वर्ग संघर्ष और जाति के विनाश के लिए संघर्ष, लैंगिक समानता के लिए और पारिस्थितिक संरक्षण के लिए संघर्ष के बीच अंतरसंबंध को सम्यक रूप से आत्मसात करने की मांग करता है। इस प्रकार एक पार्टी जो क्रांतिकारी सिद्धांत से लैस है और श्रमिकों, किसानों, और महिलाओं सहित सभी उत्पीड़ितों और लैंगिक समुदाय, आदिवासियों और दलितों के पूरे तबकों सहित पर्यावरण संरक्षण के लिए लड़ने में सक्षम हो कि आज तत्काल आवश्यकता है।

5.9 : श्रमिकों और सभी उत्पीड़ितों द्वारा अपनी सभी अभिव्यक्तियों में नवउदारवादी-निगमीकरण के खिलाफ संघर्ष के माध्यम से हासिल की गई इस प्रकार की एक एकता, एक सामान्य न्यूनतम कार्यक्रम के साथ सभी बिरादराना और कम्युनिस्ट क्रांतिकारी ताकतों को क्रांतिकारी वामपंथी कोर के दायरे में लाने के लिए भी अपरिहार्य है। यह नींव जो मेहनतकशों और उत्पीड़ित लोगों के विशाल बहुमत के हितों के लिए लडेगी, आरएसएस के नेतृत्व वाले नवफासीवाद को चुनौती देने और पराजित करने में सक्षम एक व्यापक संभव फासीवाद विरोधी मोर्चा के लिए प्रस्थान बिंदु होगा।

5.10 : बहरहाल, आज के भारत के मौजूदा नवफासीवाद के संदर्भ में हकीकत ये है कि फासीवाद, संगठन बनाने,सभा करने, बोलने की आजादी जैसे न्यूनतम राजनैतिक अधिकार को भी सहन नहीं करेगा।

इसलिए फासीवाद के तहत, पार्टी और क्रांतिकारी वामपंथी कोर के निर्माण का कार्य और फासीवाद विरोधी आंदोलन को, "पहले एक बाद में दूसरा" के क्रम में नहीं रखा जा सकता है। बल्कि, दोनों कार्य अंतर-निर्भर हैं और इसे द्वंद्वात्मक रूप से देखने की आवश्यकता है, और यह फासीवाद के खिलाफ दृढ़ संघर्ष ही है जो प्रगतिशील और जनवादी ताकतों को अपने पक्ष में लाकर पार्टी के निर्माण के लिए मंच तैयार करता है ।जो एक बड़े पैमाने पर फासीवाद विरोधी आंदोलन में शामिल होंगे। और यहां तक कि कम्युनिस्ट आंदोलन में वर्तमान ठहराव पर काबू पाने और जनवादी और क्रांतिकारी कार्यों की दिशा में आगे बढ़ने के लिए, फासीवाद विरोधी आंदोलन का निर्माण अपरिहार्य है।

5.11 : फासीवादी संदर्भ में दोहराए जाने के लिए, वर्ग संघर्ष और फासीवाद विरोधी संघर्ष दोनों परस्पर जुड़े और अविभाज्य हैं। उदाहरण के लिए, दोनों के तत्व सीएए विरोधी आंदोलन और ऐतिहासिक किसानों के आंदोलन में शामिल थे।जो कि हिंदुत्व फासीवाद और नवउदारवादी निगमीकरण के खिलाफ संचालित था। यह अनुभव तमाम फासीवाद-विरोधी और गैर-फासीवादी तबकों के साथ जुड़ कर भगवा-कॉर्पोरेट फासीवाद के खिलाफ निरंतर और समझौताहीन संघर्ष विकसित करने के लिए पर्याप्त गुंजाइश प्रदान करता है।

5.12 : जनता के इस तरह के प्रतिरोध संघर्षों में संलग्न होने के दौरान, कॉर्पोरेट-नवफासीवाद के खिलाफ जन विकल्प का निर्माण करने के लिए जागरूक राजनीतिक हस्तक्षेप की आवश्यकता होती है। कई विविधता वाले भारत जैसे विशाल देश में, इस तरह की पहल राज्य-स्तरीय समन्वय के रूप में क्रांतिकारी वामपंथी, जनवादी और संघर्षरत ताकतों के साथ जुड़ सकती है, जिससे एक फासीवाद विरोधी आम एजेंडे पर आधारित कॉर्पोरेट-हिंदुत्व फासीवाद के खिलाफ एक राष्ट्रीय समन्वय का गठन हो सकता है। जिसमें आरएसएस नव फासीवाद को अलग थलग कर पराजित करने के लिए चुनावी संघर्ष भी शामिल है। यहाँ महत्वपूर्ण प्रासंगिकता, मनुवादी-हिंदुत्व के खिलाफ समूचित वैचारिक-राजनीतिक हस्तक्षेप करना है, जो कि भारतीय फासीवाद का वैचारिक आधार है।

5.13 : कम्युनिस्टों को इस तरह के व्यापक फासीवाद विरोधी आंदोलन का हिस्सा होने के साथ-साथ, जिसमें गैर-फासीवादी शासक वर्गों के अलावा सामाजिक जनवादी, जो भारत में फासीवाद के आगमन को भी स्वीकार नहीं करते हैं, शामिल रहेंगे , कम्युनिस्टों की ओर से कोई भी शिथिलता नहीं होनी चाहिए ताकि वे मजदूर वर्ग उत्पीड़ित वर्ग के वर्ग हितों के परिप्रेक्ष्य से अपनी वैचारिक स्थिति को अथक रूप से ऊंचा उठाए रखें ।

अर्थात्, फासीवाद विरोधी संघर्ष में "रणकौशलिय गठबंधन", जिसका उद्देश्य शासक वर्गों के भीतर अंतर्विरोधों का प्रभावी ढंग से उपयोग करना है, को मजदूर और उत्पीड़ित वर्ग के 'रणनीतिक गठबंधन' से अलग किया जाएगा जो आज की शासनव्यवस्था के खिलाफ, नवउदारवाद और कॉर्पोरेट पूंजी के खिलाफ किया जाएगा। अन्यथा, फासीवाद विरोधी एकता के नाम पर बना अवसरवादी गठबंधन सर्वहारा की आजादी और कम्युनिस्टों की वैचारिक-राजनीतिक लाइन के आत्मसमर्पण के परिणामस्वरूप वर्ग संघर्ष को पूरी तरह से त्याग दिया जाएगा और यह श्रमिक वर्ग और उत्पीड़ितों के हितों के लिए विनाशकारी होगा।

5.14 : इस स्पष्ट अवधारणा के साथ, वर्ग संघर्ष के बुनियादी कार्यभार के साथ आगे बढ़ते हुए जिसमे एक क्रांतिकारी वाम कोर (नाभिक) के लिए प्रयास करना शामिल है। इस वाम कोर के लिए पार्टी, वर्ग - जन संगठनों और जनआंदोलनों के निर्माण के प्रयास से , वर्ग संघर्ष के मूल कार्यों के साथ आगे बढ़ते हुए, हमें तमाम फासीवाद विरोधी ताकतों को जोड़कर ,एक व्यापक संभव फासीवाद विरोधी मोर्चा गठन के जरिए आरएसएस नवफासीवाद को उखाड़ फेंकने के तत्कालिक कार्य में जिसमें चुनावी संघर्ष भी शामिल है, खुद को सक्रिय करना होगा। इस परस्पर संबंधित कार्य में संलग्न होने के दौरान, कम्युनिस्टों को स्वतंत्र दावेदारी को बनाए रखने के लिए समझौताहीन वैचारिक संघर्ष करना पडेगा जो हमेशा मेहनतकश और सभी उत्पीड़ितों के साथ अपनी पहचान करता है। केवल इस तरह का एक दृष्टिकोण संकीर्णतावाद और अवसरवादी भटकाव दोनों से बच सकता है।

मनुवादी-हिंदुत्व फासीवाद का प्रतिरोध करें!

फासीवाद विरोधी आंदोलन का निर्माण करें!

सर्वहारा अंतर्राष्ट्रीयता पर आधारित पार्टी का निर्माण करें!

साम्राज्यवादी छाया युद्ध और जंगखोरी के खिलाफ लड़ाई करें!

जनता के जनवाद और समाजवाद की ओर आगे बढ़ें!

भारत एक धर्मनिरपेक्ष देश नहीं रह गया क्योंकि मोदी सरकार ने पिछले दरवाजे से सीएए लागू करना शुरू कर दिया है?

तीन देशों (पाकिस्तान, अफगानिस्तान और बांग्लादेश) से केवल छह गैर-मुस्लिम वर्गों - हिंदू, सिख, पारसी, ईसाई, बौद्ध और जैन - के लिए भारतीय नागरिकता का मार्ग खोलकर, मोदी सत्ता ने मुसलमानों को इससे पूरी तरह बाहर करते हुए सीएए को लागू करना शुरू कर दिया है। इसी तरह, संयुक्त राष्ट्र के अनुसार, "सबसे अधिक उत्पीड़ित अल्पसंख्यक" रोहिंग्या सहित मुस्लिम शरणार्थियों की पहचान करने और उन्हें बाहर, मुख्य रूप से बांग्लादेश भेजने के लिए जोर-शोर से कदम उठाए जा रहे हैं।

हालांकि सरकार नागरिकता नियमों के 2015 के संशोधन के संदर्भ में यह कदम उठाने का दावा कर रही है, जिसने प्रवासियों के निवास करने को वैधता दी और उन्हें पासपोर्ट अधिनियम और विदेशी अधिनियम के प्रावधानों से उनके पासपोर्ट की समाप्ति के बाद भी छूट दी, वास्तव में यह सीएए (2019) के आंशिक कार्यान्वयन के समान है, जिसका उद्देश्य विशेष रूप से अवैध या गैर-दस्तावेज वाले 6 गैर-मुस्लिम समुदायों को नागरिकता प्रदान करना है।

इस प्रकार, सीएए के खिलाफ किसी भी क्षण भड़क सकने वाले लोगों के सुलगते असंतोष को देखते हुए, एक ओर यह दावा किया जा रहा है कि सीएए अभी तक लागू नहीं हुआ है, जबकि दूसरी ओर मोदी सरकार ने 2015 के नागरिकता संशोधन नियमों की आड़ में इसमें तेजी लाना शुरू कर दिया है। बेशक, इस जघन्य कदम को आरएसएस-बीजेपी के हिंदूराष्ट्र के अपने अंतिम लक्ष्य की ओर बढ़ने के हिस्से के रूप में, तथा हाल के दिनों में शुरू किए गए मुस्लिम अल्पसंख्यकों को निशाना बनाने वाले हिंदुत्ववादी हमलों की श्रृंखला के साथ समझा चाहिए।

भाकपा (माले) रेड स्टार पिछले दरवाजे से सीएए को लागू करने की कड़ी निंदा करती है, और प्रगतिशील-लोकतांत्रिक ताकतों, मेहनतकश लोगों और सभी उत्पीड़ितों से आह्वान करती है कि वे भारत के धर्मनिरपेक्ष चरित्र को पूरी तरह कमजोर करने वाले इस नवफासीवादी कदम का विरोध करें और उसे हराएं।

पी जे जेम्स, महासचिव, भाकपा (माले) रेड स्टार - *20/12/2022*

हाल के उपचुनाव व विधानसभा चुनाव और आरएसएस का मजबूत होता नवफासीवाद

इस प्रकार, सीएए के खिलाफ किसी भी क्षण भड़क सकने वाले लोगों के सुलगते असंतोष को देखते हुए, एक ओर यह दावा किया जा रहा है कि सीएए अभी तक लागू नहीं हुआ है, जबकि दूसरी ओर मोदी सरकार ने 2015 के नागरिकता संशोधन नियमों की आड़ में इसमें तेजी लाना शुरू कर दिया है। बेशक, इस जघन्य कदम को आरएसएस-बीजेपी के हिंदूराष्ट्र के अपने अंतिम लक्ष्य की ओर बढ़ने के हिस्से के रूप में, तथा हाल के दिनों में शुरू किए गए मुस्लिम अल्पसंख्यकों को निशाना बनाने वाले हिंदुत्ववादी हमलों की श्रृंखला के साथ समझा चाहिए।

भाकपा (माले) रेड स्टार पिछले दरवाजे से सीएए को लागू करने की कड़ी निंदा करती है, और प्रगतिशील-लोकतांत्रिक ताकतों, मेहनतकश लोगों और सभी उत्पीड़ितों से आह्वान करती है कि वे भारत के धर्मनिरपेक्ष चरित्र को पूरी तरह कमजोर करने वाले इस नवफासीवादी कदम का विरोध करें और उसे हराएं।

दूसरी ओर, 2022 का गुजरात चुनाव कांग्रेस के सम्पूर्ण इतिहास में सबसे बड़ी गिरावट का गवाह बना; 2017 की 77 सीटों पर जीत के मुकाबले 2022 में भारी गिरावट के साथ कांग्रेस केवल 16 सीटों पर ही सिमट गयी और उसके वोट प्रतिशत में भी 14 प्रतिशत से ज़्यादा की गिरावट दर्ज की गयी। यहां आम आदमी पार्टी का हिंदुत्व के प्रति 'राजा से भी ज़्यादा वफादार' रवैय्या, और उसका समान नागरिक संहिता, लक्ष्मी और गणेश के चित्र नोटों पर छापने, सरकार प्रायोजित हिन्दू मंदिरों की मुफ्त तीर्थयात्रा आदि मांगों के साथ मैदान में उतरना उन निर्णायक कारकों में से एक रहा जिसने मुस्लिम अल्पसंख्यक को अलग-थलग कर दिया और बहुसंख्यक हिंदुत्व मतों का संघटन किया। इस तरह गुजारत के सम्पूर्ण मुस्लिम बहुल इलाकों में भाजपा और आप के शक्तिशाली हिंदुत्व अभियान ने नर्म हिंदुत्व वाली कांग्रेस को लगभग रोक दिया और भाजपा के लिये अधिकतम लाभ कमाने का रास्ता साफ कर दिया। इस प्रक्रिया में आप ने अपना वोट शेयर 12 प्रतिशत से ज़्यादा की वृद्धि की और इस तरह गुजरात में कांग्रेस की सबसे बड़ी हार हुई।

मुस्लिम बहुल क्षेत्रों के साथ-साथ आदिवासी क्षेत्रों में आप के मजबूत अभियानों ने कांग्रेस को किनारे लगाते हुए गुजरात में 27 अनुसूचित जनजाति सीटों में से 23 सीटें जीतने में भी भाजपा की मदद की। कुल मिलाकर, हिंदुत्व जुड़वाँ, भाजपा और आप द्वारा फैलाए गए शातिर सांप्रदायिक ध्रुवीकरण के परिणामस्वरूप भाजपा बहुसंख्यक मतों का संघटन कर सकी, और इससे आप को भी एक राष्ट्रीय पार्टी के रूप में उभरने में मदद मिली।

हालांकि, गुजरात में लगभग 10 प्रतिशत मुस्लिमों के खिलाफ किया गया सांप्रदायिक ध्रुवीकरण हिमाचल प्रदेश में व्यावहारिक नहीं था जहाँ उनका प्रतिशत केवल 2 प्रतिशत के आसपास था। इस वस्तुनिष्ठ स्थिति में हिमाचल प्रदेश में जहां एक आक्रामक और ध्रुवीकरण वाले गुजरात मॉडल अभियान की सीमित गुंजाइश थी, वहां दोनों भगवा दल, भाजपा और आप हिमाचल भाजपा अध्यक्ष नड्डा का गृह राज्य होने के बावजूद हिंदुत्व के सम्बन्ध में एक हल्का प्रोफाइल रखने के लिए मजबूर हुये। इस प्रकार, आप के हिमाचल से लगभग अपना ध्यान हटाने और आरएसएस-बीजेपी नेतृत्व द्वारा फैलाई गयी गुजरात जैसी सांप्रदायिक ध्रुवीकरण की अनुपस्थिति ने कांग्रेस को भाजपा के खिलाफ सत्ता विरोधी कारक का लाभ उठाने में सक्षम बनाया। उन्होंने सेब किसानों की समस्याओं, सेना में भर्ती के लिये लाई गयी अग्निपथ योजना की दिक्कतों को उजागर किया और साथ ही सरकारी कर्मचारियों की पुरानी पेंशन योजना आदि की बहाली का आश्वासन भी दिया। परिणाम यह हुआ कि चुनाव में भले ही कांग्रेस जीत गई, लेकिन फिर भी कांग्रेस और भाजपा के वोट प्रतिशत का अंतर एक प्रतिशत से भी कम रहा, जो राज्य में हिंदुत्व की प्रबल अंतर्धारा को दर्शाता है।

इस बीच, हिंदुत्व फासीवाद के असली रंग की ठोस अभिव्यक्ति यूपी के रामपुर विधानसभा क्षेत्र में हुई, जहां समाजवादी पार्टी के नेता आजम खान और उनके सहयोगी पिछले दो दशकों से लगातार जीतते रहे हैं। समाजवादी पार्टी के इस गढ़ में, जहां मुस्लिम मतदाता अपेक्षाकृत ज्यादा हैं, वहां भाजपा पहली बार जीती है. जैसा कि यूपी में हाल के उपचुनावों में मतदान औसत 55 प्रतिशत था, रामपुर में यह केवल 33.94 प्रतिशत था, जबकि 2019 के चुनावों में यह 56.61 प्रतिशत दर्ज किया गया था। मौजूदा रिपोर्टों के मुताबिक, जिसे कारपोरेट-भगवा मीडिया शायद ही कभी तरजीह देता है, जब पूरे राज्य की चुनाव मशीनरी फासीवादी शासन में विलय हो रही थी, पुलिस और प्रशासन ने मुस्लिम-बहुल क्षेत्रों में मतदाताओं को अपने मताधिकार का प्रयोग करने से रोकने के लिए हर तरह के हथकंडों का इस्तेमाल किया, और दूसरी ओर हिंदुत्व मतों के संघटन को और सुगम बनाया। यह आगामी चुनावों के लिये आरएसएस फासीवादियों की ओर से किया गया एक पूर्वाभ्यास भी हो सकता है।

विधानसभा और उपचुनावों के साथ ही उत्तर वैचारिक, शहरी मध्यम वर्ग उन्मुख आप की दिल्ली निगम में जीत भी हिंदुत्व शिविर की जीत है. दिल्ली एमसीडी में आप की जीत के साथ-साथ भाजपा के वोट शेयर में 2017 के 36 प्रतिशत से 2022 में 39 प्रतिशत की वृद्धि भी फासीवादी ताकतों के आगे बढ़ने का एक प्रतिबिंब है। जाहिर है, आप की भ्रष्टाचार-विरोधी छवि होने के बावजूद, वह अल्पसंख्यकों और दलितों के प्रति अपने दृष्टिकोण में भाजपा जैसी समानता रखती है, जो ईडब्ल्यूएस, अनुच्छेद 370, सीएए और एनआरसी रद्द करने, समान नागरिक संहिता, आदि के मामले में प्रकट हुआ। अब आप दुनिया के सबसे बड़े और सबसे लंबे समय तक चलने वाले फासीवादी संगठन आरएसएस के एक अन्य राजनीतिक हथियार के रूप में भाजपा के साथ प्रतिस्पर्धा कर रही है। बेशक, भाजपा, 18 करोड़ सदस्यता वाली सबसे बड़ी राजनीतिक पार्टी है और भारत में अन्य सबसे बड़े सात राजनीतिक दलों की संयुक्त संपत्ति से भी ज़्यादा संचित संपत्ति रखने वाली यह पार्टी, आरएसएस का चर्चित राजनीतिक हथियार है। साथ ही, जैसा कि इसके नेतृत्व ने दावा किया है, आरएसएस किसी भी पार्टी को अपने राजनीतिक हथियार के रूप में इस्तेमाल कर सकता है और इस लिहाज से हाल के चुनावों में आप की भूमिका पूरी तरह से आरएसएस के इस एजेंडे के अनुरूप है।

संक्षेप में कहें तो, हाल ही में हुए विधानसभा और उपचुनावों के दौरान ईंधन और आवश्यक वस्तुओं की आसमान छूती कीमतें, अभूतपूर्व बेरोजगारी, तीव्र होती गरीबी और विनाश, भ्रष्टाचार, जीवन स्तर में गिरावट, कृषि क्षेत्र में संकट, बची-खुची सार्वजनिक क्षेत्रों की बिक्री, राष्ट्रीय संपत्तियों को अरबपतियों द्वारा हड़पना,प्रकृति की बढ़ती कॉर्पोरेट लूट, फलतः पारिस्थितिकी की तबाही, लोकतांत्रिक अधिकारों को खत्म करना, बर्बर यूएपीए को लागू करना और राजनीतिक विरोधियों पर देशद्रोह के आरोप लगाना, आदि इस चुनाव में मुख्य मुद्दे थे। उदाहरण के तौर पर, गुजरात में कॉरपोरेट मीडिया ने मोदी को ऐसे व्यक्ति के रूप में पेश किया जो "मजबूत निर्णय ले सकता है", उसने भाजपा को "दृढ़ और कठिन निर्णय लेने के लिए दृढ़ विश्वास और साहस" वाली पार्टी के रूप में पेश किया और इस तरह उसने वास्तविक मुद्दों को दरकिनार करते हुये चुनाव को "लोकतंत्र के त्योहार" के रूप में देखने और उसका जश्न मनाने की ओर मोड़ दिया।

निस्संदेह, आने वाले दिनों में और 2024 के आम चुनाव को देखते हुए, कॉर्पोरेट अरबपतियों और उनके भगवा मीडिया प्रबंधकों के समर्थन के साथ, फासीवादी ताकतें निश्चित रूप से हिंदुत्व चालों, जो पहले से ही आगे बढ़ रही हैं, की श्रृंखला का सहारा लेकर चौतरफा हमले के तीव्र चरण में प्रवेश करेगी और इस तरह छद्म राष्ट्रवाद को बढ़ावा देते हुए, धर्म के आधार पर लोगों के बीच नफरत फैलाएगी, विविधताओं की घोर अवहेलना करेगी, और सभी प्रकार की विभाजनकारी ताकतों पर से लगाम छोड़ देगी।

हालाँकि, जैसा कि चुनाव परिणामों ने दिखाया है, कांग्रेस सहित शासक वर्ग की पार्टियाँ रक्षात्मक हो गयी हैं और आरएसएस के नव-फासीवाद के खिलाफ राजनीतिक आक्रमण करने में असमर्थ हैं। इसलिए, जैसा कि भाकपा (माले) रेड स्टार की 12वीं कांग्रेस द्वारा अपनाए गए राजनीतिक प्रस्ताव में स्पष्ट रूप से रेखांकित किया गया है, कि मजदूर वर्ग और सभी उत्पीड़ितों के वर्ग हितों को ऊँचा उठाकर और साथ ही, आरएसएस की विचारधारा मनुवादी-हिंदुत्व का पर्दाफाश करते हुए, क्रांतिकारी-लोकतांत्रिक ताकतों को सभी समान विचारधारा वाली ताकतों के साथ एकजुट होकर, गैर-फासीवादी वर्गों के साथ जुड़कर, राज्यों की ठोस स्थिति के अनुसार हरसंभव सबसे व्यापक फासीवाद-विरोधी मोर्चा बनाने के लिए आगे आना होगा।

पी जे जेम्स, महासचिव, भाकपा (माले) रेड स्टार

गृह मंत्रियों का 'चिंतन शिविर' : हिंदुत्व-फासीवादी एजेंडा को आगे बढ़ाने के लिए एक कदम और

केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की अध्यक्षता में 27 और 28 अक्टूबर को फरीदाबाद में राज्यों के गृह मंत्रियों का दो दिवसीय 'चिंतन शिविर' (विचार-मंथन सत्र) जिसे मोदी ने अंतिम दिन वीडियोकांफ्रेंसिंग के माध्यम से संबोधित किया था, यह भगवा-फासीवादी एजेंडा को आगे बढ़ाने की दिशा में एक और कदम है। यद्यपि इस तथाकथित चिंतन शिविर का घोषित उद्देश्य राष्ट्रीय महत्व से संबंधित नीति के बेहतर नियोजन, समन्वय और कार्यान्वयन के लिए एक मंच का निर्माण करना था, जिसे "मोदी की टीम इंडिया" कहा जाता है, लेकिन असल उद्देश्य तो संविधान की सातवीं अनुसूची के तहत राज्य सूची के प्रावधानों का उल्लंघन करते हुए संघीय पुलिस व्यवस्था के खिलाफ राज्यों पर अखिल भारतीय पुलिसिंग थोपने की परिकल्पना को साकार बनाना था। चिंतन शिविर के निर्णयों में फासीवादी, एकात्मक हिंदुराष्ट्र के लक्ष्य को पूरा करने की दिशा में मोदी द्वारा पहले से लाए गए एन आई ए और यूएपीए अधिनियमों में कठोर संशोधनों के अलावा उन्हें और ज्यादा निरंकुश व आक्रामक बनाना शामिल था ।

आश्चर्यजनक रूप से, पंजाब और केरल के मुख्यमंत्रियों को छोड़कर, विपक्षी शासित राज्यों के सभी मुख्यमंत्री, जैसे कि बंगाल, बिहार, ओडिशा, राजस्थान और तमिलनाडु के मुख्यमंत्री जिनके पास गृह विभाग भी हैं, इस कार्यक्रम में शामिल नहीं हुए। पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान की उपस्थिति आश्चर्यजनक नहीं थी, क्योंकि आप द्वारा स्वयं को भाजपा की तुलना में हिंदुत्व के एजेंडे के प्रति अधिक प्रतिबद्ध साबित करने का प्रयास किया जा रहा है।

उसी तरह, सीपीआई (एम) के मुख्यमंत्री पिनारायी विजयन के पहले कार्यकाल के दौरान, केरल में 145 यूएपीए मामले दर्ज किए गए थे। और यह इस स्थिति के अनुरूप है जो केरल में अब भी बिना किसी रुकावट के जारी है, केरल के सीएम, जिनके पास गृह विभाग है, ने राज्यों के गृह मंत्रियों की बैठक में भाग लिया, जिसमें यूएपीए की प्रशंसा की गई।

चिंतन शिविर के केंद्रीय विषय पर आते हुए, केंद्रीय गृह मंत्री शाह ने कानून और व्यवस्था पर एक समान अखिल भारतीय नीति के साथ "एक डेटा, एक प्रविष्टि" के सिद्धांत के आधार पर 2024 तक प्रत्येक राज्य में एक एनआईए कार्यालय बनाने का आह्वान किया। इसी तारतम्य में मोदी ने 'एक राष्ट्र, एक पुलिस वर्दी' का प्रस्ताव रखा और "आतंक के खिलाफ लड़ने के लिए प्रोत्साहन" प्रदान करने के लिए यूएपीए की प्रशंसा की। यूएपीए पर मोदी का यह बयान ऐसे समय में आया है जब सुप्रीम कोर्ट उस याचिका की जांच कर रहा है जिसमें यूएपीए कानून की वैधता को ही चुनौती दी गई है। केवल 2018-20 के दौरान, जब यूएपीए के तहत 4690 लोगों को गिरफ्तार किया गया था, केवल 3 प्रतिशत को ही दोषी ठहराया गया था। यह यूएपीए के कठोर सारवस्तु का प्रमाण है जो राज्य को बिना किसी जवाबदेही के बेलगाम शक्ति देता है, अपने राजनीतिक विरोधियों, असंतुष्टों और अलग या असहमत लोगों को जेल में डालने और प्रताड़ित करने के लिए।

वीडियो कांफ्रेंसिंग के माध्यम से मोदी का भाषण, जिसमें "बंदूक" और "पेन" के माध्यम से सरकार के विरोध की व्याख्या समान रूप से की गई थी।

स्वतंत्र राय और स्वतंत्र अभिव्यक्ति पर 'देशद्रोही' और 'राष्ट्र-विरोधी' के रूप में मुहर लगाने के उनके फासीवादी इरादों को प्रकट करता है।

कई कानूनी और संवैधानिक विशेषज्ञ, मानवाधिकार कार्यकर्ता और जागरूक नागरिक पहले ही बता चुके हैं कि कैसे एनआईए भारतीय संविधान का उल्लंघन है। यह राज्य सरकारों के संघीय अधिकारों को छीन लेता है और भारतीय साक्ष्य अधिनियम और आपराधिक प्रक्रिया संहिता की प्रक्रियाओं के खिलाफ है। यह न्यायिक प्रणाली को मात्र एक दर्शक बनाता है और जिला सत्र न्यायालयों की अनदेखी करते हुए विशेष न्यायालयों की स्थापना कर सकता है।

संक्षेप में, चिंतन शिविर और उसके विचार संसदीय लोकतंत्र के सभी संस्थानों के खिलाफ हैं। यह अनुच्छेद 370 को निरस्त करने और कश्मीर को टुकड़ों में तोड़ने, और भारतीय संघ में इसके जबरन एकीकरण, उसी स्थान पर राम मंदिर का निर्माण, जहां बाबरी मस्जिद स्थित थी, की निरंतरता में सीएए और अन्य कदमों के माध्यम से मुसलमानों को द्वितीय श्रेणी के नागरिक बनाना और एनईपी -20 के माध्यम से भारतीय शिक्षा का कॉरपोरेटकरण व भगवाकरण करने के व्यापक फासीवादी एजेंडा का हिस्सा है। यह बहु-सांस्कृतिक, बहुभाषी, बहु-जातीय और बहु-धार्मिक भारत पर बहुसंख्यक हिंदुराष्ट्र को थोपने की दिशा में उठाए जा रहे बहुआयामी कदमों से जुड़ा हुआ है।

हम सभी जनवादी ताकतों से आह्वान करते हैं कि वे मोदी शासन की ओर से किए जा रहे इस नवीनतम फासीवादी हमले के खिलाफ आगे आएं और जल्द से जल्द उसे इस जघन्य कदम से पीछे हटने के लिए मजबूर करें।

*31*अक्टूबर *2022*

पी जे जेम्स, महासचिव, भाकपा (माले) रेड स्टार

'पाकिस्तान-मूल' के ऋषि सुनक को भारत के हिंदुत्ववादियों द्वारा अपनाने पर

ऋषि सुनक, ब्रिटेन के नए प्रधानमंत्री बने हैं। इनका जन्म 12 मई 1980 को साउथेम्प्टन, यूके में अफ्रीकी मूल के माता-पिता के यहाँ हुआ था। वे जन्म से एक ब्रिटिश नागरिक हैं। जबकि भारत में भगवा गिरोह, सुनक द्वारा भगवद गीता के आधार पर लिए शपथ के साथ उनके भारतीय वंश का पता लगाकर उन पर दावा ठोक रहे हैं। लेकिन उपलब्ध रिकॉर्ड इस दावे की पुष्टि नहीं करते हैं। क्योंकि, ऋषि सुनक के दादा-दादी का जन्म आधुनिक पाकिस्तान के पंजाब प्रांत के एक शहर गुजरांवाला में हुआ था, जहां से वे 1930 के दशक में नैरोबी चले गए थे। दूसरी ओर, उनके नाना तांगानिका, आधुनिक तंजानिया से थे। सुनक के पिता का जन्म 1949 में नैरोबी में और माता का जन्म तंजानिया में हुआ था। दोनों के परिवार 1960 के दशक में इंग्लैंड आ गए थे। इसलिए, भारतीय मूल के सुनक के हिंदुत्व के दावों के विपरीत, उनकी पुश्तैनी जड़ें पूरी तरह से अफ्रीका और आंशिक रूप से आधुनिक पाकिस्तान से संबंधित हैं।

जाहिर है, सुनक के हिंदुत्व पर अपना दावा ठोकना आरएसएस के प्रतिक्रियावादी "सांस्कृतिक राष्ट्रवाद" के अनुरूप है, जिसके अनुसार धर्म को राष्ट्रीयता और नागरिकता का मानदंड होना चाहिए और यह इस रूढ़िवादी पूर्वानुमान पर आधारित है जो बुर्जुआ लोकतंत्र और जागरण और आधुनिकता' के मूल आदर्शों के भी खिलाफ है।

दूसरी ओर, ब्रिटेन में बढ़ते अप्रवासी नव-नाजी प्रवृत्तियों के बावजूद, ब्रिटिश प्रधान मंत्री के रूप में सुनक की नियुक्ति इस बात का प्रमाण है कि अब भी सर्वोच्च पद सभी धर्मों और जातीय पृष्ठभूमि के लोगों के लिए खुला हो सकता है। इस संदर्भ में, आम चुनाव के माध्यम से अमेरिकी राष्ट्रपति पद के लिए प्रत्यक्ष अफ्रीकी मूल के ओबामा का उदय, सुनक की तुलना में तुलनात्मक रूप से एक सराहनीय उदाहरण था। बेशक, उन्हें ब्रिटेन के पहले गैर-श्वेत पीएम के रूप में माना जा सकता है।

साथ ही, सुनक पर संघी फासिस्ट ताकतों का दावा पूरी तरह से अंतरराष्ट्रीय कॉर्पोरेट पूंजी के आगे उनकी लार टपकाने वाली दासता के अनुरूप है।

क्योंकि, सनक पूरी तरह से कॉर्पोरेट समर्थक, धुरदक्षिणपंथी नवउदारवादी और एक प्रतिबद्ध ब्रेक्सिटियर हैं। जिनकी बोरिस जॉनसन के नेतृत्व के तहत राजकोष के चांसलर के रूप में नीतियां आज ब्रिटेन के अभूतपूर्व राजनीतिक-आर्थिक संकट के लिए भी जिम्मेदार हैं, जिसने 2 महीने के भीतर 3 प्रधानमंत्रियों को सत्तासीन किया । प्रो-ब्रेक्सिट नीतियों और झूठे वादों सहित कॉर्पोरेट परस्त नीतियों, प्रो-कॉरपोरेट टैक्स-कटौती के परिणामस्वरूप 15 वर्षों में ब्रिटिश उत्पादकता में 4 प्रतिशत की गिरावट आई है, जिससे बेरोजगारी भयावह स्तर पर पहुंच गई है, बढ़ती मुद्रास्फीति, राष्ट्रीय स्वास्थ्य सेवा का लाभ जनता को ठीक तरह से न मिलनाऔर लिज़ ट्रस का नवीनतम विफल मिनी बजट जिसने अति अमीरों को 45 बिलियन पाउंड (₹ 4.21 लाख करोड़) की कर छूट प्रदान की, जिससे बाजारों में गहरी हलचल हुई, जिसके लिए कंजर्वेटिव पार्टी के नेता के रूप में सुनक भी जवाबदेह हैं।.....

.....जाहिर है, सनक के पास *6850* करोड़ रुपए की संपत्ति है, वे ब्रिटिश इतिहास के सबसे धनी प्रधानमंत्री हैं जो उन्हें भारतीय नव-फासीवादियों के लिए भी पूजनीय बनाते हैं। उनका विवाह इंफोसिस के संस्थापक भारतीय अरबपति नारायण मूर्ति की बेटी अक्षता से हुआ है, जो इस आत्मीयता के लिए एक अतिरिक्त कारक है। सच कहें तो सुनक के ब्रिटिश पीएम बनने पर भारतीयों को गर्व महसूस करने की कोई बात नहीं है, बल्कि वह कॉरपोरेट-नव फासीवादी वैश्विक शासक वर्गों की उस श्रेणी से संबंधित है, जो दुनिया भर में मजदूर वर्ग और सभी उत्पीड़ितों के घातक दुश्मन हैं।

27 अक्टूबर *2022* **पी जे जेम्स, महासचिव, भाकपा (माले) रेड स्टार**

बस्ती सुरक्षा मंच भुवनेश्वर के तीसरे राज्य सम्मलेन का आगाज़

एलिजाबेथ युगः ब्रिटिश साम्राज्य द्वारा विनाश गाथा -

तुहिन

ब्रिटेन की रानी एलिजाबेथ के निधन के पश्चात देश और दुनिया में उनको श्रद्धांजलि देने का बड़ा सिलसिला चला। सिर्फ शासक वर्ग के लोग ही नहीं बल्कि प्रगतिशील खेमों से जुड़े कई लोगों ने उन्हें श्रद्धांजलि दी और स्मरण किया। ऐसे हालात में, रानी एलिजाबेथ जब राजगद्दी पर आसीन थीं तब ब्रिटिश साम्राज्यवाद ने एशिया, अफ्रीका, यूरोप की जनता और मानवता के खिलाफ जो जघन्य अपराध किए हैं उनकी एक बानगी पेश है-

- तृतीय कोड युद्ध : आइसलैंड (1975-76)
- फॉकलैंड युद्ध : अर्जेंटीना (1982)
- लेबनान में बहुराष्ट्रीय सेना भेजना (1982-84)
- ऑपरेशन डेजर्ट स्टोर्म/खाड़ी युद्ध : इराक (1990-91)
- बोस्निया का युद्ध (1992-95)
- ऑपरेशन डेजर्ट फॉक्स : इराक (1998)
- कोसोवो का युद्ध (1998-99)
- सिएरा लियोन का गृह युद्ध (2000-2002)
- अफगान युद्ध (2001-2021)
- इराक युद्ध (2003-2009)
- लीबिया प्रथम गृह युद्ध (2011)
- ऑपरेशन शादेर : इराक सीरिया (2014-19)
- माऊ माऊ विद्रोह दमन : केन्या (1952-60)
- जेबेल आखदार का युद्ध : ओम्मान (1954-59)
- सायप्रस में आपातकाल (1955-59)
- स्वेज नहर का युद्ध : मिस्र (1956-57)
- सीमा संघर्ष : आयरलैंड (1956-60)
- प्रथम कोड युद्ध : आइसलैंड (1958-62)
- स्टेट ऑफ नॉर्थ याफ्फा : यमन (1959)
- डोफर विद्रोह दमन : ओमान (1962-73)
- इंडोनेशिया- मलेशिया विवाद : बोर्नियो (1963-66)
- अदन में आपातकाल : यमन (1963-67)
- उत्तरी आयरलैंड विवाद (1968-98)
- द्वितीय कोड युद्ध : आइसलैंड (1972-73)

ये सिर्फ द्वितीय विश्व युद्ध के बाद और संयुक्त राष्ट्र संघ के अस्तित्व में आने के बाद, तथाकथित शीत युद्ध के दौरान ब्रिटिश साम्राज्य के साम्राज्यवादी मंसूबों की दास्तान है। द्वितीय विश्व युद्ध के पहले तो ब्रिटेन साम्राज्यवादियों का सरगना था, उसके द्वारा उपनिवेशिक लूट की नंगी सच्चाई से पूरी दुनिया वाकिफ है। ★

जातिसूचक पदनाम/टाइटल त्यागना एक शुरुआत है

शंकर

भाकपा (एमएल) रेड स्टार की बारहवीं पार्टी कांग्रेस ने फैसला किया है कि अब से पार्टी की केंद्रीय समिति के सदस्य अपने नाम के साथ जातिसूचक पदनाम/पदवी/उपाधि का उपयोग नहीं कर पाएंगे। हमारे देश में गुप्त कम्युनिस्ट पार्टी में या छिपकर छद्म शब्दों का प्रयोग करने का रिवाज है। इन नामों को 'पार्टिनेम्स' कहा जाता है। ये नाम आमतौर पर बिना उपनाम के भी होते हैं। लेकिन मुझे नहीं पता कि जाति व्यवस्था के खिलाफ तोप दागने के लिए सम्मेलन में औपचारिक प्रस्ताव पारित करके जाति के पदनाम को छोड़ने का फैसला अतीत में किसी कम्युनिस्ट पार्टी ने लिया है इसकी कोई मिसाल है या नहीं। स्वाभाविक रूप से, विभिन्न प्रश्न उत्पन्न हुए हैं। उदाहरण के लिए, इस तरह के प्रतीकात्मक उपायों के माध्यम से जाति व्यवस्था पर हमला करना किस हद तक संभव है? कितना किया जा सकता है? क्या जाति के पद/टाइटल को त्याग कर तथाकथित उच्च जातियों के सामाजिक विशेषाधिकारों से खुद को अलग करना संभव है?

क्या अतीत के शोषक अस्तित्व को त्यागना इतना आसान है? क्या जातिसूचक खिताब त्यागना और चुटकी में जीतना उतना ही आसान है? कुछ लोग कहते हैं, सरनेम/पदवी होना जरूरी है। क्योंकि जब एक तथाकथित उच्च जाति का व्यक्ति खुले तौर पर जाति व्यवस्था के खिलाफ बोलता है, तो यह व्यवस्था पर हमला करने में बहुत अधिक प्रभावी होता है।

ये सवाल ज्यादातर पश्चिम बंगाल के वामपंथी सोच वाले लोग उठाते हैं। उन्होंने एक तरह से वामपंथी राजनीति को समझना सीख लिया है। जहां भोजन, वस्त्र, आवास के लिए लड़ने की बात ज्यादा होती है। वर्ग पर चर्चा होती है, अमीर और गरीब के बीच संघर्ष का इतिहास है। बंटवारे, शरणार्थी आंदोलन की बात होती है. इस तरह यहां कम्युनिस्ट राजनीति का उदय हुआ। लेकिन अगर हम बंगाल की सीमाओं से परे उत्तर भारत और दक्षिण भारत के अन्य राज्यों में जाते हैं, तो हमें संदर्भ में एक स्पष्ट बदलाव दिखाई देगा।

असली भारत क्या है बंगाल में पता नहीं चलेगा। नतीजतन, बंगाल की कम्युनिस्ट राजनीति उत्तर और दक्षिण भारत (केरल को छोड़कर) की कम्युनिस्ट राजनीति से काफी अलग है। इसलिए उन लोगों को समझना थोड़ा मुश्किल है जो बंगाली केंद्रित राजनीति में हैं।

ऐतिहासिक रूप से, जाति व्यवस्था भारत में सामाजिक अधिशेष/अतिरिक्त या बेशी मूल्य पर कब्जा करने के एक विशेष तरीके के रूप में उत्पन्न हुई। पहला भारत , क्षेत्र में आर्यावर्त के नाम से जाना जाता था। यानी मुख्य रूप से उत्तर-पश्चिम और उत्तर भारत। बाद में इस प्रणाली को देश के विभिन्न भागों में विस्तारित किया गया। तो बंगाल के ठीक बगल में - बिहार, झारखंड, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, पंजाब, हरियाणा - आदि,यहां आज भी जाति व्यवस्था दृढ़ता से मौजूद है। हम बंगाल के इतिहास में कुलीन ब्राह्मणों की शक्ति के बारे में जानते हैं। लेकिन बंगाल में पुनर्जागरण आंदोलन, विशेष रूप से ब्रह्म समाज आंदोलन, ब्राह्मणवाद को एक बड़ा झटका देने में सक्षम हुआ। तब स्वतंत्रता संग्राम में बंगाल की अग्रणी भूमिका, मजबूत कम्युनिस्ट आंदोलन आदि की उपस्थिति ने बंगाल की जाति व्यवस्था को इतना नग्न नहीं होने दिया। लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि बंगाल में जाति व्यवस्था मौजूद नहीं है। बेशक वहाँ है, लेकिन विभिन्न ऐतिहासिक कारणों से यह इतने शर्मनाक रूप में नहीं है।

लेकिन अन्यत्र ऐसा नहीं है। घर के करीब, बिहार में जाति व्यवस्था अभी भी एक तीव्र रूप में मौजूद है, और जाति संघर्ष ने कम्युनिस्ट आंदोलन की मुख्य सामाजिक नींव में से एक के रूप में कार्य किया है। उत्तर, उत्तर-पश्चिम भारत और केरल को छोड़कर पूरे दक्षिण भारत में यही सच है। पूरे क्षेत्र में, कम्युनिस्ट पार्टी मुख्य रूप से तथाकथित पिछड़ी जातियों से जुड़ी हुई है। उच्च जाति के लोग सभी जमींदार, भूस्वामी, राजा-वज़ीर थे। आज वे पूंजीपति-भूस्वामी वर्ग या पूंजीपति हैं। मुख्यधारा की पार्टियों में उनका दबदबा है। सीपीआई (एम-एल) लिबरेशन ने एक समय में बिहार में कई बड़ी लड़ाइयाँ लड़ी हैं। जिसकी शुरुआत भोजपुर के प्रसिद्ध लड़ाई से हुई थी। अस्सी के दशक के मध्य में उन्होंने बिहार में अपने संघर्ष के बारे में एक विस्तृत पुस्तक प्रकाशित की, जिसे **"रिपोर्ट फ्रॉम द फ्लेमिंग फील्ड्स ऑफ बिहार"** कहा जाता है, हिंदी में इसका नाम **"बिहार के धधकते खेत खलिहान"** के नाम पर रखा गया । उस किताब के बारे में लंबे समय तक नहीं सुना जाता है। मुझे नहीं पता कि लिबरेशन के युवा साथी पढ़ते हैं या नहीं। लेकिन भारत में मार्क्सवादी-लेनिनवादी आंदोलन ने अब तक जो राजनीतिक साहित्य पैदा किया है, उसके इतिहास में वह किताब सुनहरे अक्षरों में लिखी जाएगी। वहाँ बिहार के जमींदारों की चर्चा करते हुए कहा गया है:

"जाति के संदर्भ में, जमींदार आम तौर पर उच्च जातियों से आते हैं और कुछ इलाकों में कुर्मी और यादवों जैसी कुछ पिछड़ी जातियों की ऊपरी परतों के जमींदार भी आते हैं। अवधिया कुर्मियों के कुछ वर्ग, जो सामाजिक सीढ़ी पर चढ़े हैं, जमींदारों की श्रेणी में एक नए प्रवेशी हैं। अमीर किसान ऊंची जातियों और कुछ पिछड़ी जातियों की ऊपरी परतों से संबंधित हैं, जबकि किसान ऊंची जातियों, पिछड़ी जातियों की ऊपरी परत और कुछ मामलों में अनुसूचित जातियों और जनजातियों से भी बने हैं। और जहां तक गरीब और निम्न-मध्यम किसानों और खेतिहर मजदूरों का सवाल है, उनके पास पिछड़ी जातियों और लगभग पूरी हरिजन और आदिवासी आबादी का बड़ा हिस्सा है।" *(पेज 46-47)*

जब पड़ोस के बिहार में यह स्थिति होगी, तो एक संघर्षरत कम्युनिस्ट पार्टी में स्वाभाविक रूप से दलित समुदाय की बहुतायत होगी - यह कहने की जरूरत नहीं है। दूसरी ओर यह स्वाभाविक है कि ऊंची जातियां ऐसी पार्टी की दुश्मन होंगी। यहां भूमि संघर्ष और अन्य सभी संघर्षों का जातिगत पहलू अपरिहार्य है। लेकिन यह स्थिति उत्तर और दक्षिण भारत के एक बड़े हिस्से में बनी हुई है। भारत में सामान्य रूप से पूंजीवाद के विकास और विशेष रूप से कृषि में पूंजीवाद के विकास ने इस स्थिति को मौलिक रूप से नहीं बदला। हालांकि, एक समय यह माना जाता था कि जाति की समस्या सामंतवाद की एक विशेष समस्या थी।

यदि पूंजीवाद आगे बढ़ता है, तो यह समस्या अब नहीं रहेगी। लेकिन हकीकत में ऐसा नहीं हुआ। ऐसा इसलिए है क्योंकि पतनशील पूंजीवाद कोई मौलिक परिवर्तन नहीं कर पाया। दुनिया में कहीं भी ऐसा नहीं हो पाया है। बल्कि, इस प्रकार की असमानता का उपयोग उच्च लाभ के लिए किया जाता है। यद्यपि पूंजीवाद आर्थिक के अलावा अन्य सभी असमानताओं को खत्म करने का दावा करता है, यह भावना दुनिया भर के मार्क्सवादियों द्वारा एक भ्रम साबित हुई है जो पूंजीवाद को एक अतिशयोक्ति के रूप में देखते हैं।

भारत में तथाकथित जाति समस्या वास्तव में एक सामंती समस्या है - यह विचार भी मार्क्सवादियों का भ्रम है। यह भ्रांति जाति व्यवस्था का गहराई से विश्लेषण करने की अनिच्छा से पैदा हुई है। अन्यथा तो साफ आंखों को एहसास हो जाता कि जाति व्यवस्था हमारे देश में सामंतवाद के उदय के बहुत पहले से मौजूद थी। और आज सामंती व्यवस्था, हालांकि लगभग समाप्त हो चुकी है, जाति व्यवस्था जीवित है।

ऐसे परिस्थिति में कम्युनिस्ट पार्टियों को काम करना होगा। आइए अब हम उत्पत्ति के पद को छोड़ने के विशिष्ट प्रश्न पर आते हैं। हां, यह सच है कि जातिसूचक पदनाम को त्यागना एक सांकेतिक कदम है। इसके द्वारा यह संदेश दिया जा रहा है कि हम जाति व्यवस्था को स्वीकार नहीं करते हैं। लेकिन जिस तरह प्रतीकात्मक संघर्ष पूरा संघर्ष नहीं है, उसी तरह ऐसा सोचना भी गलत है कि प्रतीकात्मक संघर्ष का कोई मूल्य नहीं है। बल्कि इसके विपरीत वास्तविक वर्ग संघर्ष में प्रतीक बहुत बड़ी भूमिका निभाते हैं। अन्य सभी सामाजिक संघर्षों की तरह, साम्यवादी आंदोलन में प्रतीकात्मक संघर्ष का बहुत बड़ा योगदान है और यह पूरे संघर्ष के एक बड़े हिस्से में व्याप्त है। जैसे रंग का प्रयोग। रंग भी एक प्रतीक है। लाल रंग का प्रतीक, हथौड़ा और दरांती का प्रतीक, चित्र का उपयोग भी प्रतीक है। प्रतीकों के रूप में मार्क्स, एंगेल्स, लेनिन या माओ त्से तुंग की चित्रों का प्रयोग करना। एक बड़ी सभा या सम्मेलन के अंत में 'अंतर्राष्ट्रीय' का नियमित गायन भी प्रतीकात्मक है। ऐसे कई प्रतीकों का इस्तेमाल कम्युनिस्ट आंदोलन में हमेशा से होता रहा है। लेकिन इस पर कभी सवाल नहीं उठाया गया। किसी ने यह नहीं कहा कि मार्क्स की तस्वीर टांगने का मतलब मार्क्स का अनुसरण करना नहीं है, लाल झंडा पकड़ना किसी को कम्युनिस्ट नहीं बनाता है, 'इंटरनेशनल' गाने से यह गारंटी नहीं है कि कोई आखिरी युद्ध शुरू करेगा, इसलिए कम्युनिस्ट आंदोलन में चित्रों का उपयोग अब से बंद कर देना चाहिए, या तो लाल को रद्द कर दो या झंडा को ही रद्द कर दो या 'अंतरराष्ट्रीय' गाने में समय बर्बाद करना बंद करो।

ऐसा कभी किसी ने नहीं कहा है क्योंकि प्रतीकों के प्रयोग का महत्व और सीमा दोनों ही सभी समझते हैं। लेकिन आपत्तियां तब पैदा होती हैं जब जाति व्यवस्था के खिलाफ संघर्ष में प्रतीकात्मक कदम उठाए जाते हैं, जैसे कि जातिगत पदनामों का परित्याग।

तो संदेह पैदा होता है, क्या यह आपत्ति किसी और गहरी समस्या की ओर इशारा करती है?

सवाल यह उठता है कि क्या तथाकथित उच्च जाति के कम्युनिस्ट अभी भी जातिवादी चेतना की जंजीरों में जकड़े हुए हैं?

भारत में तथाकथित जाति समस्या वास्तव में एक सामंती समस्या है - यह विचार भी मार्क्सवादियों का भ्रम है। यह भ्रांति जाति व्यवस्था का गहराई से विश्लेषण करने की अनिच्छा से पैदा हुई है। अन्यथा तो साफ आंखों को एहसास हो जाता कि जाति व्यवस्था हमारे देश में सामंतवाद के उदय के बहुत पहले से मौजूद थी। और आज सामंती व्यवस्था, हालांकि लगभग समाप्त हो चुकी है, जाति व्यवस्था जीवित है।

ऐसे परिस्थिति में कम्युनिस्ट पार्टियों को काम करना होगा। आइए अब हम उत्पत्ति के पद को छोड़ने के विशिष्ट प्रश्न पर आते हैं। हां, यह सच है कि जातिसूचक पदनाम को त्यागना एक सांकेतिक कदम है। इसके द्वारा यह संदेश दिया जा रहा है कि हम जाति व्यवस्था को स्वीकार नहीं करते हैं। लेकिन जिस तरह प्रतीकात्मक संघर्ष पूरा संघर्ष नहीं है, उसी तरह ऐसा सोचना भी गलत है कि प्रतीकात्मक संघर्ष का कोई मूल्य नहीं है। बल्कि इसके विपरीत वास्तविक वर्ग संघर्ष में प्रतीक बहुत बड़ी भूमिका निभाते हैं। अन्य सभी सामाजिक संघर्षों की तरह, साम्यवादी आंदोलन में प्रतीकात्मक संघर्ष का बहुत बड़ा योगदान है और यह पूरे संघर्ष के एक बड़े हिस्से में व्याप्त है। जैसे रंग का प्रयोग। रंग भी एक प्रतीक है। लाल रंग का प्रतीक, हथौड़ा और दरांती का प्रतीक, चित्र का उपयोग भी प्रतीक है। प्रतीकों के रूप में मार्क्स, एंगेल्स, लेनिन या माओ त्से तुंग की चित्रों का प्रयोग करना। एक बड़ी सभा या सम्मेलन के अंत में 'अंतर्राष्ट्रीय' का नियमित गायन भी प्रतीकात्मक है। ऐसे कई प्रतीकों का इस्तेमाल कम्युनिस्ट आंदोलन में हमेशा से होता रहा है। लेकिन इस पर कभी सवाल नहीं उठाया गया। किसी ने यह नहीं कहा कि मार्क्स की तस्वीर टांगने का मतलब मार्क्स का अनुसरण करना नहीं है, लाल झंडा पकड़ना किसी को कम्युनिस्ट नहीं बनाता है, 'इंटरनेशनल' गाने से यह गारंटी नहीं है कि कोई आखिरी युद्ध शुरू करेगा, इसलिए कम्युनिस्ट आंदोलन में चित्रों का उपयोग अब से बंद कर देना चाहिए, या तो लाल को रद्द कर दो या झंडा को ही रद्द कर दो या 'अंतरराष्ट्रीय' गाने में समय बर्बाद करना बंद करो।

ऐसा कभी किसी ने नहीं कहा है क्योंकि प्रतीकों के प्रयोग का महत्व और सीमा दोनों ही सभी समझते हैं। लेकिन आपत्तियां तब पैदा होती हैं जब जाति व्यवस्था के खिलाफ संघर्ष में प्रतीकात्मक कदम उठाए जाते हैं, जैसे कि जातिगत पदनामों का परित्याग।

तो संदेह पैदा होता है, क्या यह आपत्ति किसी और गहरी समस्या की ओर इशारा करती है? सवाल यह उठता है कि क्या तथाकथित उच्च जाति के कम्युनिस्ट अभी भी जातिवादी चेतना की जंजीरों में जकड़े हुए हैं? क्या इसका कारण यह है कि शहरी कम्युनिस्टों के बीच इस तरह के संदेह के बावजूद, देश के एक बड़े हिस्से में तथाकथित 'पिछड़े वर्गों' के कम्युनिस्ट कार्यकर्ताओं ने इस फैसले का बड़े हर्ष के साथ स्वागत किया?

समय इन सवालों का जवाब देगा, शंकाओं को दूर करेगा। अभी के लिए हम केवल इतना कह सकते हैं कि हम अंतिम शब्द कहने का दावा नहीं करते। इस संबंध में यह अंतिम परीक्षा नहीं है। महत्वपूर्ण बात यह है कि काम गंभीरता से किया गया है। क्योंकि यहां साम्यवादी आंदोलन बिना हस्तक्षेप के आगे नहीं बढ़ेगा। काम करते समय सही और गलत होगा, आगे पीछे होगा, दायां झुकाव होगा या बाएं झुकाव होगा, इसे रास्ते में ठीक किया जाएगा। लेकिन साहस के साथ पथ पर चलना चाहिए, प्रयोग का जोखिम उठाना चाहिए। इनके बिना आंदोलन आगे नहीं बढ़ सकता। हमारी पार्टी कांग्रेस में इस मामले पर विस्तार से चर्चा हुई। मौजूदा फासीवाद विरोधी माहौल में इस प्रकार के कदम उठाने की अन्य जटिलताओं पर भी चर्चा की गई है। जैसा कि पंजाब के साथियों ने जोर देकर कहा है, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ देश के लोगों की सभी विविधताओं को नष्ट करने की कोशिश कर रहा है। हर चीज को एक ही सांचे में ढालने की कोशिश हो रही है। विशेष रूप से जो लोग धार्मिक प्रतीकों, पोशाक या नाम और अल्पसंख्यकों के उपनामों का उपयोग करते हैं, उन पर बड़े पैमाने पर हमले हो रहे हैं। ऐसे में मनमाने ढंग से सरनेम छोड़ने की कुछ अन्य जटिलताएं भी बनी रहती हैं, यह विचारणीय है। इसलिए फिलहाल यह तय है कि केंद्रीय समिति के सदस्य ही जातिसूचक पदनाम छोड़ेंगे। भविष्य में इस मामले पर और अभ्यास किया जाएगा और स्थिति पर नजर रखी जाएगी।

"चलो यात्रा शुरू करते हैं, चले चलो दिलों में आग ले के चलो"।

लेखक कॉमरेड शंकर, भाकपा (माले) रेड स्टार पार्टी के पोलित ब्यूरो के सदस्य हैं। ये उनका लेख जो कि वेब मैगजीन नागरिक डॉट कॉम (बांग्ला) में प्रकाशित हुआ है, का त्वरित अनुवाद है।

★

ईरान में महसा अमीनी की शहादत : एक साहसी लोकप्रिय विद्रोह के सामने डगमगा रहे हैं ईरान के तानाशाह

तुहिन

गत 4 दिसंबर को ईरान की इब्राहिम रईसी सरकार ने "नैतिक पुलिस" नीति को खत्म करने की घोषणा की। एक धार्मिक सम्मेलन में ईरान के अटॉर्नी जनरल मुहम्मद जफर मोंट्रूटजी ने यह घोषणा की। पिछले तीन माह से ईरान समेत पूरी दुनिया को हिलाने वाले औरतों के जीवन जीने के अधिकार और जनता की आजादी के अधिकार पर केंद्रित इस जबरदस्त आंदोलन के लिए एक महत्वपूर्ण उपलब्धि है। ऐसा लग रहा था कि ईरान के जनता की धार्मिक कट्टरपंथ और तानाशाही के खिलाफ यह घोषणा एक जीत है, लेकिन ईरान की कट्टर धार्मिक तानाशाही सरकार ने न तो महिलाओं के हिजाब पहनने की अनिवार्यता को समाप्त किया है और न ही जन ज्वार को वो तमाम दमन पीड़न के बावजूद स्तब्ध कर पाये हैं।

[IVAN ALVARADO/REUTERS]

आंदोलन की शुरुआत की पृष्ठभूमि-

16 सितंबर को ईरान की नैतिक पुलिस के हाथों तेहरान में एक युवा कुर्द महिला, जीना महसा अमिनी (उम्र 22) की पुलिस हिरासत में मौत हो गई। 13 सितंबर को उसकी गिरफ्तारी तेहरान में शहीद हागनी एक्सप्रेस वे में धार्मिक नैतिक पुलिस द्वारा की गई थी। उसका कारण बताया गया कि उसने हिजाब पहनने के लिए बनाए कानून का कथित उल्लंघन किया था। वह ईरान के पश्चिम के इराकी सीमा से लगे कुर्द हिस्से साघेज शहर की रहने वाली थी।

तब से, ईरान में बड़े पैमाने पर विरोध प्रदर्शन शुरू हो गए हैं और जो बंद होने का नाम नहीं ले रहे; ईरान के धार्मिक सरकार के जुल्मों सितम के बावजूद। ये प्रदर्शन शुरू तो हुए ईरान के अल्पसंख्यक राष्ट्रीयता वाले कुर्द प्रांत में, लेकिन बहुत जल्द ईरान के सभी बड़े और छोटे शहरों में दिन-रात सड़कों पर अलग अलग तरीके से लड़ाकू प्रदर्शन शुरू हो गए जो आठ सप्ताह बाद भी जोर शोर से जारी है। दुनिया के बहुतेरे देशों में कुर्द वामपंथी विद्रोही महिलाओं के नारे "जिन, जियान, आजादी" (महिला, जीवन, आजादी) गूंज रहे हैं। ये नारा सबसे पहले 8 मार्च, 2006 को अंतरराष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर क्रांतिकारी कुर्द महिलाओं ने लगाया था। ईरान में सड़कों पर प्रदर्शनकारियों का दबदबा तमाम किस्म के दुष्प्रचार और दमन के बावजूद कायम है। जीना अमिनी की मृत्यु ने फिर से पूरे देश में एक क्रांतिकारी उत्तेजना की आग को प्रज्वलित कर दिया है, जो लंबे समय से जनता के बीच सुलग रही थी। महिलाओं, युवा/विद्यार्थियों के द्वारा महिलाओं के खिलाफ धार्मिक पित्रसत्तात्मक प्रतिबंधों के खिलाफ और अभिव्यक्ति की आजादी के पक्ष में शुरू हुए इस विद्रोह में मजदूरों और आम जनता के जुड़ जाने से ईरान का मौजूदा विद्रोह अभूतपूर्व रूप ले चुका है।

इतिहास खुद को दुहरा रहा है

1852 में 35 वर्षीय महिला अधिकार कार्यकर्ता ताहिरीह घोराटोलें को तेहरान में तत्कालीन शासकों द्वारा उसके तथाकथित धर्मविरोधी होने और हिजाब न पहनने के कारण मृत्युदंड दिया गया था। उसके अंतिम वाक्य थे "तुम लोग मुझे जल्दी से जल्दी जैसा तुम चाहे मार सकते हो मगर तुम लोग महिलाओं की मुक्ति को नहीं रोक सकते"। करीब 170 साल बाद उसी शहर में 22 वर्षीय माहसा जीना अमीनी नामक कुर्द युवती की मौत इस्लामिक धार्मिक शासकों का कोपभाजन बनने से हुई। इस मामले में इतिहास की पुनरावृति हुई है कि दोनों महिलाओं ने पितृसत्ता और धार्मिक तानाशाही के गठबंधन को चुनौती दी या शासकों को इन महिलाओं से डर लगा।

महसा के भाई ने कहा कि वे तेहरान के नहीं हैं और शहर के कायदे कानून से ठीक से वाकिफ नहीं थे।लेकिन फिर भी तेहरान की धार्मिक नैतिक पुलिस ने महसा को अपमानित किया और यातना देकर मार डाला। हॉस्पिटल में डॉक्टरों ने कहा कि उनका "ब्रेन डेड" हो चुका है और दिल में धक्का लगा है। ईरान की धार्मिक सरकार ने कहा कि वह पहले से गंभीर बीमारी से पीड़ित थी इसी से उसकी मृत्यु हो गई है। लेकिन महसा के परिवार और दोस्तों ने इसे झूठा करार दिया और कहा कि उसे कोई बीमारी नहीं थी।

कुर्द कौन हैं-

असल में महसा अमीनी ईरानी नाम है। महसा का कुर्दिश नाम "जीना" है। जीना का कुर्द भाषा में अर्थ जीवन है। कुर्द एक अल्पसंख्यक राष्ट्रीयता है जो ईरान, इराक, टर्की और सीरिया में बसे हुए हैं। जिस तरह हमारे देश में कश्मीरी राष्ट्रीयता के लोगों को द्वितीय श्रेणी का नागरिक बना कर सारे मौलिक अधिकारो के लिए जद्दोजहद करने पर मजबूर कर दिया गया है वैसे ही कुर्दों को उपरोक्त चारों देशों में बदहाल स्थिति रखा गया है। जिसके खिलाफ कुर्दिस्तान वामपंथी आंदोलन विशेषकर महिलाएं लगातार सक्रिय हैं। हाल ही में टर्की और समीप के देशों के कुर्द क्षेत्रों में बहुत ज्यादा सक्रिय **"कुर्दिस्तान विमेंस लिबरेशन मूवमेंट"** से जुड़ी नगिहान अकारसेल शहीद हो गई हैं। उन्हे टर्की की फासिस्ट एर्डोगन सरकार ने मार डाला। कुर्दिस्तान विमेंस लिबरेशन मूवमेंट, साम्राज्यवाद तथा उसके देशीय दलाल कॉरपोरेट घरानों व धार्मिक फासिस्ट सरकार के साथ साथ धार्मिक पितृसत्तात्मक कट्टरपंथी/आतंकवादी आइसिस के खिलाफ जीवन मरण का संघर्ष चला रही हैं। आइसिस के आतंकी जिन्हे अल कायदा और तालिबान की तरह अमेरिकी साम्राज्यवाद ने पैदा किया है, कुर्द महिला वामपंथी छापामारों से बहुत डरते रहे हैं। इन बहादुर वामपंथी महिला क्रांतिकारियों के सशस्त्र प्रतिरोध के चलते कुछ सालों पूर्व आइसिस (इस्लामिक स्टेट्स) के हाथों से **"रोझावा"** को मुक्त किया गया था, जो एक इतिहास बन चुका है।

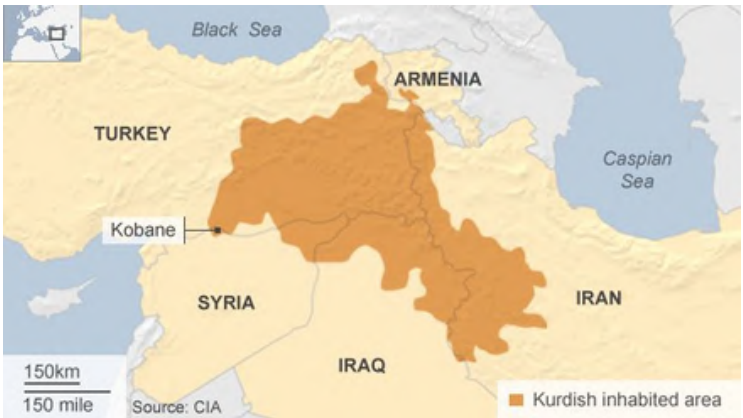

WWW.BBC.COM/

विद्रोह क्यों फैला-

पहली नज़र में, विरोध गुस्से के एक स्वतःस्फूर्त विद्रोह की तरह लगता है। लेकिन इसका एक लंबा इतिहास है। पिछले साल पहले से ही 55 से 130 प्रतिशत तक की मुद्रास्फीति लोगों के लिए असहनीय होती जा रही थी, और कई संघर्ष के अनुभव वाले श्रमिक कारखानों में संगठित हो रहे थे। मार्च 2021 से मार्च 2022 तक, इस्पात संयंत्रों , तेल, गैस, पेट्रोकेमिकल जैसे औद्योगिक क्षेत्रों से 4000 श्रमिकों के संघर्ष हुए थे।जिसमें हफ़्ट टेपे में गन्ना श्रमिकों से लेकर ट्रक ड्राइवरों, नर्सों और शिक्षकों तक संघर्ष में शामिल हुए थे।विरोध प्रदर्शनों में ट्रेड यूनियन की मांगें उठाई गईं, साथ ही कारखानों, शैक्षणिक संस्थानों और बुनियादी शहरी सेवाओं के निजीकरण ,मंहगाई और बेरोजगारी के खिलाफ मांगों को भी उठाया जा रहा है।

ईरान में पश्चिमी साम्राज्यवादी ताकतों की भूमिका-

मध्य पूर्व विशेषकर ईरान, तेल की प्रचुरता के कारण साम्राज्यवादियों का सरगना अमरीका और अन्य पश्चिमी ताकतों के निशाने पर रहा है। 1953 में ईरान की संसद (मजलिस) द्वारा निर्वाचित देश के 35वें प्रधानमंत्री मोहम्मद मोसद्देघ जो की लोकप्रिय थे और साम्राज्यवाद विरोधी भूमिका में थे को अमरीकी और ब्रिटिश साम्राज्यवाद ने प्रतिक्रांति के जरिए सत्ता से अपदस्थ कर दिया। मोसद्देग, ब्रिटिश तेल निगम "एंग्लो अमेरिकन ऑइल कंपनी(AIOC)" के दस्तावेजों का ऑडिट करने जा रहे थे। उनके नेतृत्व में ईरानी संसद मजलिस ने ईरान की तेल संपदा के राष्ट्रीयकरण के पक्ष में मतदान किया था। ब्रिटेन ने तब ईरान के तेल का विश्व व्यापी बहिष्कार की मुहिम चलाई और ब्रिटिश नियंत्रित "अबादान ऑयल रिफाइनरी" पर प्रभुत्व के लिए ईरान के खिलाफ सैनिक कार्यवाही करने की पहल की थी। ब्रिटिश प्रधानमंत्री चर्चिल और अमेरिकी राष्ट्रपति ईसनहावर मिलकर मोसद्देक सरकार को गिराने की लगातार कोशिश कर रहे थे। अंत में सीआईए और ब्रिटिश इंटेलिजेंस एमआई 5 ने मिलकर TPAJAX प्रोजेक्ट के तहत मोसद्देघ का तख्ता पलट किया। सीआईए ने मोसद्देग विरोधी प्रदर्शन करवाए।प्रतिक्रांति के बाद उन्हें सैनिक अदालत ने गिरफ्तार किया और तीन साल की कैद की सजा दी। उनके अधिकांश देशभक्त समर्थकों को या तो जेल में डाला गया या मार डाला गया। प्रतिक्रांति के बाद जनरल फजलुल्लाह जहेदी ने सत्ता शाह रजा पहलवी को सौंप दी।इस तरह प्रजातंत्र का गला घोंट कर साम्राज्यवादी ताकतों ने ईरान में राजतंत्र की स्थापना की।पहलवी वंश के अमरीकी पिट्ठू शाह का निरंकुश शासन छब्बीस वर्ष तक चला। अगस्त 2013 में अमरीकी सरकार ने ईरान में हुई 1953 की प्रतिक्रांति में अपनी भूमिका को स्वीकार किया। अमरीकी सरकार की रिपोर्ट में यह माना गया कि अमेरिकी विदेश नीति के तहत प्रशासन के सर्वोच्च स्तर के आदेश से उस समय सीआईए ने ईरानी राजनीतिज्ञों, सैनिक अधिकारियों को बड़े पैमाने पर घुस दिया और मोसद्देघ विरोधी माहौल बनाने के निमित्त प्रचार प्रसार में पैसा पानी की तरह खर्च किया गया।

1979 में ईरान में इस्लामिक क्रांति के होने तक शाह रजा पहलवी का शासन एक घोर जनविरोधी तानाशाही जुल्मी दौर था। जहां पश्चिमी बहुराष्ट्रीय कंपनियों को देश को लूटने की खुली छूट दे दी गई और जनसंघर्षों/अभिव्यक्ति की आजादी को कुचल दिया गया। ईरान के वामपंथी दलों और फिदायीन उल मुल्क जैसे साम्राज्यवाद, सामंतवाद, पूंजीवाद विरोधी दलों के कार्यकर्ताओं को बड़े पैमाने पर मार डाला गया या तेहरान की बदनाम जेल/यातनागृह सेविन में तड़पने के लिए छोड़ दिया गया। ये वही जेल "सेविन" है जहां कुछ दिन पहले भीषण आग लगी थी और कई कैदी मारे गए थे या गंभीर रूप से घायल हुए थे। इनमे ज्यादातर वे कैदी थे जो महजा अमीनी की शहादत के बाद विरोध प्रदर्शन कर रहे थे।

अप्रैल से दिसंबर 1979 के बीच ईरान में तानाशाह शाह रजा पहलवी विरोधी संघर्ष ने जोर पकड़ा और जनता प्रजातंत्र के लिए सड़कों पर उतर आई। इस विद्रोह में कम्युनिस्ट भी सक्रिय थे।यही वह समय था जब निर्वासित धार्मिक नेता अयातुल्लाह खोमेनी यूरोप से निर्वासन से लौट आए और विद्रोह की कमान संभाल ली। शाह विरोधी विद्रोह सफल होने के बाद खोमैनी ने ईरान को इस्लामिक गणराज्य घोषित कर दिया, लोगों की जनवादी आकांक्षाओं को कुचल दिया गया और वामपंथी व जनवादी ताकतों का सफाया किया जाने लगा। ईरान के इस्लामिक गणराज्य ने धार्मिक शासन कायम करते हुए अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता को खारिज करते हुए लोगों पर विशेषकर महिलाओं पर तमाम किस्म की पाबंदियां लगाईं। 1979 में इस्लामिक क्रांति के बाद से "नैतिक पुलिस" ने काम करना शुरू कर दिया। 1983 में ईरान में हिजाब पहनना अनिवार्य घोषित किया गया।

भारत के संघी फासीवादी ताकतों की भूमिका-

भारत के साथ ईरान के दोस्ताना संबंध रहे हैं। संयुक्त राष्ट्र संघ में पाकिस्तान व अमेरिका के लाए प्रस्ताव के खिलाफ ईरान ने हमेशा भारत का साथ दिया है। चाबहार बंदरगाह और ईरान भारत तेल पाइप लाइन पर ईरान से हुए समझौते के बावजूद, अमेरिकी साम्राज्यवाद के दबाव में फासिस्ट मोदी सरकार ने संयुक्त राष्ट्र संघ में ईरान का समर्थन नहीं किया, न ही उससे तेल खरीदा और न ही अमेरिका द्वारा ईरान के खिलाफ अन्यायपूर्ण कार्रवाई का ये कभी विरोध करती है।

ईरान के हिजाब विरोधी और महिला अधिकारों के लिए हो रहे प्रदर्शनों से भारत का फासिस्ट संघ परिवार और कॉरपोरेट गोदी मीडिया, हिजाब पर प्रतिबंध लगाने की उनकी अल्पसंख्यक विरोधी मुहिम के लिए मुफीद मान रहे हैं।

लेकिन वे ये भूल जाते हैं कि ईरान के महिलाओं और आम जनता का आंदोलन, धार्मिक कट्टरपंथ व फासीवाद के खिलाफ है तथा औरतों के पक्ष में समानाधिकार और आजादी का आंदोलन है। इस आंदोलन से यह ध्वनि उभरी है कि महिलाओं को यह अधिकार होना चाहिए कि वे क्या पहने, क्या खाएं और अपना जीवन कैसे बिताएं। इस लिहाज़ से साम्राज्यवाद के जूनियर पार्टनर और भारतीय जनता के दुश्मन नंबर एक संघी मनुवादी फासिस्ट ताकतों को महिलाओं के बारे में कुछ भी बोलने का कोई अधिकार नहीं है। क्योंकि सबसे बड़े महिला विरोधी और महिलाओं के खिलाफ यौन अत्याचारों में शीर्ष पर रहने वाले आरएसएस, भाजपा के नेता, संघी गुंडे/दंगाई और इनके घनिष्ठ मित्र बलात्कारी हत्यारे ढोंगी बाबा राम रहीम, आशाराम बापू जैसे लोग ही हैं।

अब क्या-

इन संघर्षों से वह शक्ति विकसित हुई जो आज के जन-विद्रोह को देशव्यापी विस्तार देती है, उनको निरंतरता प्रदान करती है और धार्मिक पितृसत्तात्मक शासन के खिलाफ उनके प्रतिरोध को निर्देशित करती है।

"लोगों का कहना है कि बस अब अति हो गई है। श्रमिक वर्ग हड़तालें कर रहा है, महिलाएं सड़कों पर हैं, शिक्षक व पेंशनभोगी महीनों से लड़ रहे हैं। हर कोई गरीबी, बेरोजगारी, मुद्रास्फीति, भूख और उत्पीड़न से भरे असहनीय जीवन के खिलाफ लड़ रहा है। विरोध स्पष्ट संकेत देते हैं कि कुर्द और ईरान के अन्य सभी समुदायों के लोग बड़ी एकजुटता के साथ एक साथ खड़े हैं।" ऐसा ईरान की अंतरराष्ट्रीय लड़ाकू महिला आंदोलन की कार्यकर्ता ईरानी जमान मसूदी कहती हैं।

जीना महसा अमीनी की मौत की खबर को सबसे पहले ईरान की पत्रकार निलोफर हमीदी ने ट्विटर पर उजागर किया था। 22 सितंबर को पुलिस ने उनके घर छापा मारकर उनके लिखने का सारा सामान जब्त किया और उन्हें गिरफ्तार कर जेल के तन्हाई सेल में डाल दिया है। उनके वकील मुहम्मद अली ने ट्विटर पर यह जानकारी दी है।

लोग अपना डर खो रहे हैं।समाचार एजेंसी रॉयटर के अनुसार चार महीनों से चल रहे आंदोलन में अब तक करीब 18000 से अधिक गिरफ्तारियों, 25000 से अधिक लोगों के घायल होने और करीब 500 मौतों (जिसमें 63 बच्चे हैं) के साथ क्रूर दमन और हिंसा के बावजूद, महिलाएं और पुरुष, कार्यकर्ता, युवा लोग, कलाकार, मीडियाकर्मी, विद्यार्थी समुदाय, घृणास्पद धार्मिक तानाशाही वाले फासीवादी शासन के खिलाफ खड़े हैं। ईरान की सरकार इस लोकप्रिय आंदोलन को "दंगों" का नाम देकर निर्मम दमन कर रही है। महिलाओं ने, पुलिस थानों, धार्मिक केंद्रों और सार्वजनिक कार्यालयों सार्वजनिक रूप से अपने हिजाब को उतार कर उसे आग के हवाले कर दिया। साथ ही पुरुष प्रधान समाज द्वारा सौंदर्य का एक मापदंड समझे जाने वाले नारी के लंबे बालों को महिलाओं ने सड़कों पर काट कर फेंक दिया। हाल ही में निका शकरीन ने खुलेआम हिजाब को उतारकर जलाया। उस दिन के बाद से वह लापता थी, दस दिन के बाद उसकी लाश मिली। नीका की मौत की खबर ने विद्रोह को और भड़का दिया। पश्चिम के कुर्द शहर "सानंदाज" में पुलिस गोलीचालन से कई नौजवानों की मौत हो गई। दोनों धार्मिक नेता, इस्लामिक क्रांति के नेता अयातुल्लाह खोमैनी और वर्तमान के सर्वोच्च धार्मिक नेता रुहेल्ला खोमैनी के चित्र पर प्रदर्शनकारी कालिख पोत रहे हैं और उनके घर पर प्रदर्शनकारी आग लगा रहे हैं और उनको मृत्युदंड दिए जाने की मांग कर रहे हैं जो अभी तक अविश्वसनीय बात थी। ईरान के वर्तमान राष्ट्रपति महोदय जब एक कॉलेज में गए तो छात्राओं ने उन्हें "गेट आउट" कहा। ईरान के कई प्रसिद्ध कलाकारों ने भी इस आंदोलन में अपना समर्थन दिया है। उनमें से कई अभिनेत्रियों ने भी अपने हिजाब सार्वजनिक रूप से उतार फैंका है। ईरान के लोकप्रिय फुटबॉलर भारिया गफूरी को जनांदोलन का समर्थन करने के कारण विश्व कप की टीम में शामिल नहीं किया गया और उन्हें जेल में डाल दिया गया है।

ईरान की ३३ वर्षीय एथलीट एलनाज रेकाबी को अंतरराष्ट्रीय प्रतियोगिता में बिना हिजाब पहने उतरने के कारण,ईरान के उत्तर पश्चिम में जानजान प्रदेश में स्थित पैतृक मकान को प्रशासन ने तोड़ डाला।ठीक वैसे ही जैसे हमारे देश में फासिस्ट योगी,शिवराज या अन्य प्रशासन ,बुलडोजर के जरिए मुसलमानों का घर तोड़ते हैं।महसा अमीनी की शहादत के बाद उपजे आंदोलन पर तो ईरान सरकार दमन चक्र चला ही रही है,अब पहली बार सरकार ने २३ वर्षीय आंदोलनकारी मोहसेन शेकारी को इस्लामिक कानून के तहत मृत्यु दण्ड की सजा दी है।अब तक ११ लोगों को मृत्यदण्ड दिया गया है। प्रशासन ने कहा है कि और भी कई प्रदर्शनकारियों को मृत्युदंड की सजा दी जाएगी।२०१९ में ईंधन की किल्लतों और बढ़ती मंहगाई के खिलाफ जब जनता आंदोलन कर रही थी तब इस्लामिक गार्ड्स ने गोलीबारी की और कई लोग मारे गए।इस खूनी कारवाई की याद में वर्तमान में आंदोलनकारियों ने शहीदों का स्मरण दिवस मनाया।

ईरान की नारियां पूरी दुनिया के नारियों का प्रतिनिधित्व करते हुए कह रही हैं कि महिलाओं के बारे में क्या सही क्या गलत है ये वे खुद तय करेंगी।पूंजीवादी,सामंती धार्मिक पितृसत्तात्मक समाज को कोई अधिकार नहीं कि वे ये तय करें की औरतें ये पहनें या ऐसे चलें।

"पितृसत्ता,साम्राज्यवाद,फासीवाद और धार्मिक कट्टरपंथ का नाश हो,ईरान में महिलाओं समेत आम जनता की आजादी,समान अधिकार और सच्चे जनवाद के लिए लड़ाई जिंदाबाद" नारे के आधार पर ICOR (कम्युनिस्ट और क्रांतिकारी संगठनों का अंतरराष्ट्रीय मंच) में शामिल चालीस से अधिक देशों(जिनमें भारत भी है)की क्रांतिकारी कम्युनिस्ट पार्टियों और क्रांतिकारी महिला संगठनों ने मिलकर ईरान की विद्रोही जनता को क्रांतिकारी सलाम के रूप में एकजुटता संदेश प्रेषित किया है।

www.aninews.in

हाल ही में कतर में चल रहे फीफा फुटबॉल विश्व कप में ईरान की राष्ट्रीय टीम ने इंग्लैंड के विरुद्ध खेलते हुए,ईरान में चल रहे जनांदोलन के समर्थन और सरकार द्वारा ढाए जा रहे जुल्मों के प्रतिवाद स्वरूप राष्ट्रीय गीत का गायन नहीं किया।

हलांकि ईरान सरकार के भीषण दबाव और अपने भविष्य के प्रति आशंका के चलते अगले मैच में उन्होंने राष्ट्रीय गीत गाया।लेकिन अंतरराष्ट्रीय मंच पर उनका प्रतिवाद बहुत उल्लेखनीय था।तिरुअनंतपुरम में आयोजित अंतरराष्ट्रीय फिल्म महोत्सव में विशेष सम्मान से सम्मानित ईरानी फिल्मकार महमूदीजाद को सम्मान ग्रहण करने ईरान से भारत नहीं आने दिया गया तो उन्होंने महिला, जीवन और आजादी की रक्षा में चल रहे ईरानी जनता के समर्थन में और मृत्युदंड दिए गए युवा शकीरी के समर्थन में अपने बालों का गुच्छा, फिल्म महोत्सव में भिजवाया।जैसे जैसे जनता का भीषण आक्रोश तीन दशक से भी अधिक समय से काबिज धार्मिक तानाशाह खुमैनी के खिलाफ सड़कों पर उमड़ रहा है वैसे वैसे ईरान की धार्मिक तानाशाह सत्ता जनता के खिलाफ जंग को तेज कर रहे हैं। हाल ही में प्राप्त समाचार के अनुसार सुरक्षा बल ,आंदोलन की अगुआई कर रहे युवतियों के यौन अंगों को और युवाओं के नितंबों को गोली का निशाना बना रहे हैं।घायलों का इलाज कर रहे डॉक्टरों ने भी इसकी पुष्टि की है।

अफगानिस्तान सहित दुनिया के चारों ओर आधी आबादी द्वारा, " जिन,जियान,आजादी"(नारी, जीवन, स्वतंत्रता) के नारों से आसमान गूंज रहा है ,ईरान में विद्रोही अपने विचारों को छुपाना अपनी शान के खिलाफ समझ रहे हैं । वे खुलकर धार्मिक फासीवादी राजसत्ता,पूंजीवाद/साम्राज्यवाद के खिलाफ सड़कों पर उमड़ रहे हैं। वे सच्चे जनवाद,बराबरी का अधिकार,शोषणहीन समाज और तमाम किस्म के जुल्मों से आजादी चाहते हैं और हकीकत है कि उनके विद्रोह से इस्लामिक धार्मिक शासक कांप रहे हैं, बहुत कुछ वैसा जैसा 1850 में कम्युनिस्ट घोषणापत्र की भूमिका में कहा गया था।क्या ईरान में महिलाओं समेत आम जनता के धार्मिक कट्टरपंथ,फासीवादी दमन और तानाशाही के खिलाफ इस महत्त्वपूर्ण जीत से हमारे देश में जनता के दुश्मन कॉरपोरेट घरानों के दलाल संघी मनुवादी फासिस्ट ताकतों के खिलाफ चल रहे आंदोलन में गति मिलेगी।

आर्थिक आधार पर आरक्षण के निहितार्थ

- रितांश आज़ाद

सुप्रीम कोर्ट द्वारा सवर्ण जाति के लोगों को 10 % आरक्षण साफ तौर पर मनुवादी निर्णय दिखाई पड़ता है, इसे गहराई से समझना चाहिए। इसके हिसाब से ये आरक्षण 8 लाख तक सालाना पारिवारिक कमाई करने वाले उच्च जाति वालों को मिलेगा। यानि महीने की 67000 रुपये पारिवारिक कमाई वाले लोग जो इनकम टैक्स देने योग्य हैं, उन्हें भी आरक्षण का लाभ मिलेगा। पहली बात संविधान में आर्थिक आरक्षण की कोई बात नहीं कही गई है, इसीलिए ज़्यादातर संविधान के जानकारों का कहना है कि गैरसंविधानिक है। आरक्षण कोई गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम नहीं है, ये सामाजिक भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए बनाया गया था। गरीब सवर्णों के आर्थिक उत्थान के लिए अलग सरकारी योजनाएं हैं। सरकारी आरक्षण समाज के उन तबकों के लिए है जो असल में बहुसंख्यक हैं और जिन्होंने 2000 से ज़्यादा सालों तक सामाजिक, आर्थिक शोषण और भेदभाव झेला है और आज भी झेल रहे हैं। सरकारी पदों में भागीदारी की असलियत के कुछ उदाहरण दें तो मोदी की केन्द्रीय सरकार के 89 सचिवों में से सिर्फ 4 SC/ST जातियों से हैं और पिछड़ी जातियों से एक भी नहीं, यानि बाकी 85 सवर्ण हैं। 275 संयुक्त सचिवों में से सिर्फ 13 SC से हैं, 9 ST से और 13 पिछड़ी जातियों से हैं, यानि 240 उच्च जातियों से हैं। संसद में खुद सरकार द्वारा पेश किया हुआ आंकड़ा है कि 45 केन्द्रीय विश्वविद्यालाओं के कुलपतियों में से केवल 1 SC से, 5 ST से और 7 पिछड़ी जातियों से हैं, यानि बाकी 32 उच्च जातियों से हैं। इसी तरह इन विश्वविद्यालाओं में कुल 12373 शिक्षक हैं जिसमें सवर्ण 8386 हैं, 1306 SC से, 568 (ST) और 1740 OBC से हैं। न्यायाधीशों को देखें तो वहाँ तो ब्राह्मणों का बोलबाला रहा ही है, ये जग ज़ाहिर है। न्यूज़ लॉन्ड्री और ऑक्सफैम की रिपोर्ट के हिसाब से मीडिया की 90% नेतृत्वकारी पदों पर सवर्ण बैठे हैं। यानि जहां सरकारी आरक्षण लागू है वहाँ भी उच्च जातियों का वर्चस्व है और निजी क्षेत्र में तो ये है ही। मतलब ज़्यादतर सवर्णों के पास समाज में एक अघोषित आरक्षण पहले से ही है। ये भी समझना चाहिए कि आरक्षण तो सिर्फ सरकारी क्षेत्र की व्यवस्था है और आज जब हर कंपनी निजी हाथों में दी जा रही है तो सरकारी आरक्षण तो वैसे ही पूरी तरह समाप्त होता जा रहा है।

मैं कुछ दिन पहले फोर्ब्स मैगज़ीन की लिस्ट देख रहा था भारत के सबसे अमीर लोगों की, सबसे ज़्यादा उसमें बनिया जाति के लोग थे। भारत के 30 सबसे अमीर लोगों की लिस्ट देखी जिसमें ज़्यादातर बनिये हैं, पिछड़ी जाति का सिर्फ एक व्यक्ति है, बाकी SC और ST का कोई नहीं।

एक और बात आप देश के सबसे बड़े मंदिरों और मठों के मठाधीशों और बाबाओं को देखिए, वे ज़्यादातर ब्रह्माण ही हैं न? क्या इस देश में वो करोड़ों का व्यापार नहीं है? क्या इस देश की ब्राह्मणवादी विचारधारा, पूंजीवादी शोषण के ऊपर पर्दा डालने और इसे बनाए रखने में मदद नहीं करती? क्या इसका सबसे ज़्यादा लाभ सामाजिक तौर पर सवर्णों को नहीं मिलता? एक गरीब दलित और एक गरीब ब्राह्मण में ज़्यादा सांस्कृतिक विरासत, सामाजिक वर्चस्व और अवसर किसके पास हैं? क्या देश में दलित अपनी जाति के नाम से खाने पीने की दुकान चला सकते हैं जैसे शर्मा स्वीटस्, गुप्ता होटल आदि? दूसरी ओर इस देश के ज़्यादातर मज़दूर और किसान दलित, आदिवासी, मुसलमान और पिछड़ी जातियों से हैं, ये आकड़ों से साबित हो सकता है आसानी से। सरकारी आंकड़ों के हिसाब से 71% दलित खेत मज़दूरों के तौर पर काम करते हैं, उनके पास कोई ज़मीन नहीं है। निर्माण मज़दूर में काम करने के हमारे अनुभव में हमें लगभग सभी मज़दूर दलित, पिछड़े या आदिवासी मिले। सिस्टम में हर जगह सवर्णों की संख्या सबसे ज़्यादा है, ये ऊपर दिए गए आँकड़े खुद दिखा रहे हैं। लेकिन उच्च जातियों की भारत में संख्या कितनी है, किसी ने सोचा है? कई जानकारों के मुताबिक ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य कुल 15% से ज़्यादा नहीं हैं। दूसरी तरफ 2011 के सरकारी सर्वेक्षण के हिसाब से दलित 16% हैं, आदिवासी 8% हैं। वहीं अंदाज़ा ये है कि पिछड़ी जातियों और मुसलमानों को मिलाकर संख्या 54-57% के बीच है। यानि मोटे तौर पर दलित, आदिवासी, मुसलमान और पिछड़े मिलाकर 80-85% के बीच हैं या शायद और भी ज़्यादा, मतलब वे असल में भारत के बहुसंख्यक हैं। अब ऊपर के आँकड़े देखिए और सोचिए **क्या उच्च जातियों को आरक्षण देना ब्रह्मणवाद नहीं है?** इसमें एक ज़रूरी बात और है आप पिछड़ी जातियों को सिर्फ 27% आरक्षण दे रहे हैं, जबकि उनकी संख्या 50% से ज़्यादा है। वहीं आप 15% उच्च जातियों को 10% आरक्षण दे रहे हैं। इसका साफ मतलब है कि सरकारी आरक्षण से जो थोड़ा बहुत लाभ समाज के वंचितों को मिला था वो भी समाप्त होने वाला है और ये मनुस्मृति को लागू करने की शुरुवात है। ये मनुवादी कॉर्पोरेट राष्ट्र बनने की ओर लिया गया एक और कदम है।

हमारे मतभेद

- शंकर

हमारी पार्टी भाकपा-माले (रेड स्टार) की 12वीं पार्टी कांग्रेस बड़े उत्साह के साथ समाप्त हो गई है। पार्टी कांग्रेस ने सभी मसौदा दस्तावेजों को सर्वसम्मति से स्वीकार कर लिया है और कॉमरेड केएन रामचंद्रन के पद छोड़ने के साथ ही कॉमरेड पीजे को अपना नया महासचिव चुना है। कॉमरेड केएन ने दशकों तक हमारी पार्टी का नेतृत्व किया और एक छोटे से समूह से एक देशव्यापी पार्टी का निर्माण किया, जिसने पिछली सदी के सत्तर के दशक में केरल से अपनी यात्रा शुरू की थी। वर्तमान फासीवाद विरोधी संघर्ष का नेतृत्व करने और समाजवादी भारत के निर्माण के लिए आगे बढ़ने के लिए अब आने वाली पीढ़ियों की जिम्मेदारी है कि वे हमारे देश में कम्युनिस्ट क्रांतिकारियों की एक संयुक्त पार्टी विकसित करने की दिशा में आगे बढ़ें। पार्टी कांग्रेस (पीसी) ने 34 सदस्यीय केंद्रीय समिति (सीसी) और 3 सदस्यीय केंद्रीय नियंत्रण आयोग (सीसीसी) का चुनाव किया।

हालांकि, यह भी एक तथ्य है कि कुछ सीसी और पोलित ब्यूरो(पीबी) सदस्यों सहित लगभग पचास प्रतिनिधि पार्टी कांग्रेस(पीसी) से बाहर चले गए और पीसी के प्रतिनिधियों द्वारा बार-बार किए गए प्रयासों के बावजूद फिर से शामिल होने के लिए वापस नहीं आए। वास्तव में यह न तो आश्चर्यजनक था और न ही अप्रत्याशित क्योंकि यह कई वैचारिक राजनीतिक सवालों पर लगभग डेढ़ साल के आंतरिक-पार्टी संघर्ष की स्वाभाविक परिणति थी। यह संघर्ष तब शुरू हुआ जब सीसी ने पार्टी कार्यक्रम (पार्टी प्रोग्राम) या क्रांति का पथ (द पाथ ऑफ रेवोल्यूशन)जैसे मौजूदा पार्टी दस्तावेजों को अद्यतन (अपग्रेड) करने का फैसला किया। पोलित ब्यूरो ने सीसी बैठक में प्रस्तावित किया कि कुछ पीबी और सीसी सदस्यों को शामिल करके काम पूरा करने के लिए एक उप-समिति या आयोग का गठन किया जाना चाहिए। हालांकि, सीसी ने पीबी को कार्य सौंप दिया। फिर अगली पीबी बैठक में यह निर्णय लिया गया कि अपग्रेडेड पार्टी प्रोग्राम को शुरुआत में तैयार किया जाएगा। कॉमरेड पीजे जेम्स को इसे लिखने का काम सौंपा गया था और उनकी मदद के लिए कॉमरेड पीजे, कॉमरेड अलीक और कॉमरेड शंकर की मदद के लिए तीन सदस्यीय उप-समिति बनाई गई थी। उपसमिति की बैठक हुई और सर्वसम्मति से अपग्रेडेड प्रोग्राम का ढाँचा तैयार किया गया। केवल जब पहले अध्याय की रूपरेखा पर चर्चा की गई तो कॉम अलिक ने रेड स्टार के आरंभ से संक्षिप्त इतिहास को लिखने में थोड़ा विरोध व्यक्त किया। इसके बजाय उन्होंने 2009 के विशेष सम्मेलन से पार्टी के इतिहास को लिखने का सुझाव दिया जिसमें सीसीआरएमएल का एक प्रतिनिधिमंडल, उनके नेतृत्व में एक छोटा समूह शामिल हुआ और अंततः विलय हो गया। उप समिति के अन्य दो सदस्य इससे सहमत नहीं थे। इस बिंदु के अलावा उन्हें और कोई आपत्ति नहीं थी।

हालांकि, जैसे ही प्रस्तावित मसौदा दस्तावेज (पार्टी कार्यक्रम) का पहला मसौदा सीसी में रखा गया, एक कड़ा संघर्ष शुरू हो गया। कॉम प्रदीप सिंह ठाकुर (पीएसटी) ने इसके खिलाफ कई आपत्तियां उठाईं। उनके कुछ तर्कों को 'कृषि क्रांति' आदि मुद्दों से संबंधित स्वीकार कर लिया गया था। लेकिन तीन प्रमुख बिंदु धीरे-धीरे सीसी के भीतर एक बहुत ही कड़वे संघर्ष के केंद्र बन गए। सीपीआईएमएल रेड स्टार के भीतर की वर्तमान स्थिति को समझने के लिए उन बिंदुओं पर एक संक्षिप्त चर्चा आवश्यक है।

पार्टी

कॉम पीएसटी ने तर्क दिया कि पार्टी कार्यक्रम एक बहुत ही संक्षिप्त दस्तावेज होना चाहिए, अधिमानतः चार पृष्ठों के भीतर पूरा किया जाना चाहिए। यह संक्षेप में बताना चाहिए कि पार्टी वास्तव में क्या करने जा रही है। विवरण और आख्यानों को इस दस्तावेज़ में जगह नहीं मिलनी चाहिए। उनके अनुसार, चूंकि वर्तमान राजनीतिक संदर्भ में कम्युनिस्ट कार्यकर्ताओं को एक पार्टी में एकजुट करना अत्यंत महत्वपूर्ण है, इसलिए एकता के बिंदु बहुत कम होने चाहिए। अपने तर्कों को मजबूत करने के लिए उन्होंने पार्टी कार्यक्रम को लिखने के लिए लेनिन के नुस्खे का हवाला दिया, जिसे उन्होंने 1903 के वर्ष में बताया था। कॉम पीएसटी ने कॉम लेनिन के उन सुझावों को "लेनिनवादी सिद्धांतों" के रूप में पार्टी कार्यक्रम की संरचना के प्रश्न पर चित्रित किया था। उन्होंने मसौदा कार्यक्रम के खिलाफ अपनी बहस विशेष रूप से दो खंडों पर केंद्रित की, यानी रेड स्टार का इतिहास और भारत का इतिहास। उनके अनुसार पार्टी कार्यक्रम में ये दो खंड अनावश्यक हैं। कॉम अलिक ने रेड स्टार के इतिहास के प्रश्न पर कॉम पीएसटी को अपना समर्थन दिया। हालांकि, कॉम पीएसटी द्वारा प्रचारित दस्तावेज की पूरी संरचना के सवाल पर वह दृढ़ नहीं थे। कॉम पीएसटी के विचार को सीसी बैठक में पीबी के एक अन्य सदस्य कॉमरेड उमाकांत ने भारी समर्थन दिया।

यह सच है कि वर्तमान रेड स्टार विभिन्न सीपीआईएमएल और गैर-सीपीआईएमएल कम्युनिस्ट क्रांतिकारी (सीआर) समूहों के साथ बनाया गया है। हालांकि, यह भी सच है कि उन समूहों में कॉमरेड केएन के नेतृत्व वाले तत्कालीन रेड फ्लैग ने एक देशव्यापी पार्टी में विभिन्न कम्युनिस्ट क्रांतिकारी (सीआर) समूहों को एकजुट करने में अग्रणी भूमिका निभाई थी।

इसलिए, यह बहुत स्वाभाविक है कि तत्कालीन रेड फ्लैग द्वारा निभाई गई प्रमुख भूमिका उस खंड में परिलक्षित होती है जहां रेड स्टार का इतिहास लिखा गया है। इस सरल सत्य को कुछ कामरेड स्वीकार नहीं कर सकते थे, विशेष रूप से वे जो अपने संकीर्ण दृष्टिकोण के कारण शामिल हुए या बाद में विलय हो गए। उन्होंने यह आरोप लगाना शुरू कर दिया कि यह दस्तावेज़ बनाने वालों की ओर से संकीर्णता है। उन्होंने आगे तर्क दिया कि यदि इस तरह के "संकीर्ण" दृष्टिकोण को सुधारा नहीं गया था, तो एक पार्टी में सीआर बलों के एक विशाल जन को एकजुट करना संभव नहीं था। उन्होंने यह स्वीकार नहीं किया कि जो सत्य है वो सत्य है। एक कम्युनिस्ट का मूल गुण इसे स्वीकार करना है। सीआर की एकता एक ऐसी पार्टी का विकास नहीं कर सकती जहां कोई भी एक साधारण सत्य को स्वीकार नहीं करता है।

लेकिन उन्होंने इस सच्चाई को क्यों नहीं स्वीकार किया कि तत्कालीन सीआरसी और रेड फ्लैग के साथियों ने आज के सीपीआईएमएल रेड स्टार को विकसित करने में अग्रणी भूमिका निभाई है? इस सच्चाई में कुछ भी नया नहीं है और वास्तव में इस प्रश्न पर पहले कभी किसी ने गंभीर बहस नहीं की। फिर इस बार इस मुद्दे पर तीखा संघर्ष क्यों छिड़ गया? साधारण कारण यह है कि इस बार कॉमरेड केएन के महासचिव(जीएस) पद से हटने से हमारे दोस्तों को पार्टी के भीतर तीव्र संघर्ष शुरू करने का मौका मिला। पार्टी में अल्पसंख्यक होने के बावजूद कुछ कामरेडों ने खुद को जीएस की स्थिति पर कब्जा करने के लिए संघर्ष में शामिल किया, वे पार्टी के इतिहास को मिटाने के लिए बाध्य थे जो स्पष्ट रूप से पूर्ववर्ती सीआरसी और रेड फ्लैग के कामरेडों द्वारा सीपीआई (एमएल) रेड स्टार को बनाने में निभाई गई प्रमुख भूमिका को स्पष्ट करता है। यह साम्यवादी विचारधारा और नैतिकता से एक दयनीय विचलन है। इसे कोई क्रांतिकारी विचारधारा वाला पार्टी कार्यकर्ता स्वीकार नहीं कर सकता।

पार्टी के इतिहास के अलावा इस बार अद्यतन पार्टी कार्यक्रम में हमारे देश के इतिहास के एक बहुत ही संक्षिप्त विवरण को जगह मिली है। हमारे एक अन्य बुनियादी दस्तावेज, भारतीय क्रांति का मार्ग में, हमने कहा है कि अब तक भारतीय कम्युनिस्टों ने आम तौर पर अन्य देशों में कम्युनिस्ट पार्टियों के किसी एक मार्ग का अनुसरण करने की कोशिश की, जहां क्रांति सफल हुई। भारत की भूमि और भारतीय इतिहास को समझे बिना कम्युनिस्टों ने सीधे सीधे नकल करने के माध्यम से "चीनी पथ" या "रूसी पथ" को लागू करने का प्रयास किया। हालाँकि, भारतीय क्रांति केवल भारतीय पथ के माध्यम से, भारतीय मार्ग से ही सफल हो सकती है। और भारत में वर्गों की उत्पत्ति, राज्य और वर्ग संघर्ष की बुनियादी समझ के बिना कोई भी भारतीय क्रांति के पथ की वास्तविक प्रकृति को नहीं समझ सकता है।

हालाँकि, असहमति रखने वाली मण्डली के हमारे दोस्तों ने माना कि पार्टी कार्यक्रम में भारतीय इतिहास का एक संक्षिप्त विवरण भी प्रस्तुत करना बिल्कुल अनावश्यक है। तथापि उन्होंने केंद्रीय समिति के दस्तावेजों से भारतीय पथ के विचार की नकल की है, वे इसे भारतीय वास्तविकता की विशिष्टता से जोड़ने के लिए सहमत नहीं हैं और इस तरह उन्होंने भारतीय पथ में अपने विश्वास को बिल्कुल सतही बना दिया है। इसलिए, उन्होंने पार्टी के इतिहास के साथ-साथ भारतीय इतिहास के पूरे हिस्से को हटाकर अपने संशोधन पेश किए। वे कुछ सामान्य राजनीतिक सूत्र लिख कर खुश हैं जो अर्थहीन और खाली हैं।

हमारे दोस्त हमेशा खुद को फासीवाद के खिलाफ एक उत्साही लड़ाके के रूप में पेश करने की कोशिश कर रहे हैं। हालाँकि, फासीवादी हमले और पूरे राज्य और समाज को अपने कब्जे में लेने की तैयारी की पृष्ठभूमि में, फासीवाद-विरोधी संघर्ष को एक विशेष देश के इतिहास से जोड़ने का महत्व कई गुना बढ़ जाता है। हमारे दोस्तों ने फासीवाद पर कॉमरेड दिमित्रोव की रिपोर्ट के बारे में सौ बार बात की, लेकिन इसे ध्यान से पढ़ने के लिए थोड़ी तकलीफ उठाने के लिए पूरी तरह से तैयार नहीं थे। मैं फासीवाद पर कॉमरेड दिमित्रोव की रिपोर्ट से इसके खिलाफ वैचारिक संघर्ष के सवाल पर कुछ अंश उद्धृत करता हूं।

"फासीवादी हर राष्ट्र के पूरे इतिहास के माध्यम से अफवाह उड़ा रहे हैं ताकि उन सभी के उत्तराधिकारी और निरंतरता के रूप में पेश हो सकें जो अपने अतीत में महान और वीर थे, जबकि जो कुछ भी लोगों की राष्ट्रीय भावनाओं के लिए अपमानजनक या आक्रामक था, वे फासीवाद के दुश्मनों के खिलाफ हथियार के रूप में उपयोग करें। जर्मनी में सैकड़ों किताबें केवल एक ही उद्देश्य से प्रकाशित की जा रही हैं - जर्मन लोगों के इतिहास को गलत साबित करना और इसे फासीवादी रंग देना।" (जॉर्जी दिमित्रोव/द यूनाइटेड फ्रंट/पृष्ठ59)

साथियों, दिमित्रोव का अवलोकन अत्यंत महत्वपूर्ण है। हमें यह समझना चाहिए। इतिहास हमेशा से सबसे अधिक राजनीतिक रूप से भरा हुआ विषय रहा है। फासीवादी युग में यह कोई नई बात नहीं है। सभी शासक वर्गों ने हमेशा खुद को अतीत में एक राष्ट्र के सभी गौरवशाली तत्वों के सच्चे उत्तराधिकारी के रूप में पेश करने की कोशिश की।

और लोगों का जन मनोविज्ञान भी उस दिशा में काम करता है कि वे अतीत के टूटने और निरंतरता के अपने द्वंद्वात्मक चरित्र के साथ वर्तमान को महसूस करते हैं। फासीवादी ताकतें इसे अपने बुर्जुआ लोकतांत्रिक पूर्ववर्तियों से बेहतर समझती हैं। हालांकि, सामान्य तौर पर कम्युनिस्ट इस बुनियादी सामाजिक विज्ञान के महत्व को समझने में विफल रहते हैं।
दिमित्रोव ने लिखा:

"मुसोलिनी गैरीबाल्डी के वीर व्यक्तित्व से अपने लिए पूंजी बनाने का हर संभव प्रयास करता है। फ्रांसीसी फासीवादी अपनी नायिका जोन ऑफ आर्क के रूप में सामने आते हैं। अमेरिकी फासीवादी अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम की परंपराओं, वाशिंगटन और लिंकन की परंपराओं की अपील करते हैं। बल्गेरियाई फासीवादी 'सत्तर के दशक के राष्ट्रीय मुक्ति आंदोलन और लोगों के प्रिय उसके नायकों, वासिल लेव्स्की, स्टीफन कारज और अन्य का उपयोग करते हैं। (वही/ पृष्ठ 60)

साथियों, कम्युनिस्टों ने हमारे देश में अब तक क्या किया है? क्या उन्होंने खुद को गौतम बुद्ध, कबीर, रामदास, बसबन्ना और वर्ग विभाजन, शोषण, उत्पीड़न और मानव जाति के खिलाफ क्रूरता के खिलाफ लोगों के संघर्ष के कई नेताओं के सच्चे उत्तराधिकारी के रूप में पेश किया? नहीं। ज्यादातर मामलों में वे हमारे पूर्वजों के कई दोषों और सीमाओं को त्यागने की कोशिश में व्यस्त थे और केवल हाल के दिनों में कम्युनिस्टों के नेतृत्व वाले संघर्षों को महिमामंडित करने का प्रयास किया। उनके लिए इतिहास तभी शुरू हुआ जब कम्युनिस्ट मेनिफेस्टो लिखा गया। वे हमेशा हमारे देश के कम्युनिस्ट आंदोलन की शुरुआत से ही अपना पार्टी कार्यक्रम शुरू करते हैं। वे हमेशा दूसरे देशों में कम्युनिस्ट पार्टियों और कम्युनिस्ट नायकों और नायिकाओं के गौरवशाली संघर्षों के प्रचार में लगे रहते थे। हमारे देश और विदेशों में कम्युनिस्ट आंदोलनों का प्रचार और महिमामंडन निस्संदेह महत्वपूर्ण और जरूरी काम हैं। लेकिन अगर कम्युनिस्ट आंदोलन केवल ऐसा करने में ही खुद को सीमित रखता है तो एक भयानक विफलता पूरी तरह से नियत है। इसलिए कॉमरेड दिमित्रोव ने चेतावनी दी:

"कम्युनिस्ट जो यह मानते हैं कि इन सबका मजदूर वर्ग के हितों से कोई लेना-देना नहीं है, जो उन्हें प्रबुद्ध करने के लिए कुछ नहीं करते हैं"
जनता अपने लोगों के अतीत पर ऐतिहासिक रूप से सही ढंग से, सही मायने में मार्क्सवादी, लेनिनवादी-मार्क्सवादी, लेनिनवादी-स्टालिनवादी भावना में, जो वर्तमान संघर्ष को लोगों की क्रांतिकारी परंपराओं और अतीत के साथ जोड़ने के लिए कुछ भी नहीं करते हैं - स्वेच्छा से सौंप देते हैं फासीवादी मिथ्याचारियों को, ...

.....राष्ट्र के ऐतिहासिक अतीत में जो कुछ भी मूल्यवान है, उसे फासीवादी जनता को भ्रमित कर सकते हैं।" (वही)

हमारे मित्र जिन्होंने सीसी दस्तावेजों को खारिज कर दिया, दिमित्रोव का नाम कई बार लिया लेकिन फासीवाद विरोधी संघर्ष के बारे में उन्होंने जो कहा, उसका कभी अध्ययन नहीं किया। अगर वे फासिस्टों से लड़ने के लिए गंभीर रूप से इच्छुक होते तो वे इस साधारण तथ्य को समझ सकते थे जो कॉम दिमित्रोव ने कहा था (भले ही दिमित्रोव न कहें):

"कामरेडों, सर्वहारा अंतर्राष्ट्रीयतावाद, इसलिए बोलने के लिए, प्रत्येक देश में अपनी जन्मभूमि में गहरी जड़ें जमाने के लिए "स्वयं को अभ्यस्त" करना चाहिए। सर्वहारा वर्ग संघर्ष के राष्ट्रीय रूप और अलग-अलग देशों में श्रमिक आंदोलन का सर्वहारा अंतरराष्ट्रीय वाद से कोई अंतर्विरोध नहीं है। इसके विपरीत, इन रूपों में ही सर्वहारा वर्ग के अंतर्राष्ट्रीय हितों की सफलतापूर्वक रक्षा की जा सकती है।" (वही)
इसलिए, जब कॉमरेड पीएसटी ने भारतीय इतिहास से संबंधित खंड के खिलाफ कई गैर-मार्क्सवादी आपत्तियां उठाईं, तो अधिकांश सीसी सदस्यों ने इसका विरोध किया। हालाँकि, वे अपनी स्थिति पर बहुत दृढ़ थे। कॉमरेड संजय और कॉमरेड उमा समर्थन में आए। उनका तर्क था कि मूल दस्तावेज में न्यूनतम चीजें लिखी जानी चाहिए ताकि एक पार्टी में सीआर को एकजुट करना आसान हो जाए। हालांकि, सीसी के अधिकांश सदस्य इनसे सहमत नहीं थे। उनके बीच एक बहुत स्पष्ट समझ विकसित हो रही थी कि एक मार्क्सवादी-लेनिनवादी (एमएल)पार्टी के स्थान पर, ये साथी एक उदार पार्टी विकसित करने में व्यस्त थे।

विवाद का दूसरा महत्वपूर्ण बिंदु भारतीय परिप्रेक्ष्य में वर्गों की प्रकृति, वर्ग विभाजन और वर्ग संघर्ष के संबंध में था। इस बिंदु पर पार्टी की स्थिति के विरोध में कॉम अलिक ने अग्रणी भूमिका निभाई। पोलित ब्यूरो में 2019 में बहस की शुरुआत तब हुई जब कम्युनिस्ट आंदोलन और अम्बेडकरवादी आंदोलन के बीच संबंधों पर पार्टी स्कूल के लिए एक पेपर का मसौदा तैयार किया गया था। मसौदा(ड्राफ्ट)लिखने का काम कॉमरेड शंकर को सौंपा गया था। पहले मसौदे को लिखने के बाद कॉम अलिक के साथ पीबी में एक तीव्र संघर्ष शुरू हुआ, जिसे कॉम उमाकांत का समर्थन प्राप्त था।

पेपर की मुख्य अंतर्वस्तु यह थी कि भारत में वर्ग वर्णों के रूप में दिखाई देते थे। इसलिए वर्ग विभाजन वर्ण विभाजन के रूप में हुआ। हमारे देश के पूरे इतिहास में आज तक कई बदलावों के बावजूद दलित लोगों का विशाल बहुमत मूल रूप से मेहनतकश/ कामकाजी लोग हैं। इसलिए, जब अम्बेडकर ने अपना "शूद्रों का राजनीतिक संघर्ष" शुरू किया, तो यह मूल रूप से मजदूर वर्ग का संघर्ष था। उस समय की कम्युनिस्ट पार्टी (CP) मामले को इस नज़रिए से देखने में नाकाम रही थी।

परिणामस्वरूप कम्युनिस्ट आंदोलन और अम्बेडकरवादी आंदोलन के बीच एक बड़ी राजनीतिक दरार पैदा हो गई, जिसे आज हमारी सचेत राजनीतिक कार्रवाई के माध्यम से पाटना चाहिए। पार्टी को देश भर में जाति उन्मूलन आंदोलन को विकसित करने के लिए हर संभव पहल करनी चाहिए और इसे मजबूत करने के अपने प्रयासों को तेज करना चाहिए। कॉमरेड अलिक ने इस समझ का भारी विरोध किया और कहा कि अम्बेडकर के राजनीतिक समझ में कई मूलभूत दोष थे, इसलिए उस समय मुख्य रूप से कम्युनिस्ट पार्टी(सीपी)सही थी। उन्होंने एक साल बाद एक वैकल्पिक पेपर लिखा और पीबी के अन्य सदस्यों के पेपर और नोट्स/टिप्पणियां दोनों , हमारी सैद्धांतिक पत्रिका मार्क्सिस्ट -लेनिनिस्ट में 2020 में प्रकाशित हुईं। सीसी में कॉमरेड विमल एक भरे पूरे ब्राम्हणवादी दृष्टिकोण के साथ अलिक की स्थिति से सहमत थे। नतीजतन, अगले साल जब पार्टी के दस्तावेजों को अपग्रेड करने का काम हाथ में लिया गया और सीसी में पार्टी कार्यक्रम का पहला मसौदा पेश किया गया, तो कामरेड विमल ने इसका विरोध किया। अन्य बातों के अलावा, जाति का प्रश्न उनकी असहमति का एक प्रमुख बिंदु था।

वर्ग

1919 में सेवरडलोव विश्वविद्यालय के छात्रों को राज्य पर अपने व्याख्यान में, **लेनिन** ने कहा,

"..... प्रश्न इतना जटिल है और बुर्जुआ विद्वानों और लेखकों द्वारा इतना भ्रमित किया गया है कि जो कोई भी इस प्रश्न का गंभीरता से अध्ययन करना चाहता है और स्वतंत्र रूप से उस पर महारत हासिल करना चाहता है, उसे इस पर कई बार हमला करना चाहिए, बार-बार इस पर विचार करना चाहिए और ताकि विभिन्न कोणों से उठ रहे प्रश्न की विवेचना करनी है ताकि इसकी स्पष्ट और निश्चित समझ प्राप्त कर सकें।"

उन्होंने आगे कहा:

"आज तक यह प्रश्न अक्सर धार्मिक प्रश्नों के साथ भ्रमित होता है; न केवल धार्मिक सिद्धांतों के प्रतिनिधि (यह उम्मीद करना काफी स्वाभाविक है), बल्कि यहां तक कि जो लोग खुद को धार्मिक पूर्वाग्रह से मुक्त मानते हैं, वे अक्सर विशिष्ट प्रश्न को भ्रमित करते हैं धर्म के प्रश्न के साथ राज्य और एक सिद्धांत का निर्माण करने का प्रयास - अक्सर एक जटिल , एक वैचारिक, दार्शनिक दृष्टिकोण और तर्क के साथ - जो दावा करता है कि राज्य कुछ दिव्य, कुछ अलौकिक है, कि यह एक निश्चित शक्ति है, द्वारा जिसके गुण से मानव जाति जीती आई है... .."

लेनिन ने आगे कहा:

"इस प्रश्न को यथासंभव वैज्ञानिक रूप से देखने के लिए हमें राज्य के इतिहास, इसके उद्भव और विकास पर कम से कम एक क्षणभंगुर नज़र डालनी चाहिए। सामाजिक विज्ञान के एक प्रश्न में सबसे विश्वसनीय चीज, और वास्तव में क्रम में सबसे आवश्यक है इस प्रश्न पर सही ढंग से संपर्क करने की आदत प्राप्त करने के लिए और अपने आप को विस्तार के द्रव्यमान में या परस्पर विरोधी राय की विशाल विविधता में खो जाने की अनुमति नहीं देना - सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि अगर कोई इस प्रश्न को वैज्ञानिक रूप से देखता है तो अंतर्निहित ऐतिहासिक संबंध को नहीं भूलना है इतिहास में दी गई घटना कैसे उत्पन्न हुई और इसके विकास के प्रमुख चरण क्या थे, इसके विकास के दृष्टिकोण से, प्रत्येक प्रश्न की जांच करने के लिए, यह जांचने के लिए कि यह आज क्या हो गया है।"

भारतीय समाज में वर्ग विभाजन, वर्ग संघर्ष और राज्य के उद्भव पर एक सावधानीपूर्वक अध्ययन के जरिए हम देख सकते हैं कि वर्गों ने इंडो-आर्यन समाज में वर्णों का रूप ले लिया। सिंधु घाटी समाज (IVC) के बारे में अभी तक बहुत कम बातें ज्ञात हैं। इसके अलावा इसने भारत में केंद्रीय सत्ता संघर्ष में भी अपनी निरंतरता खो दी। इसलिए, वर्ग विभाजन, वर्ग संघर्ष और राज्य की उत्पत्ति को समझने के लिए हम,आर्य समाज के उत्थान और विकास पर चर्चा करने के लिए बाध्य हैं। मानव जाति के सामान्य इतिहास का सिंहावलोकन करते हुए मार्क्स और एंगेल्स ने कम्युनिस्ट घोषणापत्र में निम्नलिखित रूप से घोषित किया: "अब तक के सभी मौजूदा समाज का इतिहास वर्ग संघर्षों का इतिहास है।

फ्रीमैन और दास, पेट्रीशियन और प्लेबीयन, दास मालिक(लॉर्ड) और भूदास(सर्फ़), गिल्ड-मास्टर और जर्नीमैन, एक शब्द में, उत्पीड़क और उत्पीड़ित, एक दूसरे के लगातार विरोध में खड़े थे, एक निर्बाध, अब छिपी हुई, अब खुली लड़ाई, एक लड़ाई जो प्रत्येक समय समाप्त हो गया, या तो बड़े पैमाने पर समाज के क्रांतिकारी पुनर्गठन में, या विरोधी वर्गों के सामान्य विनाश में।"

यदि हम इस सामान्य इतिहास को भारतीय परिप्रेक्ष्य में लागू करें तो हम देखते हैं कि हमारे देश में दो गठबंधनों के बीच संघर्ष शुरू हुआ। एक तरफ ब्राह्मण-क्षत्रिय गठबंधन और दूसरी तरफ वैश्य-शूद्र गठबंधन। फ्रीमैन, स्लेव, लॉर्ड, पेट्रीशियन या प्लेबीयन का कोई निशान यहां नहीं पाया जा सकता है। वर्गविहीन समाज से वर्गविभाजित समाज तक का संक्रमण काल पूरा होने के बाद, गणतंत्रात्मक राज्य प्रणालियों जैसे शाक्य, कोलियारी आदि या गैर-ब्राह्मण/क्षत्रिय नेतृत्व वाली राजशाही राज्य प्रणालियों जैसे मौर्य के सभी प्रयोग ध्वस्त हो गए। उस स्थान पर भारत के राजनीतिक परिदृश्य में मनुवादी राज्य का उदय हुआ।

इसलिए, हमारा मसौदा पार्टी कार्यक्रम निम्नलिखित रूप से कहता है:

3.1 हमारा देश भारत, जिसमें लगभग 1.4 अरब लोग रहते हैं, दुनिया के सबसे बड़े देशों में से एक है। यह विशाल विविधताओं और जटिलताओं वाला एक बहुराष्ट्रीय, बहु-जातीय, बहुभाषी और बहु-धार्मिक देश है। सिंधु के तट पर सिंधु घाटी सभ्यता नामक एक प्राचीन सभ्यता के साथ इसका एक महान अतीत है, जो लगभग 6000 वर्ष पुराना है। उसी समय, दक्षिण भारत के विशाल भूभाग में नवपाषाणकालीन सभ्यताओं का प्रभुत्व था। सिंधु घाटी सभ्यता, जिसकी निरंतरता ने कई परिकल्पनाओं को जन्म दिया है, उसके बाद वैदिक सभ्यता नामक एक और सभ्यता आई जिसने उत्तर और मध्य भारत के संपूर्ण सामाजिक-राजनीतिक इतिहास को नया रूप दिया। अनेक टूटन के बावजूद, वैदिक सभ्यता की विरासत और निरंतरता भारतीय वर्ग संघर्ष के पाठ्यक्रम को निर्धारित करने में निर्णायक रही है।

3.2 प्रारंभ में, वैदिक सभ्यता वर्ग विहीन थी। हालाँकि, उत्पादक शक्तियों के विकास और परिणामी अतिरिक्त उत्पादन के साथ, वर्ग विभाजन भी उभरने लगा। भारतीय समाज की अनूठी विशेषता के आधार पर, वर्ग वर्णों के रूप में प्रकट हुए, और वर्ग विभाजन ने एक विशिष्ट रूप धारण किया जिसे वर्ण विभाजन कहा जाता है। इस प्रकार, प्राचीन भारत में वर्ण संघर्ष वर्ग संघर्ष के रूप में उभरा। उत्तर वैदिक काल में, ब्राह्मण और क्षत्रिय देश के विशाल भूभाग में शासक वर्ग के रूप में उभरे। इस शासक वर्ग के विरोध में, वैश्य और शूद्रों से बना एक और संयोजन भी उभरा। लोग इस बाद के संयोजन के थे, देश के असली उत्पादक और मेहनतकश लोग थे। राज्य व्यवस्था इस वर्ग विभाजन में मजबूती से स्थापित हुई, जो बाद के वैदिक काल में आर्यों के पूर्ववर्ती राजनीतिक संगठनों, सभा और समिति की जगह पर उभरी, जो लगभग पांच सौ वर्षों तक जारी रही।

3.3 इस अवधि का अंत जो मौर्य शासन के पतन के साथ मेल खाता था, मनुवादी या मनुवादी राज्य के आगमन के रूप में चिह्नित किया गया था। इस नई शासन व्यवस्था ने वर्ण-विभाजन के संस्थागतकरण और जाति व्यवस्था में इसके परिवर्तन का मार्ग प्रशस्त किया। मनुवादी राज्य की मनुवादी विचारधारा में निहित मनुवादी कानून सभी महिलाओं को शूद्र मानता था। प्राचीन भारत में उभरी यह भयंकर पितृसत्तात्मक शासन व्यवस्था आज भी बिना किसी मूलभूत परिवर्तन के जारी है। नतीजतन, जाति संघर्ष और लैंगिक संघर्ष शुरू से ही भारतीय वर्ग संघर्ष के दो अभिन्न पहलुओं के रूप में विकसित होते रहे हैं।"

आज जब हम एक फ़ासीवादी राजनीतिक माहौल में रह रहे हैं और पूरे देश के सामने मुख्य कार्य कॉर्पोरेट भगवा फ़ासीवादी ताकत से लड़ना और देश की राज्यसत्ता और समग्र राजनीतिक क्षेत्र से उखाड़ फेंकना है, तो अगर हम इस बात को नही समझ सकते कि भारतीय फासीवाद का वैचारिक आधार मूल रूप से मनुवाद है तो मनुवादी राज्य की उत्पत्ति का पता लगाने के लिए एक अध्ययन अत्यंत महत्वपूर्ण है। अन्यथा पार्टी कार्यक्रम के अद्यतन मसौदे में हम जिस अत्यंत महत्वपूर्ण निष्कर्ष पर पहुंचे हैं कि जाति संघर्ष और लैंगिक संघर्ष भारतीय वर्ग संघर्ष के दो अविभाज्य पहलू हैं, पूरी तरह से सतही होगा।

हालांकि, जब सीसी बैठक में पार्टी कार्यक्रम का मसौदा रखा गया तो कॉमरेड अलीक, कॉमरेड विमल और कॉम पीएसटी सहित कुछ कामरेड भारी विरोध के साथ सामने आए। कॉम पीएसटी का मुख्य बिंदु यह था कि पार्टी कार्यक्रम इतिहास पर चर्चा करने का स्थान नहीं था। इन सभी आख्यानों को एक अलग दस्तावेज़ में लिखा जा सकता है, लेकिन मूल दस्तावेज़ों में नहीं, क्योंकि पार्टी के सदस्यों को उन दस्तावेज़ों का पालन करना चाहिए। उनकी मंशा बहुत साफ थी। वह उन बिंदुओं को अकादमिक चर्चा के रूप में स्वीकार कर सकता है लेकिन कम्युनिस्ट क्रांतिकारी ताकतों के बीच समझौते के बुनियादी बिंदुओं के रूप में नहीं। नतीजा यह हुआ कि हमारे बीच एक बुनियादी फर्क पैदा हो गया।

कॉम अलिक ने कुछ और सवाल उठाए। उन्होंने कहा कि 'जाति संघर्ष' या 'लैंगिक संघर्ष' जैसे दस्तावेजों में जिन शब्दों का इस्तेमाल किया गया है, वे गलत हैं. क्यों? उन्होंने कहा कि वर्ग संघर्ष के मामले में एक वर्ग ने दूसरे वर्ग को सत्ता से उखाड़ फेंका। इसलिए, यदि हम "जाति संघर्ष" या "लैंगिक संघर्ष" जैसे शब्दों का उपयोग करते हैं, तो यह यह आभास दे सकता है कि कुछ जातियाँ या लिंग हैं जो प्रकृति में क्रांतिकारी हैं और कुछ अन्य जातियाँ या लिंग प्रतिक्रियावादी हैं और कम्युनिस्टों को इसका पक्ष लेना चाहिए। 'सत्तारूढ़ जाति' या 'सत्तारूढ़ लिंग' को उखाड़ फेंकने के लिए 'क्रांतिकारी जाति' या 'क्रांतिकारी लिंग'! उनके अनुसार मार्क्सवाद की इस प्रकार की विकृति मूल रूप से मार्क्सवाद का उपहास है।

इस सवाल पर थोड़ी चर्चा की जरूरत है। यांत्रिक या पारंपरिक मार्क्सवादी दृष्टिकोण से कॉम अलिक के तर्कों में कुछ भी नया नहीं है। भारतीय कम्युनिस्ट आंदोलन अपनी स्थापना के समय से ही इस जाल में फंस गया है। पिछली सदी के 30 और 40 के दशक में बढ़ते अंबेडकरवादी आंदोलन के सामने सी.पी. ने सोचा कि यह आंदोलन मजदूर वर्ग की एकता को तोड़ने वाला है। इस विचार प्रक्रिया के परिणामस्वरूप कम्युनिस्ट आंदोलन और अम्बेडकरवादी आंदोलन के बीच एक दरार पैदा हो गई। हालाँकि, हमारे देश का इतिहास बताता है कि भारतीय परिप्रेक्ष्य में तथाकथित उच्च जातियाँ मूल रूप से शासक वर्ग हैं और स्वभाव से प्रतिक्रियावादी हैं। दूसरी ओर, तथाकथित निचली जातियों में मुख्य रूप से मेहनतकश लोग शामिल हैं। इसलिए, अक्सर जाति संघर्ष वास्तव में भारतीय धरती पर वर्ग संघर्ष होते हैं। क्या इसका मतलब यह हुआ कि मजदूर वर्ग में कोई ब्राह्मण या क्षत्रिय नहीं है? स्पष्टः नहीं। जाति व्यवस्था की उत्पत्ति के इतने वर्षों के बाद मजदूर वर्ग के कतारों
में कई तथाकथित उच्च जाति के कार्यकर्ता हैं। लेकिन अगर एक ब्राह्मण कार्यकर्ता ब्राह्मण के रूप में रहता है तो वह एक क्रांतिकारी कार्यकर्ता में तब्दील होने में असफल रहेगा।
यही बात लैंगिक संघर्ष के प्रश्न पर भी लागू होती है। हम याद कर सकते हैं कि एंगेल्स ने क्या लिखा था:
"मातृ-अधिकार को उखाड़ फेंकना स्त्रीलिंग की विश्व स्तर पर ऐतिहासिक हार थी। पुरुष ने घर में भी कमान संभाली; महिला को नीचा दिखाया गया और दासता में ला दिया गया, वह उसकी वासना की दासी बन गई और बच्चे पैदा करने के लिए महज एक यंत्र बन गई। महिला की यह अपमानित स्थिति, विशेष रूप से वीर और शास्त्रीय युग के यूनानियों के बीच विशिष्ट, धीरे-धीरे हल्का और चमकीला हो गया है, और कभी-कभी हल्के रूप में ओढ़ा जाता है; किसी भी मायने में इसे समाप्त नहीं किया गया है। " (परिवार, निजी संपत्ति और राज्य की उत्पत्ति)

यह पुस्तक की एक प्रसिद्ध उक्ति है। हालांकि, कम्युनिस्ट आंदोलन में कई पुरुष कम्युनिस्ट इसके मूल संदेश पर गौर नहीं करना चाहते हैं। परिच्छेद को ध्यान से पढ़ने से यह स्पष्ट रूप से पता चलता है कि सभ्य समाज में पुल्लिंग शासक लिंग है और इस स्थिति को शांत करने और चमकाने के बावजूद समाप्त नहीं किया गया है। मर्दानापन एक सामाजिक निर्माण है। और अगर एक पुरुष कार्यकर्ता मर्दानापन और मर्द के रूप में अपने अस्तित्व को जैविक रूप से नहीं बल्कि एक सामाजिक निर्माण के रूप में दूर नहीं करता है, तो वह एक क्रांतिकारी कार्यकर्ता बनने में विफल रहेगा। इसलिए लेनिन ने चेतावनी दी थी कि अगर लैंगिकता के सवाल को ठीक से नहीं निपटाया गया, तो कम्युनिस्टों को हमेशा असभ्य के रूप में पतित होने का खतरा था।
इसलिए, "जाति संघर्ष" और "लैंगिक संघर्ष" जैसे शब्द न केवल मान्य हैं, बल्कि अत्यंत आवश्यक शब्द भी हैं जिनके बिना भारत में वर्ग संघर्ष को सही ढंग से चित्रित नहीं किया जा सकता है। हमारे दोस्तों ने कुछ अलग शब्दों का उपयोग करने का सुझाव दिया, जैसे, "जातिगत भेदभाव को खत्म करने के लिए संघर्ष" या "लैंगिक भेदभाव को खत्म करने के लिए संघर्ष" या उसके करीब कुछ। हालाँकि, वे जो तथ्य छिपाते हैं, वह यह है कि जब भी तथाकथित पिछड़ी जाति के लोग जाति आधारित भेदभाव के खिलाफ लड़ते हैं, तो वे जातियाँ जो इस भेदभाव का फल प्राप्त करती हैं, संघर्ष के सामने खड़ी हो जाती हैं और एक जाति संघर्ष शुरू हो जाता है। जेंडर के मामले में भी ऐसा ही होता है। और सबसे दिलचस्प बात वर्ग संघर्ष के मामले में भी यही होता है। मजदूर वर्ग भविष्य में दूसरा शोषक वर्ग बनने के लिए नहीं, बल्कि समाज से वर्ग भेद को खत्म करने के लिए संघर्ष करता है। फिर हमारे विद्वान मित्र इस संघर्ष को "वर्ग विभाजन को मिटाने का संघर्ष" या ऐसा ही कुछ क्यों नहीं कहते? क्या इसलिए कि मार्क्स ने इस संघर्ष को वर्ग संघर्ष बताया? या, क्या यह इस तथ्य के कारण है कि "वर्ग संघर्ष" शब्द हमारे ब्राह्मण लड़कों के लिए उनके सामाजिक अस्तित्व में गैर विषैले और हानिरहित साबित होता है?

संयुक्त मोर्चा

हमारी बहस का तीसरा बिंदु फासीवाद-विरोधी संयुक्त मोर्चे की प्रकृति और हमारा कार्य है। वर्ष 2014 से यह प्रश्न सीआर की बहसों, चर्चाओं और मतभेदों के केंद्र में बना हुआ है। हमारी पार्टी ने 2018 में बैंगलोर में आयोजित पार्टी कांग्रेस के राजनीतिक प्रस्ताव के दस्तावेज में एक नारा दिया, जिसमें स्वतंत्र वामपंथी पहल के आधार पर फासीवादी ताकतों को हराने का आह्वान किया गया था। उस समय से, तीन कार्यों को हाथ में लिया गया था, अर्थात्, पार्टी निर्माण, फासीवाद-विरोधी व्यापक मोर्चे के भीतर एक वाम कोर विकसित करना और फासीवाद-विरोधी व्यापक मोर्चे का निर्माण करना। कॉम पीएसटी ने उस समय इस नारे का विरोध किया था। उन्होंने कहा कि फासीवाद-विरोधी व्यापक संभव संयुक्त मोर्चा बनाना सीआर के सामने पहला और सबसे महत्वपूर्ण कार्य था। कॉम पीएसटी के लिए व्यापक संभव फासीवाद विरोधी मोर्चे का क्या अर्थ था। उन्होंने जोर देकर कहा कि पार्टी को कांग्रेस, विभिन्न क्षेत्रीय दलों, सीपीआईएम और अन्य वाम दलों सहित सभी भाजपा विरोधी दलों के साथ और जाहिर तौर पर अन्य सीआर पार्टियों के साथ एक संयुक्त मोर्चा बनाने का प्रयास करना चाहिए। दिलचस्प बात यह है कि उन्होंने बंगाल की टीएमसी को इस लिस्ट से बाहर कर दिया। बंगाल राज्य समिति की कई बैठकों में उन्होंने कहा कि टीएमसी भी एक फासीवादी पार्टी थी! कॉम पीएसटी ने आगे कहा, चूंकि फासीवाद-विरोधी व्यापक संभव मोर्चा बनाना आज का एजेंडा है, इसलिए पार्टी को उन पार्टियों की आलोचना करने से बचना चाहिए।

दूसरी ओर, कॉम अलिक की राय कॉम पीएसटी के 180 डिग्री विपरीत थी। उनकी समझ के अनुसार, फासीवादी अधिग्रहण एक अतिशयोक्ति है। निस्संदेह भाजपा/आरएसएस फासीवादी पार्टी है। लेकिन फासीवादी पार्टी के सत्ता में आने का मतलब यह नहीं है कि राज्य फासीवादी है। इसलिए हमें फासीवाद-विरोधी व्यापक मोर्चा बनाने के लिए पीछे भागने की बजाय अपनी खुद की पार्टी बनाते रहना चाहिए। हमें इस पर ध्यान देना चाहिए। यह कॉम अलिक की स्थिति थी। यह ध्यान दिया जाना चाहिए कि 2018 की पार्टी कांग्रेस द्वारा तैयार किए गए पूरे कार्य को कोई भी समझ नहीं सका। कॉम पीएसटी ने इसका एक हिस्सा पकड़ लिया और बाकी हिस्सों को छोड़ दिया। यह सही विचलन /भटकाव का एक उदाहरण है। दूसरी ओर कॉम एलिक ने उस कार्य के दूसरे भाग को पकड़ लिया जिसे कॉम पीएसटी ने छोड़ दिया था, लेकिन दूसरा भाग छोड़ दिया, अर्थात् फासीवाद-विरोधी कार्य। यह वाम विचलन का एक उदाहरण है।

इस पृष्ठभूमि में जब पीसी दस्तावेजों का मसौदा तैयार करने का काम हाथ में लिया गया था, कॉम अलिक को राजनीतिक प्रस्ताव (पीआर) का मसौदा तैयार करने का काम सौंपा गया था। राजनीतिक प्रस्ताव वह दस्तावेज है जिसमें पार्टी अगले तीन वर्षों के लिए अगले कांग्रेस तक अपने कार्य के बारे में कहती है। कॉम अलिक ने फासीवाद विरोधी कार्य के संबंध में पूरे दस्तावेज़ में केवल एक ही पंक्ति लिखी थी। इसलिए, स्वाभाविक रूप से पोलित ब्यूरो में बहस छिड़ गई। बहरहाल, कॉमरेड अलीक इतने अड़ गए कि बहस ने उग्र रूप ले लिया। कॉम अलिक और कॉम उमाकांत को छोड़कर लगभग सभी पीबी सदस्यों ने कहा कि मसौदा पीआर अन्य दस्तावेजों के अनुरूप नहीं था। अल्पसंख्यक होने के कारण कॉम अलिक अन्य दस्तावेजों के अनुरूप दस्तावेज़ को फिर से लिखने के लिए सहमत हुए। हालांकि, दोहराव के प्रयासों के बावजूद उन्होंने इसे अन्य तीन दस्तावेजों की भावना के अनुसार कभी नहीं लिखा। परिणामस्वरूप पीबी को इस दस्तावेज़ को सीसी में यह उल्लेख करने के लिए मजबूर होना पड़ा कि यह अलिक का दस्तावेज़ था, पीबी का नहीं। सीसी में पूरी चर्चा के बाद यह निर्णय लिया गया कि दस्तावेज़ को फिर से लिखने के लिए पीबी मामले को आगे उठाएगा। इस बार कॉमरेड अलीक के साथ टकराव की एक श्रृंखला हुई, जिसने दिखाया कि पार्टी के भीतर कुछ महत्वपूर्ण कामरेडों के रवैये में बदलाव आ रहा था। इस बार जनवादी केंद्रीयता को जबरदस्ती तोड़ने का प्रयास स्पष्ट होने लगा।

अलग-अलग राज्यों में एक-एक करके राज्य सम्मेलन शुरू होने के बाद दिलचस्प घटनाक्रम होने लगे। इस समय तक सीसी ने सभी दस्तावेजों को स्वीकार कर लिया, उन्हें सभी सदस्यों और यहां तक कि पार्टी के बाहर भी सुझाव और संशोधन आमंत्रित करते हुए परिचालित किया, विभिन्न भाषाओं में दस्तावेजों का अनुवाद किया गया और राज्य सम्मेलन शुरू हुए। उस समय केवल सात सीसी सदस्यों और एक केंद्रीय नियंत्रण आयोग के सदस्य ने महासचिव के माध्यम से सीसी को एक संयुक्त पत्र भेजा जिसमें कहा गया था कि पार्टी का नेतृत्व इसे गलत दिशा में ले जा रहा है और ये कामरेड पार्टी को सही दिशा में वापस लाने का प्रयास करेंगे। इसलिए, वे वैकल्पिक दस्तावेज देंगे। यह जुलाई के पहले सप्ताह में हुआ था।

यह बहुत दिलचस्प था कि कॉम पीएसटी और कॉम अलिक दोनों ने उपर्युक्त पत्र पर हस्ताक्षर किए। हालाँकि, तथ्य यह था कि सभी राजनीतिक प्रश्नों में उनके विचार विपरीत थे। प्रमुख राजनीतिक प्रश्नों पर विपरीत विचार रखने वाले साथियों का समूह वैकल्पिक दस्तावेज कैसे दे सकता है? लेकिन उन्होंने घोषणा की कि वे उन्हें तैयार करने के लिए काम कर रहे हैं।

अंत में उन्होंने अपने वैकल्पिक दस्तावेज पार्टी कांग्रेस के सामने केवल बीस दिन पहले रखे। यह देखा गया कि कॉम अलिक ने फासिस्ट विरोधी मोर्चे के प्रश्न के मामले में कॉम पीएसटी के आगे आत्मसमर्पण कर दिया है। यह वही अलिक थे जो कभी भी पीबी में अपनी स्थिति बदलने के लिए सहमत नहीं हुये और उसी प्रश्न पर बहुमत को स्वीकार करने से इनकार कर दिया। अब इसी कॉमरेड ने अपनी स्थिति बदल ली और सहयोगी कॉम पीएसटी और कॉमरेड संजय के पक्ष में विपरीत *180* डिग्री पर पहुंच गया। पीबी और सीसी इनके वैकल्पिक दस्तावेजों को स्वीकार करने के लिए सहमत नहीं थे। सीसी ने सुझाव दिया कि वे पार्टी कांग्रेस में बहस और मतदान के लिए दस्तावेजों के बजाय अपने संशोधन भेजें। चूंकि कोई अन्य विकल्प नहीं था, इसलिए उन्होंने ऐसा किया।

अपने संशोधनों में उन्होंने सीसी दस्तावेजों के उन सभी हिस्सों को हटा दिया जहां संसदीय वाम, कांग्रेस आदि सहित अन्य राजनीतिक दलों की आलोचना की गई थी। इसके पीछे तर्क वही पुराना था जो कॉम पीएसटी और कॉमरेड संजय ने बहुत पहले दिया था। ग़ैर-फ़ासीवादी बुर्जुआ और निम्न-बुर्जुआ ताकतों पर हमारा राजनीतिक हमला फासीवाद-विरोधी मोर्चा विकसित करने के लिए हानिकारक है।

इस प्रश्न पर हमारी स्थिति बहुत स्पष्ट थी। निस्संदेह हमें गैर-फासीवादी बुर्जुआ और निम्न-बुर्जुआ ताकतों के साथ व्यापक आधार पर फासीवाद-विरोधी मोर्चा बनाना है, लेकिन गैरआलोचनात्मक रूप से नहीं। हमें उनकी नवउदारवादी नीतियों, उनके नरम हिंदुत्व और उनके जनविरोधी कार्यक्रमों का विरोध और आलोचना करनी चाहिए। यदि हम ऐसा नहीं करते हैं तो फासीवाद-विरोधी मोर्चे पर मजदूर वर्ग का नेतृत्व स्थापित नहीं किया जा सकता और जिसके बिना फासीवाद-विरोधी संघर्ष में यह मोर्चा बेकार है। यह आत्मसमर्पण करने वाला रवैया फासिस्टों को नहीं रोक सकता। इसलिए दिमित्रोव ने निम्नलिखित कहा:

"यह सब, हालांकि, इस तथ्य के महत्व को कम नहीं करते हैं कि, फासीवादी तानाशाही की स्थापना से पहले, बुर्जुआ सरकारें आमतौर पर कई प्रारंभिक चरणों से गुजरती हैं और कई प्रतिक्रियावादी तरीकों को अपनाती हैं,

जो सीधे फासीवाद की सत्ता तक पहुंच की सुविधा प्रदान करते हैं। जो कोई बुर्जुआ वर्ग के प्रतिक्रियावादी उपायों और इन प्रारंभिक चरणों में फासीवाद के विकास से नहीं लड़ता है, वह नहीं है फासीवाद की जीत को रोकने की स्थिति में नहीं रहता, बल्कि, इसके विपरीत, उस जीत को सुगम बनाता है।" *(वही)*

फासीवाद विरोधी मोर्चे के प्रश्न में हमारे मित्रों की राजनीतिक स्थिति वास्तव में विलोपवादी है। फासीवादी प्रभुत्व के युग में, पार्टी के अंदर घबराया हुआ निम्न-बुर्जुआ ,पूंजीपति वर्ग के पीछे छिपने की कोशिश कर रहा है और मजदूर वर्ग के नेतृत्व को स्थापित करने और मोर्चे पर पहल करने के हमारे प्रयासों को आत्मसमर्पण करने के लिए तैयार है। इसे कोई क्रांतिकारी विचारधारा वाला पार्टी कार्यकर्ता स्वीकार नहीं कर सकता।

बाद के विकास

हमारे दोस्त विलाप कर रहे हैं कि पार्टी में लोकतंत्र नहीं है! हालांकि, तथ्य यह है कि उन्हें पिछले डेढ़ साल से पार्टी कमेटी के भीतर सभी प्रमुख राजनीतिक मुद्दों पर बहस करने और चर्चा करने का पूरा मौका मिला है। अंत में कुछ मतभेद अभी भी मौजूद थे जिन्हें उन्होंने पार्टी कांग्रेस में लड़ने का फैसला किया। हमारी पार्टी में पार्टी कांग्रेस की सहमत प्रक्रियाओं के अनुसार पीसी के समय में तीन प्लेटफार्मों के माध्यम से अपनी राय स्थापित करने के लिए संघर्ष किया जा सकता है। यह संबंधित पार्टी समितियों में, राज्य सम्मेलनों या जिला सम्मेलनों में और पीसी में संशोधन के माध्यम से किया जा सकता है। पीसी की सहमत प्रक्रिया के अनुसार कोई वैकल्पिक दस्तावेज भी दे सकता है यदि कम से कम एक तिहाई सीसी सदस्य समर्थन करते हैं। दूसरे, चूंकि वैकल्पिक दस्तावेजों को केंद्रीय दस्तावेज माना जाता है, इसलिए उन पर राज्य सम्मेलनों में भी चर्चा की जानी चाहिए। हालांकि, हमारे दोस्तों ने सभी राज्य सम्मेलनों के पूरा होने के बाद अपने दस्तावेज रखे। उन्होंने तर्क दिया कि वैकल्पिक दस्तावेज किसी भी समय दिए जा सकते हैं, यहां तक कि सीधे पार्टी कांग्रेस के मंच पर भी। चूंकि हमारे संविधान में इस मामले में विशेष और स्पष्ट निर्देशों का अभाव है और हमें सामान्य प्रक्रिया का पालन करने की आदत है, इस समय अचानक वे बहस करने लगे कि चूंकि संविधान में कोई स्पष्ट निर्देश नहीं लिखा गया है, वे कुछ भी कर सकते हैं। पार्टी कांग्रेस के पहले पिछली सीसी बैठक में कांग्रेस में चर्चा के लिए अपने दस्तावेजों को स्वीकार करने के उनके प्रस्ताव को 8-14 मतों से पराजित किया गया था। फिर उन्होंने संशोधन के रूप में वैकल्पिक दस्तावेजों को तोड़ा और उन्हें पीसी पर चर्चा के लिए प्रस्तुत किया।

अन्य सभी संगठनों की तरह हमारी पार्टी में भी बहस और मतभेद कोई नई बात नहीं थी। हालांकि इस बार कुछ कामरेडों के रवैये में अहम बदलाव साफ तौर पर देखा गया। लगभग सभी प्रमुख प्रश्नों में भिन्न-भिन्न मत रखने वाले कामरेड केंद्रीय समिति के भीतर एक गुट बनाने के करीब आ गए और काफी मजबूती से आगे बढ़ने लगे। उनका तर्क था कि पीसी के समय हर चीज की अनुमति है। उनके जोरदार शोरगुल/प्रदर्शन की प्रतिक्रिया के रूप में जब पीबी या सीसी में बहुसंख्यक हिस्से ने उन्हें रोकने की कोशिश की तो वे रोने लगे, 'देखो, पार्टी में लोकतंत्र नहीं है'! मिसाल के तौर पर ,केंद्रीय कमिटी ने यह निर्णय लिया था कि पार्टी कांग्रेस के समक्ष वैकल्पिक दस्तावेजों को पेश नहीं किया जाएगा।निश्चित रूप से इस पर बहस हुई मगर बहुमत के द्वारा यह निर्णय लिया गया।जनवादी केंद्रीयता के मूलभूत नियम के अनुसार जब मतविभाजन के जरिए कोई निर्णय अगर लिया जाता है तो वह फिर बहुमत का निर्णय नहीं कहलाता बल्कि पूरी कमिटी का निर्णय कहलाता है।हालांकि केंद्रीय कमिटी के निर्णय का उल्लंघन करते हुए कॉमरेड अलिक ने वैकल्पिक दस्तावेजों को सोशल मीडिया के सभी ग्रुप में डाल दिया जहां कई गैर पार्टी सदस्य भी मौजूद हैं।ये पार्टी विरोधी गतिविधि का एक उदाहरण है। पिछले सात महीनों के इस पूरे प्रकरण में तीखी बहस हुई और सबसे अधिक समस्या यह रही कि अल्पसंख्यकों ने बहुमत को मानने से इनकार कर दिया। एक गंभीर संकट धीरे-धीरे सामने आ रहा था। अंत में, बहुमत हिस्सा यह निर्णय लेने के लिए बाध्य था कि अध्यक्ष मंडल और संचालन समिति, पार्टी कांग्रेस को चलाने के लिए दो सबसे महत्वपूर्ण समितियाँ, दोनों विरोधी विचारों के साथियों के साथ नहीं बनाई जा सकतीं। तदनुसार उन समितियों का एक पैनल पिछले सीसी में रखा गया था। इस सवाल पर सीसी में एक बार फिर तीखी बहस छिड़ गई। अंत में इस प्रश्न में भी मतदान कर अल्पसंख्यक हिस्से को फिर से हार का सामना करना पड़ा।

कांग्रेस ने 24 सितंबर को रैली और जनसभा के साथ शुरुआत की। जनसभा के मंच से अल्पसंख्यक हिस्से के नेता अपने-अपने विचारों का प्रचार-प्रसार करने लगे।

कम्युनिस्ट क्रांतिकारियों के मंच रेड स्टार को पढ़ें और वर्ग संघर्ष के हित में प्रचार-प्रसार करें।
जुड़ने और मदद करने के लिए संपर्क करें:
मोबाइल नंबर: 9425560952
ऑफिस फोन: 011-41056622
ईमेल: redstarhindi@gmail.com
आर्थिक मदद के लिए:
गूगल पे नंबर: 8714336875
यूपीआई: *kabeerkatlat@okicici*

और अगले दिन जब उद्घाटन समारोह के बाद प्रतिनिधि सत्र शुरू हुआ तो अल्पसंख्यक हिस्से ने हल्ला गुल्ला और अराजकता का सहारा लिया। कॉमरेड केएन, निवर्तमान महासचिव अध्यक्ष मंडल (प्रेसीडियम)और संचालन समिति के पैनल का प्रस्ताव कर रहे थे। हालाँकि, उन्हें उस स्थिति की व्याख्या करते हुए कुछ शब्द कहने पड़े कि जिसने सीसी को इस तरह का एकतरफा पैनल लगाने के लिए मजबूर किया।तुरंत साथियों का एक झुंड खड़ा हो गया और चिल्लाना शुरू कर दिया और उन्होंने मंच के सामने एक प्रदर्शन करना शुरू किया। कॉम पीएसटी ने पूरे प्रकरण का नेतृत्व किया जो अंततः उन लोगों के पार्टी कांग्रेस से बाहर निकलने के साथ समाप्त हुआ।

उस दुर्भाग्यपूर्ण घटना के बाद पार्टी कांग्रेस ने उन्हें कांग्रेस में वापस लाने के लिए बार-बार प्रयास किए लेकिन उस हिस्से के अड़ियल नेताओं ने कुछ प्रस्ताव दिए जो मूल रूप से चल रहे पीसी को अन्यायपूर्ण, अमान्य और शून्य घोषित करने के समान थे। स्पष्ट कारणों से पीसी इससे सहमत नहीं हो सका। उल्लेखनीय है कि पिछली सीसी बैठक में दोनों हिस्सों के सभी प्रमुख साथियों को शामिल करते हुए अगली सीसी के एक पैनल को स्वीकार किया गया था। हालांकि, उनकी अनुपस्थिति और कांग्रेस के बहिष्कार में उनके बिना एक सीसी पैनल रखा जाना था जिसे सर्वसम्मति से अपनाया गया था।

पार्टी कांग्रेस के बाद अल्पसंख्यक हिस्से ने संदेश दिया कि वे नवनिर्वाचित सीसी की पहली बैठक तक इंतजार करेंगे और उसके बाद वे अपनी भविष्य की कार्रवाई तय करेंगे।

शंकर
16.10.2022

पुनश्च/संप्रति - जब यह आलेख लिखा गया था तब से आज तक की स्थिति में बहुत बदलाव आया है। हालिया स्थिति यह है कि इन साथियों ने चेन्नई में बैठक कर अलग संगठन (भाकपा माले क्रांतिकारी पहल) बना लिया है। तदनुसार पार्टी विरोधी गतिविधियों के लिए पहले, पुराने रेड स्टार की केंद्रीय कमिटी के सात साथियों (प्रदीप सिंह ठाकुर, संजय सिंघवी, उमाकांत, विमल त्रिवेदी, सूर्यम, प्रवीण नाडकर, अलिक चक्रवर्ती) और फिर कॉमरेड बाबूराम शर्मा को पार्टी से निष्कासित किया गया है।

छत्तीसगढ़

आंगनबाड़ी कार्यकर्ता सहायिका संयुक्त मंच का सांभागीय स्तर का कार्यक्रम संपन्न, अनिश्चित कालीन हड़ताल की चेतावनी :-

आंगनबाड़ी कार्यकर्ता-सहायिका संयुक्त मंच के नेतृत्व में सरकार की वादा खिलाफी के विरुद्ध छत्तीसगढ़ के पांचों संभागों में धरना,सभा,रैली वा ज्ञापन प्रधानमंत्री,मुख्यमंत्री, महिला एवं बाल विकास विभाग के सचिव, संचालक,आयुक्त एवं मुख्य सचिव को दिया गया। 09 सितम्बर को बिलासपुर, 23 सितम्बर को बस्तर जगदलपुर, 12अक्टूबर को सरगुजा जिले के अम्बिकापुर, 31अक्टूबर को दुर्ग एवं 17 नवंबर को रायपुर के बूढातालाब धरना स्थल पर हजारो के तादाद में कार्यक्रम में भाग लिया। "भूपेश बघेल की कांग्रेस सरकार वादा निभाओ " नारे के साथ प्रदर्शन किया गया। भूपेश बघेल की सरकार, फासिस्ट मोदी सरकार जैसे जुमले बाजी करना बंद करें, वर्ना रमन सिंह की सरकार जैसी हाल हो जाएगी, संयुक्त मंच-में शामिल यूनियन प्रगतिशील आंगनबाड़ी कार्यकर्ता सहायिका संघ की अध्यक्ष हेमा भारती, छत्तीसगढ़ आंगनबाड़ी कार्यकर्ता सहायिका संघ की प्रान्तीय अध्यक्ष सरिता पाठक, छत्तीसगढ़ प्रदेश आंगनबाड़ी महिला कार्यकर्ता सहायिका संघ की प्रांतीय अध्यक्ष कॉमरेड रुक्मणी सज्जन, एवं संघर्षशील आंगनबाड़ी कार्यकर्ता सहायिका संघ की अध्यक्ष कल्पना चंद्रा, देवेंद्र पटेल, कॉमरेड सौरा, विश्वजीत हरोडे, भारत भूषण, चन्द्रशेखर पांडये, पिंकी ठाकुर, पार्वती यादव, रुक्मणी साहू, सुनीता, सुमन यादव, कविता यादव और अन्य जिला के प्रमुख साथियों ने संभगीय कार्यक्रमो में मुख्य भूमिका अदा किया।

आज के कार्यक्रम में छत्तीसगढ़ जुझारू आंगनबाड़ी कार्यकर्ता संघ के प्रमुख पदमा साहू, भुनेश्वरी तिवारी, सुधा रात्रे एवं अन्य कार्यकर्ताओं ने भाग लिया।

प्रदेश में 45हजार आंगनबाड़ी केंद्रों में लगभग एक लाख कार्यकर्ता-सहायिका वर्ष 1975 से राज्य शासन के महिला बाल विकास विभाग के अधीन कार्यरत है। गर्भधारण से लेकर प्रसूति, गर्भवति महिलाओं का टिकाकरण, जांच एवं डिलवरी, उसका आहार एवं पूरक पोषण, बच्चों का वजन एवं टीकाकरण, सभी बच्चों 0 से लेकर 6 वर्ष के उनका पूरक पोषण आहार, अनौपचारिक शिक्षा आहार, कुपोषण से बचाव, सुपोषण, गोद भराई, अन्नप्रासन, बालभोज, दत्तकपुत्री सुपोषण योजना, बालमित्र बनना, स्व सहायता समूह बनना, मुख्यमंत्री कन्या विवाह, शाला प्रवेशोत्सव, सुपोषण चौपाल, बाल संदर्भ, अमृत दूध योजना, महतारी जतन, पालक बैठक जैसे कई योजनाओं पर काम करती हैं। साथ ही इससे संबंधित तमाम रजिस्टरों को दिन-रात बैठकर भरना भी पड़ता है। इसके अलावा अन्य विभागों के कार्यों में राशन कार्ड बनाना, राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा एवं मुख्यमंत्री स्वास्थ्य बीमा (स्मार्ट कार्ड) बनवाना, अपने एरिया में क्लोरिन-फाइलेरिया की गोली बांटना, पल्स पोलियो, निर्वाचन आयोग में बीएलओ जनगणना, आर्थिक सर्वेक्षण, स्वच्छ भारत के तहत शौचालय का सर्वे, पशु सर्वे, नगर स्वराज, ग्राम स्वराज, किशोरी बालिकाओं की देखरेख, 11 से 16 वर्ष को विटामिन गोली वितरण, रोज गृह भेंट देना, विधवा परित्यागता सर्वे करना, मातृमृत्यु दर को रोकना, आयुष्मति योजना.....

इसी प्रकार केंद्र के अंदर आने वाले हितग्रहियों का देखरेख और संरक्षण इन समस्त कार्यों को करना व माह में सुपरवाइजर के माध्यम से परियोजना अधिकारी द्वारा राज्य शासन को रिपोर्ट भेजना, महतारी जतन योजना के तहत थाली सजा कर गर्भवती को परोसने का कार्य सहायिकाओं को दिया गया। सभी कार्यकर्ता-सहायिका पूर्व में चार घंटे कार्य करते थे, लेकिन अब उसे बढ़ा कर छह से आठ घंटे कर दिया गया है। कई बार तो 8-10 घंटे भी काम करना पड़ता है।

चुनाव के पूर्व कांग्रेस ने अपने घोषणापत्र में वादा किया था कि सरकार बनने पर आंगनबाडी कार्यकर्ताओं का नर्सरी शिक्षक के रुप में उन्नयन किया जायेगा और कलेक्टर दर पर वेतन दिया जायेगा। किन्तु सरकार बनने के तीन साल बाद भी भूपेश बघेल की कांग्रेस सरकार ने अपना वादा नहीं निभाया है। छत्तीसगढ़ की महिलाओं के श्रम के साथ इतना बड़ा खिलवाड़ और किसी राज्य में नहीं दिखलाई दे रहा है। इस बात को लेकर अनेक बार प्रदेश की आंगनबाड़ी कार्यकर्ता एवं सहायिकाओं ने धरना-प्रदर्शन कर शासन-प्रशासन को मांग पत्र दिया जा चुका है, लेकिन हर बार केवल आश्वासन देकर हमारे साथ खिलवाड़ किया जा रहा है एवं अनिश्चितकालीन हड़ताल के लिए सरकार हमें मजबूर कर रही है। आंगनबाड़ी में कार्यरत सभी यूनियनो ने विगत 16 नवम्बर को रायपुर में एक बैठक आयोजित किया और निर्णय लिया है है कि पांचो संभागीय कार्यक्रम के बाद एक बार पुनः शासन प्रशासन के साथ चर्चा किया जाएगा अगर मांग नही मानी गई तब आगामी दिसंबर माह में आंदोलन की रुप रेखा तैयार कर जनवरी के अंत में या फरवरी के प्रथम सप्ताह में अनिश्चित कालीन हड़ताल में जाने का ऐलान किया है।आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं एवं सहायिकाओं की मांगे:-

- शिक्षाकर्मियों की तरह आंगनबाडी कार्यकर्ताओं एवं सहायिकाओं को भी शासकीय कर्मचारी घोषित किया जाये एवं मध्यप्रदेश शासन की तरह 10,000 रुपये प्रतिमाह दिया जाये।
- मिनि आंगनबाडी को पूर्ण आंगनबाडी बनाया जाये।
- सुपरवाइजर के रिक्त पदों को वरिष्ठता क्रम के आधार पर कार्यकर्ताओं से ही शीघ्र भरा जाये।
- कार्यकर्ता के रिक्त पदों को सहायिकाओं से ही भरा जाये तथा 25 प्रतिशत के बंधन को समाप्त किया जाये।
- मासिक पेंशन, ग्रेच्युटी एवं समूह बीमा का लाभ दिया जाये।
- मोबाईल, नेट चार्ज और मोबाइल भत्ता दिया जाये। भत्ता जब तक प्रदान न हो, तब तक बी.एल.ओ सहित कोई भी मोबाईल संबंधी कार्य न लिया जाये।
- आंगनबाडी कार्यकर्ताओं, सहायिकाओं की सेवा के दौरान असामयिक मृत्यु होने पर परिवार के एक सदस्य को अनुकम्पा नियुक्ति दिया जाये।
- आंगनबाडी सह क्रेश कार्यकर्ताओं को आंगनबाडी कार्यकर्ता के रुप में नजदीकी केन्द्र में तत्काल समायोजित किया जाये।

छत्तीसगढ़

केन्द्र सरकार की वादाखिलाफी के विरोध में किसानों ने राष्ट्रपति के नाम राज्यपाल को सौंपा ज्ञापन

संयुक्त किसान मोर्चा के देशव्यापी आह्वान पर छत्तीसगढ़ किसान मजदूर महासंघ, संयुक्त किसान मोर्चा दिल्ली से जुड़े किसान संगठनों ने संयुक्त रूप से केंद्र सरकार द्वारा किसानों से किए गए वादाखिलाफी और न्यूनतम समर्थन मूल्य की कानूनी गारंटी समेत अन्य मांगों पर राज्यपाल छत्तीसगढ़ को राष्ट्रपति के ज्ञापन पत्र सौंपा है। *26* नवम्बर को छत्तीसगढ़ किसान मजदूर महासंघ के संयोजक मंडल सदस्य तेजराम विद्रोही, जनकलाल ठाकुर, पारसनाथ साहू, हेमंत कुमार टंडन, अखिल भारतीय क्रांतिकारी किसान सभा के उपाध्यक्ष मदन लाल साहू, छत्तीसगढ़ किसान महासभा के संयोजक नरोत्तम शर्मा, जिला किसान संघ बालोद के अध्यक्ष गैंद सिंह ठाकुर, छत्तीसगढ़ मुक्ति मोर्चा के सदस्य नवाब जिलानी, भारतीय किसान यूनियन छत्तीसगढ़ प्रभारी प्रवीण श्योकंड, कृष्णा नरवाल, राजधानी प्रभावित किसान कल्याण समिति के अध्यक्ष रूपन लाल चन्द्राकर, गिरधर पटेल, फुलेश बारले, ललित यादव, आदिवासी भारत महासभा के संयोजक सौरा, क्रांतिकारी सांस्कृतिक मंच के महासचिव तुहिन, जहुर राम साहू, मदन साहू, सिख संगठन रायपुर से पलविंदर सिंह पन्नू, हरिंदर सिंह संधू, मूलक सिंह, सतनाम सिंह, बिसहत कुर्रे, आदि के नेतृत्व में डॉ भीमराव अंबेडकर प्रतिमा में माल्यार्पण कर राजभवन तक पैदल मार्च कर ज्ञापन सौंपा जिसमें राष्ट्रपति को सम्बोधित करते हुए कहा कि आज, संविधान दिवस के अवसर पर, देश भर के किसान अपने-अपने राज्यों के राज्यपाल महोदय के माध्यम से आपको केंद्र सरकार द्वारा किसानों से किए गए वायदे याद दिला रहे हैं। जैसा कि आपको ज्ञात होगा, संयुक्त किसान मोर्चा ने *21* नवंबर *2021* को केंद्र सरकार को लिखे चिट्ठी में अपने छह लंबित मुद्दों की तरफ सरकार का ध्यान आकृष्ट किया था। इसके जवाब में कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय के सचिव श्री संजय अग्रवाल ने *9* दिसंबर *2021* को संयुक्त किसान मोर्चा के नाम एक पत्र *(*सचिव*/* ऐएफडब्लू*/2021/*मिस*/1)* लिखा। इस पत्र में उन्होंने कई मुद्दों पर सरकार की ओर से आश्वासन दिया और आंदोलन को वापस लेने का आग्रह किया था। सरकार की इस चिट्ठी पर भरोसा कर संयुक्त किसान मोर्चा ने दिल्ली की सीमा पर लगे मोर्चा और तमाम धरना प्रदर्शनों को *11* दिसंबर *2021* को उठा लेने का निर्णय किया था। आज दस महीने बाद भी केंद्र सरकार ने किसानों से किए गए वायदे पूरे नहीं किए हैं।

हम आपसे एक बार पुनः अनुरोध करते हैं कि आप केन्द्र सरकार से लंबित मांगों को हल करने के लिए तुरंत ठोस कदम उठाने और किसानों की समस्याओं पर ध्यान देते हुए निम्नलिखित मांगों को पूरा करने का आग्रह करें।

- स्वामीनाथन आयोग की सिफारिश के आधार पर सभी फसलों के लिए सी *2* धन *50* फीसदी के फार्मूला से एमएसपी की गारंटी का कानून बनाया जाए। केन्द्र सरकार द्वारा एमएसपी पर गठित समिति व उसका घोषित ऐजेंडा किसानों द्वारा प्रस्तुत मांगों के विपरीत है। इस समिति को रद्द कर, एमएसपी पर सभी फसलों की कानूनी गारंटी के लिए, किसानों के उचित प्रतिनिधित्व के साथ, केंद्र सरकार के वायदे के अनुसार एसकेएम के प्रतिनिधियों को शामिल कर, एमएसपी पर एक नई समिति का पुनर्गठन किया जाए।

- खेती में बढ़ रहे लागत के दाम और फसलों का लाभकारी मूल्य नहीं मिलने के कारण 80 फीसदी से अधिक किसान भारी कर्ज में फंस गए हैं, और आत्महत्या करने को मजबूर हैं। ऐसे में, आपसे निवेदन है कि सभी किसानों के सभी प्रकार के कर्ज माफ किए जाएं।
- बिजली संशोधन विधेयक, 2022 को वापस लिया जाए। केंद्र सरकार ने 9 दिसंबर 2021 को संयुक्त किसान मोर्चा को लिखे पत्र में यह लिखित आश्वासन दिया था कि, "मोर्चा से चर्चा होने के बाद ही बिल संसद में पेश किया जाएगा।" इसके बावजूद, केंद्र सरकार ने बिना कोई विमर्श के यह विधेयक संसद में पेश किया।
- (अ) लखीमपुर खीरी जिला के तिकोनिया में चार किसानों और एक पत्रकार की हत्या के मुख्य साजिशकर्ता केन्द्रीय गृह राज्यमंत्री अजय मिश्र टेनी को मंत्रिमंडल से बर्खास्त किया जाए और गिरफ्तार करके जेल भेजा जाए।
- (ब) लखीमपुर खीरी हत्याकांड में जो निर्दोष किसान जेल में कैद हैं, उनको तुरन्त रिहा किया जाए और उनके ऊपर दर्ज फर्जी मामले तुरन्त वापस लिए जाएं। शहीद किसान परिवारों एवं घायल किसानों को मुआवजा देने का सरकार अपना वादा पूरा करे।
- सूखा, बाढ़, अतिवृष्टि, फसल संबंधी बीमारी, आदि तमाम कारणों से होने वाले नुकसान की पूर्ति के लिए सरकार सभी फसलों के लिए व्यापक एवं प्रभावी फसल बीमा लागू करे।
- सभी मध्यम, छोटे और सीमांत किसानों और कृषि श्रमिकों को ₹ 5000 प्रति माह की किसान पेंशन की योजना लागू की जाए।
- किसान आन्दोलन के दौरान भाजपा शासित प्रदेशों व अन्य राज्यों में किसानों के ऊपर जो फर्जी मुकदमे लादे गए हैं, उन्हें तुरंत वापस लिया जाए।
- किसान आंदोलन के दौरान शहीद हुए सभी किसानों के परिवारों को मुआवजे का भुगतान और उनके पुनर्वास की व्यवस्था की जाए, और शहीद किसानों के लिए सिंघु मोर्चा पर स्मारक बनाने के लिए भूमि का आवंटन किया जाए।

इस ज्ञापन के जरिए देश का अन्नदाता सरकार तक अपना गुस्सा प्रेषित करना चाहता है। हम आपसे अनुरोध करते हैं कि आप केंद्र सरकार को उसके लिखित वायदों की याद दिलाएं और देश के किसानों के संपूर्ण कर्ज मुक्ति, किसान बीमा, और किसान पेंशन की मांगों को जल्द से जल्द पूरा करवाएं। हम आपके माध्यम से केंद्र सरकार से अनुरोध करते हैं कि वह किसानों के धैर्य की परीक्षा लेना बंद करे। यदि सरकार अपने वायदे और किसानों के प्रति जिम्मेदारी से मुकरना जारी रखती है, तो किसानों के पास आंदोलन को और तेज करने के सिवाय दूसरा कोई रास्ता नहीं बचेगा।

छत्तीसगढ़

बस्तर के आदिवासी ग्रामों से फासिस्ट संघ परिवार द्वारा 66 आदिवासी ईसाइयों को प्रताड़ित कर गांव से भगाए जाने एवम दमन और गांव ,जंगल,जमीन बचाने गुहार लगा रहे आदिवासियों के ऊपर जानलेवा हमला पर छत्तीसगढ़ के राज्यपाल को फासीवाद विरोधी जन संघर्ष मोर्चा का ज्ञापन

ग्राम मुंगवाल, थाना बयानार, जिला कोंडागांव, छत्तीसगढ़ आदिवासी गाँव मुंगवाल छत्तीसगढ़ राज्य में जिला मुख्यालय कोंडागाँव से लगभग *45* किलोमीटर दूर एक ग्राम पंचायत है। गुंगवाल गाँव में *13* आदिवासी ईसाई परिवार और आश्रित गाँव गदनार में लगभग *40* आदिवासी ईसाई परिवार निवासरत हैं। कुछ हफ्ते पहले गांव गुंगवाल के स्थानीय आदिवासी लोगों ने स्थानीय पास्टर रागूराम सलाम को रास्ते में रोक लिया और उन्हें स्थानीय चर्च में सेवा के लिए नहीं आने की चेतावनी दी, अन्यथा उन्हें मार दिया जाएगा। गांव के आदिवासी ईसाई विश्वासी बिना पास्टर के प्रार्थना भवन में प्रार्थना करने लगे। तब ग्रामीणों ने उन्हें धमकी दी कि वे न तो प्रार्थना भवन में और न ही गाँव के किसी भी घर में प्रार्थना करें। *4* दिसंबर *2022* रविवार को सुबह *9* बजे गांव की बैठक बुलाई गई। आदिवासी ईसाई प्रार्थना भवन में प्रार्थना कर रहे थे, जब उन्हें स्थानीय आदिवासियों ने बैठक में भाग लेने के लिए बुलाया। लगभग *150* से *200* की संख्या में गाँव के लोगों ने ग्राम प्रधान *(*सरपंच*)* के नेतृत्व में आदिवासी ईसाइयों पर यीशु मसीह को अस्वीकार करने और पहले के आदिवासी विश्वास में लौटने का दबाव डाला। आदिवासी ईसाई असहमत थे और उनसे कहा कि वे कभी भी यीशु मसीह का अनुयायी होना नहीं छोड़ेंगे वे कभी भी यीशु से प्रार्थना करना बंद नहीं करेंगे, साथ ही वे अपने पैतृक गांव को भी नहीं छोड़ेंगे। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि किसी भी धर्म या आस्था का परिचालन करना उनका संवैधानिक अधिकार है। आदिवासी ईसाइयों की बात सुनकर ग्रामीणों ने झूठा आरोप लगाया कि ईसाइयों ने अपने सभी आदिवासी संस्कृति, परंपराओं व रीति - रिवाजों को छोड़ दिया है। इसलिए वे अब अपनी जाति, धर्म और गांव का हिस्सा नहीं हैं। उन्होंने गांव के निवासी होने का अधिकार खो दिया है। ग्रामीणों ने आदिवासी ईसाईयों को आदेश दिया कि वे अपना सारा सामान छोड़कर गाँव से बाहर चले जाएँ। संध्या लगभग छह बजे ग्रामीणों ने आदिवासी ईसाइयों को बलपूर्वक गांव की सीमा से बाहर लगभग *5-6* किलोमीटर की दूरी तक धकेल दिया। वे बहुत ही अपमानजनक भाषा का प्रयोग करते हुए आदिवासी ईसाइयों के विरुद्ध चिल्ला रहे थे। आदिवासी ईसाइयों को अपने साथ कुछ भी ले जाने नहीं दिया गया। बच्चों, महिलाओं और बुजुर्गों सहित *13* आदिवासी ईसाई परिवारों के *66* सदस्यों को खाली हाथ खदेड़ दिया गया। पीड़ितों के इस समूह में से *10* साल की उम्र के *10* बच्चे हैं। ग्रामीणों ने आदिवासी ईसाइयों को धमकी दी कि अगर वे ईसाई धर्म का खंडन किए बिना गांव लोटेंगे तो वे उन्हें मार देंगे और उनके शवों को घनघोर जंगल में फेंक देंगे। ग्रामीणों ने आदिवासी ईसाइयों से कहा, "गाँव हमारा है और गाँव में शासन हमारा है। हमें संविधान, अदालत या पुलिस की परवाह नहीं है। सर्वोच्च न्यायालय हमारे आदेश के अनुसार फैसला करेगा। हम किसी भी आदेश का पालन नहीं करेंगे। गाँव से बाहर निकल जाओ और कभी लौटकर मत आना। पुलिस हमारा कुछ नहीं करेगी।" आदिवासी ईसाइयों ने स्थानीय पुलिस को फोन किया, घटना के बारे में बताया और फोन पर मदद मांगी ।

पुलिस ने गांव जाने के बजाय ईसाइयों को बचानार थाने बुलाया, जो गांव से 2 किमी दूर है। आदिवासी ईसाई थाने जाने का साहस नहीं कर पाये क्योंकि ग्रामीण उन्हें थाने जाने से रोकने के लिए खड़े थे। भयभीत आदिवासी ईसाई गाँव बुखल की ओर चल पड़े। रात करीब 9 बजे वे वहां पहुंचे और आम के पेड़ के नीचे रात बिताई। अगली सुबह वे कोडागांव नगर, जिला मुख्यालय की ओर चले गए और अपने रिश्तेदारों के पास कोंडागांव और आसपास के गांवों में शरण मांगी। आदिवासी ईसाई बहुत ही गंभीर स्थिति में है, जहां रहने के लिए कोई जगह नहीं है, खाने के लिए भोजन नहीं है और पहनने के लिए कपड़े भी नहीं हैं। बस्तर संभाग के अलग - अलग स्थानों पर आदिवासी ईसाई विश्वासियों और पास्टरों के साथ हिंसा, प्रताड़ना और सामाजिक बहिष्कार की इसी तरह की कई गंभीर घटनाएं हो चुकी हैं। लेकिन प्रभावितों की संख्या के लिहाज से यह सबसे बड़ी घटना है। ये लोग कोंडागांव के कलेक्ट्रेट में जाकर शासन प्रशासन से अपनी सुरक्षा की मांग किया है। पुलिस और प्रशासन को बार - बार शिकायत करने के बावजूद, आदिवासी ईसाइयों के लिए कोई राहत नहीं है, इस घटना के पीछे कुछ साम्प्रदायिक फासीवादी ताकते है, जिन्हें पुलिस संरक्षण दे रही है, जिसके चलते ये घटनाए बार बार घट रही है। तत्काल इन असामाजिक तत्वों को गिरफ्तार किया जाय ताकि गांवो में सामाजिक सद्भाव बना रहे।

वही सुकमा जिले के बुर्जी, कुदेड़ में धरना दे रहे आदिवासियों के ऊपर बर्बर हमला किया गया जिसमे महिलाओं को भी बेदम पिटाई किया गया है 15 दिसंबर और 20 दिसंबर को यह घटना किया गया पुसनार,बेचापाल बेचाघाट जैसे कई गावों में इस तरह भयानक घटना फोर्स द्वारा किया गया। हम राज्यपाल महोदया से अनुरोध करते है कि इस मामले पर हस्तक्षेप करते हुए आवश्यक कार्यवाही कर पीड़ित आदिवासी ईसाईयों परिवारों को न्याय दिलाने का कष्ट करेंगे।

छत्तीसगढ़ जन संघर्ष मोर्चा, संयोजक मंडल सदस्य
वी एन प्रसाद राव, अब्दुल अजीम, सौरा यादव, कलादास डहरिया, प्रज्ञा बौद्ध

झारखण्ड

15 नवंबर 2022 को शहीद नीलांबर पीतांबर समारोह समिति की टीम नीलांबर पीतांबर पुर पहुंचकर उनकी समाधि स्थल का शिलान्यास किया गया।

शहीद नीलांबर पीतांबर के परपोता देव नारायण सिंह के हाथों से शिलान्यास किया गया

14 नवम्बर को शहीद नीलांबर पीतांबर के पैतृक गांव चेमो सनेया से शुरू कर उनके शहादत स्थल नीलांबर पीतांबर तक दो दिवसीय यात्रा निकाली गई। रास्ते में शहीद बिरसा मुंडा की जयंती को डाल्टनगंज रामकंडा, डाल्टनगंज में मनाया गया और केंद्र सरकार के कैबिनेट द्वारा प्रस्तावित वन संरक्षण संशोधन अधिनियम की प्रतियों को जलाते हुए, कंपनी राज के खिलाफ पुरजोर प्रतिरोध दर्ज कराया गया। नीलांबर पीतांबर, बिरसा मुंडा के देश में कंपनी राज नही चलेगा।

नीलांबर पीतांबर पूर *(*लेसलीगंज*)* पहुंच कर शहीदों के परपोते देवनारायण सिंह द्वारा समाधि निर्माण का शिलान्यास किया गया। जिसके बाद गांधी चौक पर नुक्कड़ सभा हुआ। सभा में वक्ताओं ने कहा कि सरकारें हमारे शहीदों की शहादत को धूमिल करते हुए उनकी लड़ाइयों को खत्म कर देना चाहती है। इसके विरुद्ध में नीलांबर पीतांबर शहादत समारोह समिति के साथी शहीदों के गौरवपूर्ण इतिहास को स्थापित करने के साथ उनके संघर्षों को लड़ाइयों को मंजिल तक पहुंचाने के लिए संकल्पित हैं। आज नीलांबर पीतांबर पुर में समाधि स्थल निर्माण शिलान्यास के साथ पूरे पलामू प्रमंडल में जल जंगल जमीन के सवाल पर गांव गांव यात्रा होगा और *28* मार्च *2023* को नीलांबर पीतांबर के शहादत दिवस के अवसर पर नीलांबर पीतांबरपूर *(*लेसलीगंज*)* में विशाल जनसभा होगा।

सभा की अध्यक्षता भाकपा माले नेता कमेश सिंह चेरो ने किया। सभा में मुख्य रूप से जन संग्राम मोर्चा के केंद्रीय अध्यक्ष युगल पाल, जिला अध्यक्ष बृजनंदन सिंह, केंद्रीय सचिव राजेंद्र जी, अशोक पाल, मूलनिवासी संघ के विनय पाल, शहादत समारोह समिति संयोजक एवं हुल क्रांति दल के नेता चंद्रधन महतो, ओबीसी एससी एसटी और माइनोरिटी मंच के रवि पाल, भाकपा माले रेड स्टार के प्रदेश सचिव वशिष्ठ तिवारी, जन क्रांति मंच के केंद्रीय अध्यक्ष शत्रुधन शत्रू, निर्मला जी, भाकपा माले के नेता शिवनाथ महतो, मीना जी, आइसा के प्रमंडलीय प्रभारी रंजीत सिंह चेरो और आर वाई ए के प्रदेश सचिव अविनाश रंजन के साथ सैकड़ों लोग शामिल थे।

छत्तीसगढ़

एक शाम शहीदों के नाम - नफरत और नहीं" दुर्ग, छत्तीसगढ़ में संगोष्ठी/कन्वेंशन संपन्न

संघी मनुवादी फासिस्ट ताकतों के खिलाफ संघर्षशील मोर्चा बनाना वक्त की पुकार

गत 12 दिसंबर को."एक शाम शहीदों के नाम, नफ़रत और नहीं" पर केंद्रित संगोष्ठी/ कन्वेंशन का आयोजन दुर्ग में, राज्य के जनवादी, संघर्षशील संगठनों और बुद्धिजीवियों के संयुक्त आयोजन में रखा गया था। कार्यक्रम की अध्यक्षता छत्तीसगढ़ मुक्ति मोर्चा के अध्यक्ष साथी जनक लाल ठाकुर ने की। क्रांतिकारी सांस्कृतिक मंच(कसम) के महासचिव साथी तुहिन ने आधार वक्तव्य दिया। कार्यक्रम का संचालन जनवादी आंदोलन से जुड़े और अल्पसंख्यकों के अधिकार के लिए संघर्षरत साथी प्रसाद राव ने किया।संगोष्ठी को संबोधित करने वालों में साथीगण- लखन सुबोध (अध्यक्ष, गुरु घासीदास सेवादार संघ), सौरा (राज्य सचिव, भाकपा(माले) रेड स्टार, अजय टी जी (राज्य कार्यकारिणी सदस्य, पीयूसीएल), तेजराम विद्रोही (अखिल भारतीय सचिव, AIKKS), राजकुमार गुप्ता (अध्यक्ष,स्वाभिमान मंच), पास्टर चोवाराम साहू, प्रज्ञा बौद्ध, सविता बौद्ध, विनोद सोनी(जिला सचिव,भाकपा), विजेंद्र तिवारी (राज्य सचिव, भाकपा (माले) लिबरेशन), एडवोकेट शाहिद कुरैशी(बहुजन, अल्पसंख्यक मोर्चा), वजी अहमद(इस्लामिक स्कॉलर), मजदूर नेता सुरेंद्र मोहंती, एडवोकेट हरप्रीत सिंह, रजत सिंह भारतीय, शाकिर अली और कलादास (छत्तीसगढ़ मुक्ति मोर्चा, मजदूर कार्यकर्ता समिति) शामिल थे। कलादास और तुहिन ने जन गीत प्रस्तुत किया। सभा ने सर्वसम्मति से राज्य में आरएसएस नव फासीवाद और उसके वैचारिक आधार मनुवादी हिंदुत्व के खिलाफ राजनैतिक सांस्कृतिक अभियान छेड़ने के लिए तमाम लड़ाकू संगठनों का एक संघर्षशील मोर्चा निर्माण करने का प्रस्ताव पारित किया गया।

तुहिन ने कहा कि हम सभी जानते हैं कि जब से केंद्र में मनुवादी फ़ासिस्ट भाजपा सरकार सत्ता में आयी है, तब से ही देश की संस्कृति,इतिहास और संविधान को बदलने का कुत्सित प्रयास किया जा रहा है।भारतीय जनता के दुश्मन और कॉरपोरेट घरानों के दलाल राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ (आरएसएस) और उसके अनुसांगिक संगठन भाजपा, विश्व हिन्दू परिषद, बजरंग दल जैसे विभिन्न संगठनों की सोच शुरू से ही बाबा साहब अंबेडकर द्वारा लिखे संविधान के खिलाफ रही है।

संघ और उससे जुड़े संगठनों के विचारकों का मानना है कि भारत का संविधान पश्चिमी देशों के संविधानों की नक़ल है अथवा यह विदेशों से आयातित है। इसमें भारत का अपना कुछ भी नहीं है। इसलिए वर्तमान में लागू संविधान को बदल दिया जाना चाहिए। भारतीय संस्कृति और मूल्यों की आड़ में संघ और भाजपा मिलकर उसी ब्रम्हाणवादी मनुस्मृति का राज कायम करना चाहते है जहाँ शूद्रों गरीबों और महिलाओंको इंसान होने का दर्जा तक हासिल नहीं था। चूंकि संविधान देश के आदिवासियों, दलितों, अन्य वंचित पिछड़ी जातियों, अल्पसंख्यकों और महिलाओं के पक्ष में खड़ा है, इसलिए भी संघ इसे बदलना चाहता है।उन्होंने कहा कि कसम और जाति उन्मूलन आंदोलन,समान विचार वाले संगठनों से मिलकर 6दिसंबर को बाबरी मस्जिद विध्वंस और बाबा साहेब डॉक्टर आंबेडकर के महापरिनिर्वाण दिवस से 25 दिसंबर को मनुस्मृति दहन दिवस तक आरएसएस के वैचारिक आधार मनुवादी हिंदुत्व के खिलाफ सांस्कृतिक अभियान देश भर में चला रहे हैं।

लखन सुबोध ने कहा कि मोदी सरकार के पहले जब अटल बिहारी वाजपेयी के नेतृत्व में भाजपा सरकार आयी थी तब उन्होने संविधान की समीक्षा करने की शुरुआत की थी इसके लिए एक आयोग का गठन किया था। व्यापक विरोध के बाद वाजपेयी सरकार को पीछे हटना पड़ा था। वर्ष 2017 में हैदराबाद में आयोजित एक सभा में संघ प्रमुख मोहन भागवत ने कहा कि, "भारतीय संविधान में बदलाव कर उसे भारतीय समाज के नैतिक मूल्यों के अनुरूप बनाया जाना चाहिए। संविधान के बहुत सारे हिस्से विदेशी सोच पर आधारित है, आज जरुरत है कि आज़ादी के 70 साल के बाद इस पर गौर किया जाय।" इस बयान से साफ है संघ प्रमुख जिन नैतिक मूल्यों के आधार पर संविधान में परिवर्तन चाहते है वे मनुस्मृति पर आधारित है।उन्होंने गुरुद्वारा प्रबंधन कानून की तर्ज पर सतनाम धर्मस्थल कानून बनाने की मांग रखी।सौरा ने कहा कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ (आरएसएस) के प्रमुख मोहन भागवत ने संघ के मुखपत्र 'पांचजन्य' और 'आर्गेनाइज़र' को दिए इंटरव्यू में कहा है कि "आरक्षण पर फिर से विचार करने का समय आ गया है। आरक्षण की ज़रूरत और उसकी समय सीमा पर एक समिति बनाई जानी चाहिए।" बाबा साहब के दिये आरक्षण के अधिकार को भी संघ और भाजपा खत्म करने पर आमादा है। हिंदू राष्ट्र के नाम पर इस देश के दलितों, आदिवासियों, पिछड़ों को बरगलाकर मुसलमानों और अन्य अल्पसंख्यकों के खिलाफ खड़ा किया जा रहा है। मुस्लिमों के खिलाफ़ नफ़रत का माहौल तैयार कर मनुस्मृति आधारित हिंदू राष्ट्र बनाने की साज़िश रची जा रही है। उन्होंने छत्तीसगढ़ में संघी मनुवादी फासिस्ट ताकतों के खिलाफ एक संघर्षशील मोर्चा निर्माण के लिए एक कार्ययोजना पेश की जिसे सभा ने स्वीकार किया।

राजकुमार गुप्ता ने कहा कि हमारे छत्तीसगढ़ में भी सांप्रदायिक हिंसा के मामले बढ़ रहे है। कारण है,देश में आरएसएस के नेतृत्व वाले सांप्रदायिक हिंदुत्ववादी बहुसंख्यकवादी आक्रमण से प्रतिस्पर्धा करते हुए छत्तीसगढ़ में शासकों द्वारा नर्म हिंदुत्व की बयार बहाई जा रही है। देश में हर रोज अखबारों व न्यूज़ चैनलों में दलितों, आदिवासियों, पिछड़ों और अल्पसंख्यकों के खिलाफ हो रही सामूहिक हिंसा और दुर्व्यवहार के मामले प्रकाशित हो रहे हैं। इसी प्रकार महिलाओं के खिलाफ हिंसा के कई मामले आये हैं। ऐसा प्रतीत हो रहा है जैसे देश में संविधान और कानून का राज खत्म हो चुका है। तेजराम विद्रोही ने कहा कि आरएसएस – भाजपा की सरकार ने तमाम ब्रम्हाणवादी – मनुवादी सांप्रदायिक ताकतों को हिंसा और अत्याचार करने की खुली छूट दे दी है। कॉरपोरेट घरानों की दलाल मोदी सरकार के इशारों पर पुलिस - प्रशासन इन प्रतिक्रियावादी ताकतों का साथ दे रहा है। एक तरफ शोषित-वंचित समाज के खिलाफ हिंसा और अत्याचार के मामले बढ़ रहे है वहीं इसका प्रतिरोध करने वाली ताकतों के खिलाफ़ राजकीय दमन का सहारा लिया जा रहा है।उन्होंने छत्तीसगढ़ किसान मजदूर महासंघ जो की SKM से जुड़ा है की ओर से संघी फासीवाद विरोधी मोर्चा निर्माण में पूर्ण सहयोग करने की बात कही।

अजय टी जी ने कहा की धर्म के आधार पर नफ़रत की राजनीति को हवा दी जा रही है ताकि आम मेहनतकश जनता का ध्यान मूल मुद्दों से हटाया जा सके। जनता को हिन्दू राष्ट्र का नशा पिलाकर जनता के गाढ़ी कमायी से खड़े किए गए तमाम सरकारी उद्योग-धंधों और प्रतिष्ठानों को औने पौने दाम पर अडानी-अंबानी जैसे कार्पोरेट घरानों को बेचा जा रहा है। चोआ राम साहू ने कहा कि निजीकरण और ठेका प्रथा ने मजदूरों का शोषण बढ़ा दिया है। संख्यानुपात के आधार पर आरक्षण देने के बजाय निजीकरण से लगभग आरक्षण की व्यवस्था को ही समाप्त कर दिया गया है।छत्तीसगढ़ में ईसाइयों पर होने वाले हमले बढ़ रहे हैं। प्रज्ञा बौद्ध ने कहा कि भ्रष्टाचार खत्म करने व काला धन वापसी के नाम पर की गई नोटबंदी और जीएसटी ने सिर्फ़ कार्पोरेट घरानों को ही लाभ पहुंचाया है, बल्कि इससे जनता पर मंहगाई और बेरोज़गारी की भीषण मार पड़ी है। मंहगाई ने जनता का जीना दूभर कर दिया है। शिक्षा और स्वास्थ्य आम जनता की पहुँच से कोसों दूर चला गया है।सविता बौद्ध ने कहा कि नई शिक्षा नीति (NEP) के चलते देशभर में लाखों सरकारी स्कूल बंद हो रहे है। इन तमाम कठिनाईयों से त्रस्त आकार यदि जनता सरकार बदलना भी चाहे तो भाजपा धन –बल और ईवीएम के सहारे सत्ता पर काबिज हो जाती है। ईवीएम के दुरुपयोग से एक व्यक्ति एक वोट का अधिकार ही छीन लिया गया है। लोकतन्त्र के स्थान पर तानाशाही और संविधान के स्थान पर मनुस्मृति को लागू किया जा रहा है ।मनुस्मृति के आधार पर संघ परिवार,हिंदुराष्ट्र बनाने पर आमादा है जहां महिलाओं को मानव का दर्जा नहीं दिया जाता। आरएसएस/भाजपा घोर महिला विरोधी है।

विजेंद्र तिवारी ने कहा कि आज संविधान और लोकतन्त्र की हत्या के लिए तमाम मनुवादी/ ब्रम्हाणवादी फ़ासिस्ट ताक़तें एकजुट है, उनका कार्पोरेट पूंजी के साथ गठजोड़ है। वाजी अहमद ने कहा कि कार्पोरेट मनुवादी ताकतों की नापाक साज़िशों को नाकाम करने और संविधान की रक्षा के लिए हम सभी शोषित- वंचित समाजों और अल्पसंख्यक वर्गों के लोगों को एकताबद्ध होना समय की मांग है।सभा की शुरुआत में साथी प्रसाद राव द्वारा, देश के और छत्तीसगढ़ के साम्राज्यवाद,सामंतवाद और पूंजीवाद के खिलाफ लड़ाई के अमर शहीद भगत सिंह, अशफाकुल्ला खान,राम प्रसाद बिस्मिल, प्रिटिलता वड्डेदार,रोहित वेमुला,स्टेन स्वामी,वीर नारायण सिंह,जरहू गोंड,रामाधीन गोंड, शंकर गुहा नियोगी,अनुसुइया बाई ,बाबा बालकदास,सुखराम नागे,रमेश परिडा और गुण्डाधुर को याद करने के आहवान पर सभी ने इन शहीदों का स्मरण किया। अंत में अध्यक्षीय वक्तव्य देते हुए जनक लाल ठाकुर ने कहा कि शहीदों के सपनों का भारत बनाने के लिए हमें अपने संविधान के समावेशी मूल्यों की रक्षा करते हुये एक सच्चे लोकतान्त्रिक समाज की ओर आगे बढ़ना होगा। इसी उद्देश्य से हम ,समता, समानता, बंधुत्व ,अभिव्यक्ति की आजादी और संविधान पर यकीन रखने वाले संगठनों और व्यक्तियों से राज्य में इस संघी फासीवाद विरोधी मोर्चा में शामिल होने की अपील करते है। इस सभा/कन्वेंशन में प्रदेश के जनवादी संगठनों के प्रतिनिधि और प्रगतिशील बुद्धिजीवी बड़ी संख्या में उपस्थित थे।

उड़ीसा

आवास, आजीविका, शिक्षा, स्वास्थ्य, स्वच्छता के अधिकार एवम बलपूर्वक झुग्गी बस्तियों को पुलिस/बुलडोजर द्वारा उजाड़ने के खिलाफ, बस्ती सुरक्षा मंच, भुवनेश्वर द्वारा *16* दिसंबर को विधानसभा के समक्ष जंगी रैली व प्रदर्शन का आयोजन किया गया।प्रदर्शन का नेतृत्व बस्ती सुरक्षा मंच की सलाहकार कॉमरेड प्रमिला, हिना बारीक,राधारानी, मिनती भोई, ने किया।क्रांतिकारी सांस्कृतिक मंच *(RCF)* की ओर से तुहिन, असीम गिरी, विचित्र पात्र, शोभा, विजय बारीक, पूर्णिमा, आशामणि, हरपाल कौर और रजल कुमारी ने क्रांतिकारी जन गीत प्रस्तुत किया।

मध्य प्रदेश

26 नवम्बर, संविधान दिवस के अवसर पर भोपाल में मनाया गया संविधान सुरक्षा संकल्प दिवस!

आयोजित महासभा में शामिल होकर सैकड़ों लोगों ने लिया संविधान की रक्षा का संकल्प!

26 नवंबर को देशभर में संविधान दिवस के अवसर पर विभिन्न कार्यक्रमों का आयोजन हुआ। इसी क्रम में भोपाल के विभिन्न संगठनों द्वारा ओबीसी, एसटी, एससी, अल्पसंख्यक संयुक्त मंच के नेतृत्व में 26 नवम्बर को "संविधान सुरक्षा संकल्प दिवस" एवं महासभा का आयोजन अम्बेडकर जयंती मैदान, सेकंड स्टॉप में 12 बज़े से किया गया। महासभा में हजारों लोगों ने संविधान की रक्षा करने का संकल्प लिया तथा संपूर्ण मध्यप्रदेश में संविधान जागरूकता अभियान चलाने का निर्णय लिया। भोपाल की विभिन्न बस्तियों और क्षेत्रों से संविधान की प्रतिकात्मक तस्वीर के साथ जुलूस बनाकर लोग कार्यक्रम स्थल तक पहुंचे। कार्यक्रम की शुरुआत में अ.भा. ओबीसी महासभा के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष और कार्यक्रम के संयोजक ओबीसी एडवोकेट तुलसीराम पटेल ने अतिथियों और श्रोताओं का स्वागत किया।

संविधान सुरक्षा संकल्प महासभा को दिल्ली से आए मुख्य अतिथि भानुप्रताप सिंह अधिवक्ता सुप्रीम कोर्ट, विशिष्ट अतिथि महमूद प्राचा सीनियर अधिवक्ता सुप्रीम कोर्ट और दिल्ली विश्वविद्यालय की प्रोफेसर डॉ. रितु जी ने संबोधित किया। अन्य विशिष्ट वक्ताओं में पिछड़ा वर्ग नेता प्रीतम लोधी, अ.भा. ओबीसी महासभा के राष्ट्रीय अध्यक्ष ओबीसी ललित कुमार, राष्ट्रीय क्रांति मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष देवरावेन भलावी, संविधान बचाओ मंच के मध्यप्रदेश अध्यक्ष सुनील बोरसे एवं बौद्ध समाज के वरिष्ठ नेता कैलाश वल्ले ने भी महासभा को संबोधित किया। कार्यक्रम की अध्यक्षता वरिष्ठ समाजिक कार्यकर्ता एच. एन. गोलाईत और संचालन विजय कुमार, संयोजक लोकतान्त्रिक अधिकार मंच मध्यप्रदेश ने किया।

महासभा को संबोधित करते हुए मुख्य अतिथि भानुप्रताप सिंह अधिवक्ता सुप्रीम कोर्ट, ने कहा की कहा कि केंद्र में मनुवादी फ़ासिस्ट भाजपा सरकार सत्ता में आयी है, तब से ही संविधान को बदलने का कुत्सित प्रयास किया जा रहा है। राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ (आरएसएस) और उसके अनुषांगिक संगठन भाजपा, विश्व हिन्दू परिषद, बजरंग दल जैसे विभिन्न संगठनों की सोच शुरू से ही बाबा साहब अंबेडकर द्वारा लिखे संविधान के खिलाफ रही है।

संघ और उससे जुड़े संगठनों के विचारकों का मानना है कि भारत का संविधान पश्चिमी देशों के संविधानों की नक़ल है अथवा यह विदेशों से आयातित है। इसमें भारत का अपना कुछ भी नहीं है। इसलिए वर्तमान में लागू संविधान को बदल दिया जाना चाहिए। असल में भारतीय संस्कृति और मूल्यों की आड़ में संघ और भाजपा मिलकर उसी ब्रम्हाणवादी, मनुस्मृति का राज कायम करना चाहते है जहाँ शूद्रों को इंसान होने का दर्जा तक हासिल नहीं था।

छत्तीसगढ़

आदिवासी भारत महासभा ने मैनपुर क्षेत्र केआदिवासियों की समस्याओं को लेकर धरना प्रदर्शन कर मुख्यमंत्री के नाम अनुविभागीय अधिकारी को ज्ञापन दिया

5 जनवरी को मैनपुर ,जिला गरियाबंद में आदिवासी भारत महासभा एवं मजदूर किसान एकता संघटन के नेतृत्व में मैनपुर क्षेत्र की समस्याओं एवं प्रदेश में आदिवासियों के ऊपर बढ़ते दमन के खिलाफ एक दिवसीय धरना,प्रदर्शन एवम रैली कर खण्ड शिक्षा अधिकारी,वन विभाग के एस डी ओ एवं अनुविभागीय अधिकारी को मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन दिया गया।

सभा की अध्यक्षता कॉमरेड भोजलाल नेताम ने किया, संचालन प्रताप मरकाम और आभार युवराज नेताम ने किया।

कॉमरेड भोजलाल नेताम ने कहा कि बस्तर संभाग के बीजापुर,सुकमा जिला में पुलिसिया आतंक एवं सी आर पी एफ कैम्प के खिलाफ विगत तीन सालो से सेलेगर सहित कई इलाकों में आदिवासियों का आंदोलन जारी है।सेलेगर में आज से दो साल पूर्व सी आर पी एफ एवं पुलिस फायरिंग में चार लोग मारे गए थे, ताड़मेटला ,सरकेगुडा सहित दर्जनों फर्जी मुठभेड़ हुई है, जिसका खुलासा अग्रवाल कमीटी ने उजागर कर दिया है।अभी हाल में सुकमा जिले के बुर्जी औऱ कुन्देड़ में पुलिस कैम्प के खिलाफ शान्ति पूर्वक धरना दे रहे थे, विगत 15दिसम्बर को 20 दिसम्बर को पुलिस ने आंदोलनकरियो पर निर्मम तरीके से हमला किया जिसमे 13लोग बुरी तरह जख्मी हो गए। जिसमे महिलाओं को भी नही बक्शा गया।बुर्जी और कुन्देड़ के अलावा पुसानार, बेचापाल,बेचाघाट ,नम्बीधारा ,गोमपाड,सिंगराम,गोड़ेरास,सेलेगर सहित कई जगहों पर पुलिस/सी आर पी एफ कैम्प का विरोध किया जा रहा है, लेकिन सरकार तमाश देख रही है, पेसा कानून,ग्राम सभा का भी पालन नहीं कर रही हैं।जो कि संविधान में प्राप्त अधिकारों का उलंघन है। नेताम ने पुलिसिया आतंक व दमन की घोर निंदा करते हुए आगे कहा कि निर्दोष आदिवासियों पर दमन करना बंद करे,इस घटना की न्यायिक जांच कर पीड़ित लोगों का डॉक्टरी इलाज कराई जाए,दोषी पुलिस अधिकारियों पर कड़ी कार्यवाही किया जाने की मांग किया गया।

कॉमरेड सौरा यादव ने कहा कि हाथी विचरण की समस्या एक बड़ी समस्या है,वन विभाग को इस समस्या को गंभीरता से लेना चाहिए।शिक्षा, स्वस्थ्य का मुद्दा मौलिक अधिकार है लेकिन इचरादी मे स्कूल नही है शिक्षक नही है, बच्चो के जिंदगी के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है। आज भी अपने वन अधिकारों से लाखों आदिवासी वंचित हैं, जो दावा जमा नहीं कर पाये हैं या फिर उनके दावों को बिना कोई पूर्व सूचना दिये निरस्त कर दिया गया है।आज भी लाखों आदिवासियों को उनके जमीन का मालिकाना हक तक नहीं मिल पाया है। लम्बे संघर्षों के बदौलत ग्राम सभा ,पेसा कानून ,पांचवी अनुसूची बनाया गया, लेकिन इच्छाशक्ति के अभाव के चलते इसे अब तक लागू नहीं किया गया। आज भी ब्रिटिश काल के 1927 के कानून में संशोधन करके केंद्र की फासिस्ट मोदी सरकार लागू करने की कोशिश कर रही है ।इस कानून के लागू होने से आदिवासियों की जिंदगी और भी ज्यादा जटिल और तकलीफदेह होने वाली है।आदिवासियो पर बढ़ते अन्याय एवं अत्याचार को दूर करने एवं वन क्षेत्रों में व्यापक भूमि सुधार लाने और लोकतांत्रिक शासन पद्धति लागू करने के उद्देश्य से अनुसूचित जनजाति व अन्य परंपरागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम 2006 बनाया गया। इसे प्रदेश में 2008 में लागू किया गया, इस कानून से सदियों से पीड़ित आदिवासियों को उम्मीद जागी थी लेकिन अब तक आदिवासियों को उनका अधिकार नहीं मिला है, उल्टे गैर कानूनी ढंग से इनके अधिकारों को छीना जा रहा है ।इसके साथ साथ पंचायतो के प्रावधान (अनुसूचित क्षेत्रों का विस्तार)अधिनियम 1996 पेसा कानून को इनकी भावना के अनुरूप क्रियान्वयन नहीं किया गया। आदिवासी क्षेत्रों में ग्राम सभाओं को अपने संसाधनों पर नियंत्रण एवं प्रबंधन का अधिकार आज तक प्राप्त नहीं हो पाया है। अब भी ग्राम सभा शासकीय प्रशासनिक तंत्र की गिरफ्त में है। समुदाय के तमाम प्रयासों संघर्षों के बावजूद भी ग्राम सभाओं को स्वशासन की इकाई नहीं बनाने दिया गया है।

महेंद्र नेताम ने कहा कि अभयारण्य के नाम पर वन विभाग पूरा अधिकार अपने हाथों में ले लेगा फॉरेस्ट विभाग को और ज्यादा ताकतवर बना देगा जंगलों में जेल बनाया जाएगा फॉरेस्ट के अधिकारियों को बंदूक देकर दमन करने का पूरा अधिकार सौंपा जा रहा है,जो आदिवासी विरोधी कृत्य है। आज की सभा को लोकेश्वरी नेताम ,खोलूराम कोमर्रा,लाल सिंह यादव,लोकेश्वर नागेश,बलिराम ठाकुर,सियाराम ठाकुर,मुकुंद कुंजाम,चैतन मरकाम ने भी अपना विचार रखे।सभा में भी कोनारी,जिडर,गिरोला, बुढार,मैनपुर कला,इचरादी, कोदोमाली,कुल्हाड़ी घाट,भटीगड़, गोबरा,राजपुर,जडापदार से सैकड़ों के तादाद में महिला ,बच्चे एवं पुरुषों ने भाग लिया।

संयुक्त किसान मोर्चा प्रेस नोट, करनाल;

संयुक्त किसान मोर्चा की एक बैठक 8 दिसंबर 2022 को हरियाणा में करनाल के गुरुद्वारा डेरा कार सेवा में संपन्न हुई। किसान नेता सत्यवान, किशोर धमाले, सुरेश कौथ ने संयुक्त रूप से इसकी अध्यक्षता की। बैठक में अधिकतम एकता और जोरदार संघर्ष के संकल्प के साथ संयुक्त किसान मोर्चा को सशक्त व व्यापक बनाने पर सभी ने बल दिया।

बैठक में देशभर से आये किसान नेताओं में हनान मौला, शंकर घोष, आशीष मित्तल, आर. वैंकेया, रूलदू सिंह मानसा, प्रेम सिंह गहलावत, बूटा सिंह बुर्जगिल, जोगिंदर सिंह, दर्शन पाल, आविक शाहा, सतनाम सिंह अजनाला, बलदेव सिंह निहालगढ़, रामिन्द्र सिंह पटियाला, किरणजीत सिंह सेखों, हरदेव सिंह संधू, गौरव टिकैत, हरजीत सिंह, रतनमान, विरेंद्र सिंह डागर, इंद्रजीत सिंह, हरजीत सिंह, जयकरण मांडोठी, जोगिंदर सिंह नैन, तेजराम विद्रोही, लक्खा सिंह, फूलचंद ढ़ेवा, युवराज गटकल तेजवीर सिंह पंजोखरा, गुरनाम सिंह भीखी आदि ने प्रमुखता से अपने विचार रखे।

कामरेड तेजराम, एस के एम के बैठक में अपनी बात रखते हुए

पिछले आन्दोलनों की समीक्षा में नेताओं ने बताया कि 26 नवंबर को संपन्न हुआ "राज निवास चलो" कार्यक्रम मोहाली, पंचकूला, लखनऊ, पटना, कोलकाता, भोपाल, जयपुर और देश की राजधानी दिल्ली समेत देशभर में सफल रहा। कुछ राज्य सरकारों द्वारा प्रदर्शनकारियों को गिरफ्तार करने की कड़ी निंदा की गई। सरकार के किसान विरोधी रवैए पर सभी नेताओं ने भारी रोष प्रकट किया। घर वापसी से पहले एमएसपी गारंटी कानून बनाने समेत किये गये वादे उसने नहीं निभाये।

उल्टे, बिजली क्षेत्र को प्राइवेट कम्पनियों के हाथों में सुपर्द करने के बुरे इरादे से उसने बिजली बिल 2022 को लोकसभा में पेश कर दिया है और किसानों पर तरह तरह के हमले किये जा रहे हैं। सभी नेताओं ने महसूस किया कि 26 जनवरी, 2021 को सरकार ने जिस तरह से किसान आंदोलन को बदनाम करने की साजिश रची थी और किसानों को जाति, धर्म, इलाका, भाषा के नाम पर बांटने की जो साजिश रची थी, वह अभी भी जारी है। संयुक्त किसान मोर्चा ने इसे हर कीमत पर विफल करने का संकल्प दोहराया। साथ ही, कहा कि आगामी 26 जनवरी को देश भर में बड़े स्तर पर जन-गण एकता कार्यक्रम लेने के अलावा आगामी बजट सत्र पर बकाया मांगों को संसद पर जोरदार ढंग से बुलंद किया जाएगा। व्यापक विचार विमर्श के माध्यम से इनकी घोषणा 24 दिसंबर को करनाल में पुन: होने जा रही अगली बैठक में की जाएगी। लखीमपुर खीरी में किसानों पर जुल्म ढ़हाने के दोषियों पर अदालत द्वारा आरोप तय किये जाने पर कहा कि इससे हत्यारों को दण्डित करने की आस बंधी है। साथ ही कहा कि झूठे केसों में फंसाए गये किसानों को तुरंत प्रभाव से मुक्त किया जाये। भूमि अधिग्रहण व अन्य मुद्दों पर देशभर में चल रहे किसान संघर्षों को समर्थन घोषित किया। गन्ना किसानों को लाभकारी दाम और बकाया रकम तुरंत प्रभाव से अदा करने की मांग की गई। किसानों की लड़ाई जारी रहेगी। 'लड़ेंगे - जीतेंगे' के संकल्प के साथ बैठक सम्पन्न हुई।

जारी कर्ता:

संयुक्त किसान मोर्चा

सितम्बर 2022, कोझिकोड, केरल में संपन्न हुई 12वीं पार्टी कांग्रेस

संयुक्त वक्तव्य

6 से 25 दिसंबर तक आरएसएस के वैचारिक आधार मनुवादी हिंदुत्व के खिलाफ अभियान को सफल बनाएं

2014 के मध्य में मोदी सरकार के सत्ता में आने के बाद से, दुनिया का सबसे पुराना और सबसे बड़ा फासीवादी संगठन आरएसएस , भारत को एक हिंदूराष्ट्र के रूप में बदलने की दिशा में सुनियोजित ताबड़तोड़ आक्रमण में लगा हुआ है। आरएसएस का वैचारिक आधार मनुस्मृति है जिसके अनुसार दलितों/उत्पीड़ितों और महिलाओं दोनों को इंसान नहीं समझा जाता।इसके अलावा इसके तथाकथित हिंदुराष्ट्र में आरएसएस, मुसलमानों को नागरिकता और मानवाधिकारों से वंचित करती है। विशेष रूप से, मोदी के दूसरे कार्यकाल के तहत 2019 के बाद से, भारत "मोदीनॉमिक्स" का एक क्रूर स्वरूप भी देख रहा है, जो आज क्रोनी कैपिटलिज्म का भारतीय संस्करण है और अखिल भारतीय स्तर पर पूर्ण रूप से कॉर्पोरेट-भगवा फासीवाद का बहु-आयामी संस्करण है।

आज भगवा नव-फासीवाद के तहत देश का समूचा सामाजिक ताना-बाना, अत्यधिक विभाजनकारी नीतियों और साम्प्रदायिक उकसावे के जरिए भयावह विघटन का सामना कर रहा है।

इस तथाकथित हिंदुराष्ट्र में लोगों के बीच आपसी द्वेष, नफरत और विभाजन पैदा किया जाता है जिससे दलितों और अल्पसंख्यकों में असुरक्षा की भावना पैदा हो। राज्य सत्ता के समर्थन से, आरएसएस ने भारत में सभी संवैधानिक और प्रशासनिक संस्थानों के भगवाकरण के अलावा सामाजिक जीवन के हर पहलू को अपने जाल में फंसाने में सफलता हासिल की है। 2019 के मध्य से, यानी मोदी के नेतृत्व में, हिंदुत्व आक्रमण को एक अतिरिक्त गति मिली। दूसरी बार सत्ता में आने के तीन महीने के भीतर, मोदी ने संविधान के अनुच्छेद 370 को निरस्त करने के साथ शुरू होने वाली फासीवादी चालों की एक श्रृंखला शुरू की, जिससे एक ओर कश्मीर के टुकड़े हो गए और दूसरी ओर इसे जबरन भारतीय संघ में एकीकृत कर दिया गया। संविधान को मानने की शपथ लेने के बावजूद धर्मनिरपेक्षता का उल्लंघन करते हुए, मोदी ने स्वयं बाबरी मस्जिद के स्थान पर राम मंदिर निर्माण की नींव रखी, जिसके बाद सीएए/एन आर सी के जरिए मुसलमानों के खिलाफ नागरिकता के अधिकार के मुद्दे पर भेदभाव करना और उन्हें दूसरे दर्जे का नागरिक बनाने की ओर अग्रसर है। अगला कदम NEP 2020 के माध्यम से शिक्षा का भगवाकरण और कॉरपोरेटीकरण राज्यों पर हिंदी और संस्कृत को थोपना और भारत के इतिहास व संस्कृति को साम्प्रदायिक तथा विकृत बनाना था। बेशक, उनका एजेंडा बहुराष्ट्रीय, बहुभाषी, बहुसांस्कृतिक, बहु-जातीय और बहु-धार्मिक भारत को कॉरपोरेट के प्रभुत्व वाले एक बहुसंख्यक हिंदुराष्ट्र में बदलना है।

मौजूदा स्थिति में, विधानसभा चुनावों में हिंदू वोट-बैंक को मजबूत करने और 2024 के आम चुनाव में भगवा स्वीप के लिए जमीन तैयार करने के लिए, आरएसएस और बीजेपी शासन द्वारा हिंदुत्व पर कोई रोक नहीं लगाकर उसे बेलगाम किया जा रहा है। उदाहरण के लिए, अक्टूबर के अंतिम सप्ताह के दौरान आयोजित राज्य के गृह मंत्रियों के तथाकथित चिंतन शिविर में, शाह और मोदी दोनों ने प्रावधानों का उल्लंघन करते हुए एक अखिल भारतीय पुलिसिंग को जबरदस्ती थोपने के लिए अपनी बयानबाजी के साथ बहुसंख्यकवादी एजेंडे को आगे बढ़ाने की पूरी कोशिश की। संविधान की सातवीं अनुसूची की राज्य सूची और 2024 तक प्रत्येक राज्य में एनआईए कार्यालय खोलने की योजना सहित कठोर एनआईए और यूएपीए को और मजबूत करने का कार्यक्रम बनाया है। आतंक से लड़ने के नाम पर, "एक डेटा, एक प्रविष्टि" जैसे कई विचार ", "इस्लामोफोबिया को व्यवस्थित रूप से फैलाने और मुसलमानों को दुश्मन के रूप में चित्रित करने के साथ-साथ एक राष्ट्र, एक पुलिस की वर्दी का एजेंडा भी आगे रखा गया है।

अब इस भगवा आक्रमण की श्रृंखला में नवीनतम चोट, समान नागरिक संहिता और आर्थिक आधार पर आरक्षण हैं। जाहिर है.....

डॉ. अम्बेडकर द्वारा प्रस्तुत किए गए संवैधानिक रूप से अनिवार्य जाति-आधारित आरक्षण का उद्देश्य सामाजिक जीवन के सार्वजनिक क्षेत्रों में उच्च जातियों के हमले से उत्पीड़ित जातियों की रक्षा करना था। हालांकि, आर्थिक आरक्षण को शामिल करके 103वां संवैधानिक संशोधन, जिसे सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में समर्थन दिया है, मोदी शासन ने जाति-आधारित आरक्षण को कमजोर कर दिया है, जिसका उद्देश्य ब्राह्मणवादी ऊंची जातियों द्वारा अछूत और उत्पीड़ित जातियों के खिलाफ किए गए ऐतिहासिक अन्याय को सुधारना था।

इसी संदर्भ में जाति उन्मूलन आंदोलन के साथ समान विचार वाले संगठनों ने 6 दिसंबर से 25 दिसंबर तक तीखे होते आरएसएस नवफासीवाद के खिलाफ देशव्यापी राजनीतिक अभियान शुरू करने का फैसला किया है। जाहिर है, दिसंबर 6, भगवा गुंडों द्वारा बाबरी मस्जिद के विध्वंस के साथ-साथ भारतीय संविधान के निर्माता अम्बेडकर की पुण्यतिथि का प्रतीक है, जबकि 25 दिसंबर वह दिन है जब अम्बेडकर ने आरएसएस फासीवाद के वैचारिक आधार मनुस्मृति को जलाया था। मुस्लिम-विरोधी, दलित-विरोधी,किसान,मजदूर,आम मेहनतकश जनता और पितृसत्तात्मक घोर महिला विरोधी संघी मनुवादी फासीवाद के खिलाफ हम मेहनतकश वर्ग, देशभक्त,जनवादी,धर्मनिरपेक्ष ,प्रगतिशील अवाम और तमाम उत्पीड़ितों से अपील करते हैं कि आरएसएस के वैचारिक आधार मनुवादी हिंदुत्व के खिलाफ इस महत्वपूर्ण राजनैतिक अभियान को एक बड़े पैमाने पर सफल बनाएं।

इंकलाब ज़िंदाबाद।
देश की साझी शहादत, साझी विरासत की परंपरा पर हमें गर्व है।
साझी शहादत साझी विरासत जिंदाबाद।
जनता के दुश्मन कॉरपोरेट घरानों के दलाल संघी मनुवादी फासिस्ट मुर्दाबाद।

- **जाति उन्मूलन आंदोलन,**
- **क्रांतिकारी सांस्कृतिक मंच,**
- **अखिल भारतीय क्रांतिकारी महिला संगठन,**
- **क्रांतिकारी नौजवान भारत सभा,**
- **अखिल भारतीय क्रांतिकारी विद्यार्थी संगठन,**
- **आदिवासी भारत महासभा**

संपर्क- बंडू मेश्राम (9890269435), तुहिन (9425560952), प्रमिला (9437206230), रितांश (8079032993), निरंजन (9207602584), भोजलाल नेताम (7987555189).

राज्यों की रिपोर्ट

राजस्थान

25 दिसम्बर को नौजवान भारत सभा (RYFI) ने राजस्थान के विभिन्न जन संगठनों और बुद्धिजीवियों के साथ मिलकर राजस्थान हाई कोर्ट में लगी मुनि मूर्ति के खिलाफ जयपुर के शहीद स्मारक पर विरोध प्रदर्शन किया। हमारे साथ AIDWA, AIKS, PUCL, डॉ अंबेडकर विचार मंच, डॉ अंबेडकर स्वाभिमान आर्मी, संविधानिक विचार मंच आदि कई संगठनों के लोग इसमें शामिल हुए। जयपुर के विभिन्न इलाकों से लोगों ने प्रदर्शन में भाग लिया। मनुस्मृति में महिलाओं और समाज के वंचित तबकों के बारे में क्या लिखा है ये बताया गया। साथ ही कैसे RSS/BJP आज हिन्दू राष्ट्र के नाम पर मनुस्मृति लागू करना चाहती है, ये समझाया गया। कैसे काँग्रेस, बीजेपी दोनों ही मनुवादी हैं ये भी बताया गया।

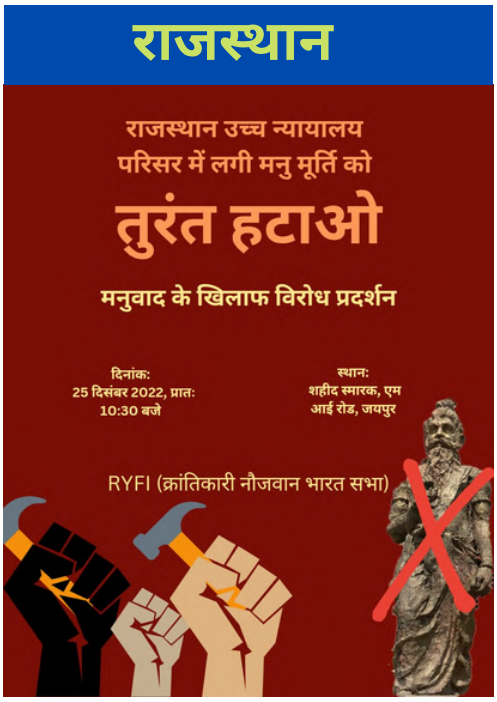

हम मिलकर मनुवाद/ब्राह्मणवाद, पुरुषप्रधानता और सांप्रदायिता के खिलाफ संघर्ष करेंगे, ये शपथ ली गई।

इसके बाद मनुस्मृति के एक प्रतीक का दहन भी किया गया। साथियों ने आज़ादी, मनुवाद, जातिवाद के खिलाफ और नारी मुक्ति के पक्ष में नारे लगाए। हम पिछले काफी समय से जयपुर के विभिन्न इलाकों में मनुवाद के खिलाफ इस प्रदर्शन के लिए ही अभियान चला रहे थे।

जिन भी साथियों ने हमारे अभियान को लोगों तक ले जाने में हमारी मदद की उनका तहे दिल से धन्यवाद, आपको हमारी ओर से भीम लाल सलाम! आने वाले दिनों में RSS के मनुवादी/ब्राह्मणवादी फासीवाद के खिलाफ हमारी लड़ाई जारी रहेगी।

उत्तर प्रदेश

बलिया के सुल्तानपुर में आंबेडकर परिनिर्वाण दिवस और बाबरी मस्जिद विध्वंस पर "आरएसएस का हिंदुराष्ट्र और डॉक्टर आंबेडकर का सपना" विषय पर संगोष्ठी संपन्न

6 से 25 दिसंबर तक आरएसएस के वैचारिक आधार मनुवादी हिंदुत्व के खिलाफ जाति उन्मूलन आंदोलन और क्रांतिकारी सांस्कृतिक मंच के साझा अभियान का आगाज़

6 दिसंबर को जाति उन्मूलन आंदोलन और क्रांतिकारी सांस्कृतिक मंच द्वारा आरएसएस के वैचारिक आधार मनुवादी हिंदुत्व के खिलाफ अभियान की शुरुआत उत्तर प्रदेश के बलिया के सुल्तानपुर में "आरएसएस का हिंदुराष्ट्र और बाबासाहेब आंबेडकर का सपना" विषय पर संगोष्ठी का आयोजन किया गया। संगोष्ठी की अध्यक्षता अखिल भारतीय क्रांतिकारी महिला संगठन की राज्य संयोजिका कॉमरेड अंजू ने किया।

कार्यक्रम के मुख्य वक्ता क्रांतिकारी सांस्कृतिक मंच (कसम) के महासचिव और जाति उन्मूलन आंदोलन के केंद्रीय कमिटी सदस्य कॉमरेड तुहिन थे।संचालन युवा नेता कॉमरेड कन्हैया ने किया। वक्ताओं में कॉमरेड श्री राम चौधरी (सम्मानित अध्यक्ष अखिल भारतीय खेत मजदूर सभा व केंद्रीय कमिटी सदस्य, भाकपा माले लिबरेशन, कॉमरेड मुनि सिंह (अखिल भारतीय किसान सभा के जिला अध्यक्ष), कॉमरेड श्री राम भारती (भाकपा मनियर ब्लॉक सचिव), कॉमरेड श्री राम नारायण (जिला सचिव खेत मजदूर यूनियन), साथी गणेश तथा पत्रकार अमरनाथ यादव शामिल थे। कॉमरेड सुरेंद्र राम ने जन गीत प्रस्तुत किया। कार्यक्रम की शुरुआत में डॉक्टर आंबेडकर को श्रद्धांजलि देते हुए क्षेत्र के दिवंगत कम्युनिस्ट नेता कॉमरेड एस पी सुल्तानपुरी का भी स्मरण किया गया। कार्यक्रम में मनियर व सुल्तानपुर के जनवादी कार्यकर्ता, दलित/शोषित व महिला संगठनों के साथी बड़ी संख्या में उपस्थित थे।

वक्ताओं ने कहा कि 2014 के मध्य में मोदी सरकार के सत्ता में आने के बाद से, दुनिया का सबसे पुराना और सबसे बड़ा फासीवादी संगठन आरएसएस , भारत को एक हिंदूराष्ट्र के रूप में बदलने की दिशा में सुनियोजित ताबड़तोड़ आक्रमण में लगा हुआ है।

आरएसएस का वैचारिक आधार मनुस्मृति है जिसके अनुसार दलितों/उत्पीड़ितों और महिलाओं दोनों को इंसान नहीं समझा जाता।इसके अलावा इसके तथाकथित हिंदुराष्ट्र में जो कि अति अमीर अंबानी अदानी जैसे कॉरपोरेट घरानों के हित में बनाया जा रहा है, आरएसएस, मुसलमानों को नागरिकता और मानवाधिकारों से वंचित करती है।

इसीलिए जैसा कि बाबासाहेब आंबेडकर ने कहा था कि ब्राम्हणवाद और पूंजीवाद, भारतीय जनता के दो शत्रु हैं और एक सच्चे लोकतांत्रिक भारत बनाने के लिए जातियों का विनाश जरूरी है,के लिए आरएसएस के वैचारिक आधार मनुवादी हिंदुत्व को उखाड़ फेंकना जरूरी है। इसी संदर्भ में जाति उन्मूलन आंदोलन के साथ समान विचार वाले संगठनों ने 6 दिसंबर से 25 दिसंबर तक तीखे होते आरएसएस नवफासीवाद के खिलाफ देशव्यापी राजनीतिक अभियान शुरू करने का फैसला किया है. जाहिर है, दिसंबर 6, भगवा गुंडों द्वारा बाबरी मस्जिद के विध्वंस के साथ-साथ भारतीय संविधान के निर्माता अम्बेडकर की पुण्यतिथि का प्रतीक है, जबकि 25 दिसंबर वह दिन है जब अम्बेडकर ने आरएसएस फासीवाद के वैचारिक आधार मनुस्मृति को जलाया था। मुस्लिम-विरोधी, दलित-विरोधी, किसान, मजदूर, आम मेहनतकश जनता और पितृसत्तात्मक घोर महिला विरोधी संघी मनुवादी फासीवाद के खिलाफ हम मेहनतकश वर्ग, देशभक्त, जनवादी, धर्मनिरपेक्ष, प्रगतिशील अवाम और तमाम उत्पीड़ितों से अपील करते हैं कि आरएसएस के वैचारिक आधार मनुवादी हिंदुत्व के खिलाफ इस महत्वपूर्ण राजनैतिक अभियान को एक बड़े पैमाने पर सफल बनाएं..... शेष अगले पेज में.....

तमिलनाडु

25 दिसम्बर को मनुस्मृति दहन दिवस के अवसर पर तमिलनाडू के मदुरै में कामरेड विजय गोपाल एवं कॉमरेड श्रीधर ने आरएसएस के कॉर्पोरेट - मनुवादी - हिन्दुत्व फासीवाद के विरुद्ध जन विरोध कार्यक्रम आयोजित किया।

कर्नाटक

बाबासाहेब अंबेडकर द्वारा मनुस्मृति के दहन दिवस के अवसर पर 6 दिसम्बर से 25 दिसम्बर तक आरएसएस - बीजेपी के वैचारिक आधार मनुवादी हिन्दुत्व नव-फासीवाद के विरुद्ध देश भर में चलाए गए राजनैतिक अभियान के अवसर पर 25 दिसम्बर को रायचुर, कर्नाटक में एक जनसभा आयोजित किया गया। जिसमें पार्टी महासचिव पीजे जेम्स, पोलित ब्यूरो सदस्य कॉमरेड मनसैय्या, राज्य सचिव कॉमरेड रुद्रैय्या, एवं केन्द्रीय कंट्रोल कमीशन सदस्य अमीर अली एवं अन्य नेतृत्त्वकर्ता साथियों ने भाग लिया।

दिल्ली

दिल्ली के नरेला में मनुस्मृति दहन दिवस के अवसर पर एक जनसभा का आयोजन किया गया।

भाकपा माले रेड स्टार के पोलित ब्यूरो सदस्य के एन रामचंद्रन, कामरेड श्यामलाल जी, कामरेड निरंजन, कामरेड लेनिना, कामरेड हरपाल, अश्विनी, और शिशु रंजन ने अपनी बात जनता के बीच रखी और आरएसएस - बीजेपी के मनुवादी-ब्राह्मणवादी हिंदुत्व को उखाड़ फेंकने का आह्वान किया। युवा साथियों ने जनता के बीच जाति व्यवस्था के खिलाफ गीत भी गाया।

पंजाब

3 जनवरी को अकलिया मानसा, पंजाब में मजदूर अधिकार आन्दोलन और पार्टी के नेतृत्त्व में ग्रामीण मजदूरों ने सावित्री बाई फुले के जन्मदिवस को शिक्षक दिवस के रूप में मनाया और मनरेगा मजदूरों के समस्यायों पर सभा का आयोजन किया। सभा के कामरेड लाभ सिंह, केवल सिंह, हरप्रीत कौर और मंजीत कौर ने सम्भोदित किया।

कोझिकोड, केरल में, पार्टी कांग्रेस के रैली के कुछ दृश्य

पेज संख्या का शेष (उत्तर प्रदेश)

कॉरपोरेट घरानों के दलाल मेहनतकशों के दुश्मन आरएसएस नव फासीवाद के खिलाफ एकजुट हो- कॉमरेड शंकर 25 दिसंबर को बलिया जिले के मनियर सरवर के "ज्ञानसागर सरस्वती विद्यापीठ सरवार" में संघी मनुवादी फासिस्ट ताकतों के खिलाफ हल्ला बोल सभा संपन्न २५ दिसंबर को भाकपा (मा ले) रेड स्टार द्वारा संघी मनुवादी फासिस्टों पर हल्ला बोल सभा का आयोजन उत्तर प्रदेश के बलिया जिले के मनियर में मनुस्मृति दहन दिवस के ९५ वी वर्षगांठ के अवसर पर किया गया था।हल्ला बोल सभा के मुख वक्ता - कॉमरेड शंकर,पोलित ब्यूरो सदस्य, भाकपा (माले) रेड स्टार थे।अध्यक्षता कॉमरेड तुहिन,पोलित ब्यूरो सदस्य भाकपा (माले) रेड स्टार ने की।सभा का संचालन कॉमरेड अंजू(राज्य संयोजिका,अखिल भारतीय क्रांतिकारी महिला संगठन) ने की। स्वागत भाषण कॉमरेड कन्हैया,राज्य कार्यकारिणी सदस्य एवम जिला सचिव भाकपा(माले)रेड स्टार ,बलिया ने दिया।वक्ताओं में कॉमरेड श्रीराम चौधरी केंद्रीय कमिटी सदस्य भाकपा माले,कॉमरेड अमरजीत मानववंशी(संरक्षक,सामाजिक न्याय मोर्चा),कॉमरेड दिनेश राजभर (संयोजक,सामाजिक न्याय मोर्चा), कॉमरेड बलवंत(नेता,SKM), कॉमरेड अमरनाथ यादव (नेता भारतीय समाजवादी लोकतांत्रिक मंच),कॉमरेड सानमति एवम कॉमरेड हरेंद्र आजाद शामिल थे।कॉमरेड तुहिन ने क्रांतिकारी गीत प्रस्तुत किया।सभा में सर्वसम्मति से आजमगढ़ जिले के खिरियाबाग में कॉरपोरेट घरानों के हित में एयरपोर्ट के नाम पर ८ गांव के ४०००० लोगों को उजाड़ने के खिलाफ फासिस्ट योगी सरकार के दमनात्मक कदम का विरोध करते हुए संघर्ष रत किसानों के साथ एकजुटता कायम करने का प्रस्ताव पारित किया गया।कार्यक्रम में मेनियर क्षेत्र के जनवादी संगठनों और मेहनतकशों की उल्लेखनीय उपस्थिति रही।

भारतीय संविधान पर मनुवादी हमलों के खिलाफ एकजुट हो
जातिविहीन-वर्गविहीन समाज का निर्माण करो (अभनपुर, छत्तीसगढ़)

मनुस्मृति दहन दिवस के अवसर पर डॉ भीमराव अंबेडकर चौक भेलवाडीह अभनपुर में जाति उन्मूलन आंदोलन, मूलनिवासी मंच के बैनर तले 25 दिसम्बर को जनसभा का आयोजन किया गया। कार्यक्रम की मुख्य वक्ता अखिल भारतीय क्रांतिकारी किसान सभा के सचिव तेजराम विद्रोही रहे हेमंत टंडन ने संचालन किया और लखबीर सिंह ने आभार व्यक्त किया। सभा को पुनुराम देशलहरे, टिकेंद्र बघेल, उत्तम डीडी, रवि धृतलहरे, बोधन फ़रिकर, बिष्णु मिर्जे, राजू बारले आदि ने संबोधित किया सभा को सम्बोधित करते मुख्य वक्ता तेजराम विद्रोही ने कहा कि 25 दिसंबर 1927 को बाबासाहेब डॉ. भीमराव अम्बेडकर ने मनुस्मृति का दहन किया। ऐतिहासिक महाड़ सत्याग्रह के दौरान एक घटना में घोर जन विरोधी मनुस्मृति को जला दिया गया था। तालाब से पानी पीने का अधिकार पाने के लिए महारों द्वारा आयोजित यह एक उल्लेखनीय आंदोलन था। मनुस्मृति को जलाने से पहले डॉ अम्बेडकर ने अपने उद्बोधन में कहा था कि "आइए असमानता में पैदा हुए प्राचीन हिंदू शास्त्रों के अधिकार को नष्ट कर दें जो धर्म और दासता न्याय संगत नहीं हैं"। बाद में डॉ अम्बेडकर ने भारत की हिंदुत्व ताकतों (हिंदू महासभा, आर.एस.एस) की भी निंदा की जो भारत में हिंदू राज स्थापित करना चाहती थीं।

अम्बेडकर ने कहा कि हिंदू राज अवर्णों के लिए सबसे विनाशकारी होगा क्योंकि इसमें कोई स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व नहीं है और उन्हें अछूत माना जाएगा। उनका जीवन अमानवीय और क्रूर जाति व्यवस्था के खिलाफ संघर्ष था। मनुस्मृति को जलाने का कार्य (भले ही हम किताबों को जलाने का समर्थन न करें) भारत के लोगों को अपनी चेतना जगाने और जाति व्यवस्था को नष्ट करने का एक प्रतीकात्मक संदेश है। अब मनुस्मृति के विचार अभी भी भारतीय उपमहाद्वीप में सहस्राब्दी पुरानी प्रथाएं हैं जिसके कारण अस्पृश्यता, भेदभाव, शोषण आदि अभी भी प्रचलित हैं।

स्वतंत्रता संग्राम के समय से ही आरएसएस और अन्य सांप्रदायिक ताकतें बड़े पैमाने पर हिंदू राष्ट्र के अपने विचार को फैलाने की कोशिश कर रही हैं। बौद्ध धर्म, चार्वाक और मेहनतकश जनता आदि पर सनातनी ब्राह्मणवादी-मनुवादी ताकतों द्वारा किए गए हमलों पर पूरी चुप्पी के साथ भारत के इतिहास को स्वर्ण युग मानने वाले हिंदुत्व के विचार को प्रतिपादित करने वाले सावरकर ने मुसलमानों और ईसाइयों को बाहरी मानकर उन्होंने हिंदुओं और गैर-हिंदुओं के बीच नफरत फैलाई। गोलवलकर, हेगड़ेवार, मुंजे आदि ने ब्राह्मणवादी हिंदू राष्ट्र की इस दलित-विरोधी, महिला विरोधी, आदिवासी विरोधी, मुस्लिम-अल्पसंख्यक-विरोधी विचारधारा के विकास में योगदान दिया।

अब समय आ गया है जब जनता भाजपा-आरएसएस हिंदुत्व ताकतों के तीखे हमलों का सामना कर रही है। जिन्होंने भारत को हिंदू राष्ट्र बनाने के लिए राज्य की सत्ता तक पर कब्जा कर लिया है।

जैसा कि डॉ अंबेडकर ने हमें चेतावनी दी थी कि हिंदू राज शूद्रों और अति-शूद्रों के लिए विनाशकारी होगा, इन नफरत फैलाने वालों के खिलाफ लड़ना जरूरी है जो जातिगत आधिपत्य और धार्मिक भेदभाव को तेज करते हैं। इस तथाकथित हिंदुराष्ट्र में लोगों के बीच आपसी द्वेष, नफरत और विभाजन पैदा किया जाता है जिससे दलितों और अल्पसंख्यकों में असुरक्षा की भावना पैदा होती हो। राज्य सत्ता के समर्थन से आरएसएस ने भारत में सभी संवैधानिक और प्रशासनिक संस्थानों के भगवाकरण के अलावा सामाजिक जीवन के हर पहलू को अपने जाल में फंसाने (फासीवादीकरण) में सफलता हासिल की है । 2019 के मध्य से यानी मोदी के नेतृत्व में हिंदुत्व आक्रमण को एक अतिरिक्त गति मिली। दूसरी बार सत्ता में आने के तीन महीने के भीतर मोदी ने संविधान के अनुच्छेद 370 को निरस्त करने के साथ शुरू होने वाली फासीवादी चालों की एक श्रृंखला शुरू की जिससे एक ओर कश्मीर के टुकड़े हो गए और दूसरी ओर इसे जबरन भारतीय संघ में एकीकृत कर दिया गया। 103 वां संवैधानिक संशोधन, जिसे सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में समर्थन दिया है मोदी शासन ने जाति-आधारित आरक्षण को कमजोर कर दिया है जिसका उद्देश्य ब्राह्मणवादी ऊंची जातियों द्वारा अछूत और उत्पीड़ित जातियों के खिलाफ किए गए ऐतिहासिक अन्याय को सुधारना था।

इसी संदर्भ में जाति उन्मूलन आंदोलन के साथ समान विचार वाले संगठनों ने 6 दिसंबर से 25 दिसंबर तक तीखे होते आरएसएस नवफासीवाद के खिलाफ देशव्यापी राजनीतिक अभियान शुरू करने का फैसला किया है। जाहिर है दिसंबर 6 भगवा गुंडों द्वारा बाबरी मस्जिद के विध्वंस के साथ-साथ भारतीय संविधान के निर्माता अम्बेडकर की पुण्यतिथि का प्रतीक है जबकि 25 दिसंबर वह दिन है जब डॉ अम्बेडकर ने आरएसएस फासीवाद के वैचारिक आधार मनुस्मृति को जलाया था। मुस्लिम-विरोधी, दलित-विरोधी, किसान, मजदूर, आम मेहनतकश जनता और पितृसत्तात्मक घोर महिला विरोधी संघी मनुवादी फासीवाद के खिलाफ हम मेहनतकश वर्ग, देशभक्त, जनवादी, धर्मनिरपेक्ष , प्रगतिशील अवाम और तमाम उत्पीड़ितों से अपील करते हैं कि आरएसएस के वैचारिक आधार मनुवादी हिंदुत्व के खिलाफ इस महत्वपूर्ण राजनैतिक अभियान को एक बड़े पैमाने पर सफल बनाएं।

कार्यक्रम में उत्तम कुमार साहू, कोमल गिलहरे,भरत धृतलहरे, मनमोहन कुर्रे, हेमंत कुर्रे, पन्नालाल, उमेश, लोकेश, देवकुमार, त्रिवेंद्र, कालूराम, रामखिलावन, राजेश बारले, जगन्नाथ पटेल, रामरतन चौहान, करीम खान, धनऊ बारले, ललतुराम मंजीत, मंगल बारले, हरीश सिन्हा आदि उपस्थित रहे।

आरएसएस के खिलाफ़ देशव्यापी राजनीतिक अभियान के तहत 25 दिसम्बर को मुंबई में प्रदर्शन किया गया

छत्तीसगढ़ डायरी - सपन

छत्तीसगढ़ के आदिवासी बहुल क्षेत्र बस्तर में पिछले तीन माह से भी अधिक समय से फासिस्ट संघ परिवार का अल्पसंख्यक मसीही समाज के खिलाफ तांडव चल रहा है लेकिन भूपेश बघेल की कांग्रेस सरकार अपने नर्म हिंदुत्व के लाइन पर चलकर मूक दर्शक बने बैठी है।पिछले चुनाव के पहले, १५ साल से राज्य में काबिज भाजपा सरकार ,अपने मार्गदर्शक आरएसएस के निर्देशों पर आदिवासी से आदिवासी को लड़ाने का खूनी खेल खेलने के साथ साथ ,वनवासी कल्याण आश्रम सहित संघ परिवार के आनुषांगिक संगठनों की मदद से आदिवासियों के हिंदूकरण में जोर शोर से जुटी थी।२०१८ में जनता द्वारा फासिस्ट भाजपा का सूपड़ा साफ कर कांग्रेस को सत्ता सौंपा गया।लेकिन कांग्रेस भी कॉरपोरेट परस्त नीतियों और राम वनगमन पथ,कौशल्या मंदिर एवम गाय गोबर की राजनीति के जरिए संघ परिवार के वैचारिक आधार मनुवादी हिंदुत्व को खाद पानी दे रही है।

बस्तर में धुर दक्षिणपंथी फासिस्ट हिंदूवादियों की विशेष मुहिम की शुरुआत तब हुई जब गत वर्ष २६ अप्रैल को आरएसएस द्वारा निर्मित "जनजाति सुरक्षा मंच" की पहल से नारायणपुर जिले सहित कई स्थानों पर "रोको, टोको और ठोको" रैली व सभा का आयोजन कर ग्रामीणों को धर्मांतरित ईसाइयों के खिलाफ नफरती भाषण के जरिए भड़काया गया। उस दिन भाजपा नेता भोजराम नाग, रुपसाय सलाम,नारायण मरकाम आदि ने धर्मांतरित ईसाई आदिवासियों के खिलाफ डी लिस्टिंग करने ,उन्हे सरकारी सुविधाओं से वंचित करने और सामाजिक आर्थिक बहिष्कार करने की मांग की।तब से लगातार ईसाई अल्पसंख्यकों के खिलाफ लोगों को भड़काते हुए गत अक्टूबर से संघ परिवार हरकत में आया।बस्तर के कांकेर,कोंडागांव और नारायणपुर जिले के विभिन्न गांवों में तब से नफरत की आग सुलग रही है।मसीही समुदाय के पादरीगण तथा चर्च जाने वाले लोग जिनमें महिलाएं और बच्चे ज्यादा हैं को लगातार मारा पिता जा रहा है कि वे ईसाई धर्म छोड़कर हिंदू धर्म अपना लें नहीं तो गंभीर परिणाम होंगे।मसीही समुदाय का ग्रामों में सामाजिक आर्थिक बहिष्कार किया गया और उन्हें बलपूर्वक बिना घरेलू सामान के गांवों से बाहर खदेड़ दिया गया।

१८ दिसंबर से संघ परिवार द्वारा व्यापक हिंसा फैलाया गया।हिंसा के फलस्वरूप जो विश्वासी/ ईसाई लोग गांव से भाग कर फरसगांव (कोंडागांव) में शरण ले रहे थे, उनको प्रशासन द्वारा जबरन गांव वापस भेजा गया। उनमें से ग्राम चिंगनार के लोगों के साथ फिर मार पीट होने की खबर आई। रात को ही पुरुष लोग अपनी सुरक्षा के लिए गांव से निकल कर जंगल में छुप गए थे, पर दूसरे दिन सुबह महिलाओं के साथ बहुत बुरी तरह से मारपीट हुई है। उनका सामान भी बाहर निकाल कर फेंका गया है। पटवारी और सरपंच महिलाओं को प्राथमिक उपचार के लिए ले गए थे, और फिर वापस गांव में ही छोड़ दिया है। थाने में रिपोर्ट लिखवाने से भी मना कर रहे हैं। इनके साथ १८ दिसंबर से लगातार मारपीट हो रही है।सवाल ये है कि जब ये लोग खुद घर–बार छोड़ कर भाग के नारायणपुर/ फरसगांव आए हैं, इन्हे उसी भयावह माहौल में वापस क्यों धकेला जा रहा है? क्या प्रशासन की कोई जिम्मेदारी नहीं है कि पहले गांव में समझौता करवाए, माहौल को शांत बनाए, फिर ही इन्हें वापस भेजे और इनकी सुरक्षा की जिम्मेदारी ले? या फिर केवल अपनी जिम्मेदारी से हाथ धोना चाहती है?नारायणपुर में २० ग्रामों के ५०० ईसाई अल्पसंख्यकों ने शरण लिया है।पहले प्रशासन ने इन्हे खुली जगह रुकवा दिया था,विरोध करने पर नारायणपुर इंडोर स्टेडियम में इन्हें रुकवाया गया है।अपने गर्म कपड़ों,बिस्तर,कंबल,भोजन की व्यवस्था सब मसीही समाज स्वयं कर रहा है,प्रशासन ने अपनी जिम्मेदारी से पल्ला झाड़ लिया है।२५ दिसंबर को क्रिसमस के दिन बेनूर थाने के अंतर्गत ग्रामों में ईसाई समुदाय पर हमला हुआ।पिछले तीन माह में ५०० से अधिक नामजद शिकायतें आरएसएस/ भाजपा नेताओं के खिलाफ दर्ज की गई हैं लेकिन पुलिस प्रशासन मूक दर्शक बनी रही।

२ जनवरी को अल्पसंख्यक समुदाय के खिलाफ हिंसा परवान चढ़ी जब हथियारबंद संघी गिरोह ने नारायणपुर जिले के बंगलापारा के सैक्रेड हार्ट चर्च पर हमला कर दिया।मौके पर पहुंचे पुलिस अधीक्षक सदानंद सहित सात पुलिस कर्मी इस घटना में घायल हो गए। इस घटना के बाद पुलिस ने बाध्य होकर एक भाजपा नेता समेत ११ लोगों को गिरफ्तार किया है।मजे की बात है कि २ जनवरी को नारायणपुर जिले के भाजपा अध्यक्ष रूपसाय सलाम के नेतृत्व में नारायणपुर में ईसाइयों के खिलाफ भड़काऊ सभा का आयोजन किया गया।जिला कलेक्टर अजीत वसंत ने पत्रकारों से कहा कि रुपसाय सलाम और अन्य भाजपा नेता,रैली / सभा को शांतिपूर्ण बनाए रखने का वादा किए हैं।लेकिन करीब २००० लोग नारायणपुर में इकठ्ठे होकर विश्वपीठ स्कूल और सैक्रड हार्ट चर्च पर हमला कर उसे तहस नहस कर दिया।

जरूरत इस बात की है कि कांग्रेस फिर से एक बार धर्मनिरपेक्षता को समझे और हिंदुत्ववादियों के पिच पर खेलना छोड़ दे।कांग्रेस की सॉफ्ट हिंदुत्व की नीति से उसे तनिक भी लाभ नहीं होगा क्योंकि लाभ तो फासिस्ट संघ परिवार को जाना है। जो जल जंगल जमीन पर आदिवासियों के अधिकार को भटकाने और कॉरपोरेट घरानों की लूट को सुगम बनाने के लिए मनुवादी हिंदुत्व का जहर आदिवासी समाज के भीतर घोल रही है।कांग्रेस सरकार अगर जनता का दिल जीतना चाहती है तो उसे कांग्रेस के भीतर और पुलिस प्रशासन में छुपे और खुले मनुवादी हिंदुत्व के पैरोकारों को निबटाना पड़ेगा।लेकिन अपने वर्गचरित्र के चलते कांग्रेस,ये फासीवाद विरोधी पोजीशन नहीं लेगी।सर्व आदिवासी समाज और अन्य आदिवासी संगठनों को चाहिए कि वे आरएसएस के इस तथाकथित हिंदुराष्ट्र के अभियान को समझें,उससे दूरी बनाए और आदिवासी समाज में चेतना पैदा करें कि आदिवासी कभी हिंदू नहीं थे। आरएसएस के घोषित संविधान मनुस्मृति के अनुसार आदिवासी,दलित ,महिला आदि सब शुद्र हैं जिन्हे मानव का दर्जा नहीं प्राप्त है। जल, जंगल जमीन पर अधिकार,मूलभूत मानव अधिकार,जीने की आजादी के लिए आदिवासियों की लड़ाई को भटकाना आदिवासियों के दुश्मन,कॉरपोरेट घरानों के दलाल संघी मनुवादी फासिस्ट ताकतों की चाल है,धर्मांतरित ईसाई उनके अपने हैं।मूल लड़ाई कॉरपोरेट घरानों और उनके दलाल आरएसएस नवफसिवादियों से जनता की है।वामपंथी जनवादी संघर्षशील संगठनों को चाहिए कि वे पूरे देश और छत्तीसगढ़ में एक न्यूनतम कार्यक्रम के आधार पर व्यापक संघी फासीवाद विरोधी लड़ाकू मोर्चा का निर्माण करें अन्यथा कल बहुत देर हो जाएगी।